



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202]

No. 202]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 30, 2003/वैशाख 10, 1925

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 30, 2003/VAISAKHA 10, 1925

महानिदेशक का कार्यालय

(विनिर्दिष्ट सुरक्षा)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2003

विषय :—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ग के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (संक्रमणकालीन उत्पाद विनिर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क) नियमावली, 2002 (जिसे इसमें इसके बाद एस.एस.जी.डी. नियमावली कहा गया है) के नियम 5 के अधीन भारत में औद्योगिक सिलाई मशीन की सुईयों (आई.एस.एम.एन.) के आयातों के संबंध में रक्षोपाय शुल्क जांच-अंतिम जांच परिणाम।

सा.का.नि. 359(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और इसकी सीमाशुल्क टैरिफ (संक्रमणकालीन उत्पाद विनिर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क) नियमावली, 2002 के अधीन।

क. प्रक्रिया

भारत में आई.एस.एम.एन. के आयातों के संबंध में विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क जांच की शुरुआत का नोटिस दिनांक 13-08-2002 को जारी किया गया था और दिनांक 29-08-2002 को भारत के असाधारण राजपत्र में जारी किया गया था। आवेदन और एक प्रश्नावली की प्रति सहित नोटिस की एक प्रति दिनांक 23 सितम्बर, 2002 तक सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों के विचार जानने के लिए उन्हें भेजी गई थी, अर्थात् :—

घरेलू उत्पादक

- (i) आल्टेक लम्पर्टज नीडल्स लिमिटेड, तमिलनाडु।
- (ii) टी.वी.एस. नीडल्स लिमिटेड, तमिलनाडु।
- (iii) शेमेज (आई) प्रा. लि. मुम्बई।
- (iv) ग्राज-बेकर्ट एशिया लिमिटेड, चंडीगढ़।

निर्यातक

- (i) ग्रोस बेकर्ट ए.जी., जर्मनी ।
- (ii) फर्ड शेमेज जी.एमबीएच, जर्मनी ।
- (iii) आर्गन नीडल कं० लि०, जापान ।
- (iv) के. ओ. नीडल कं० लि०, जापान ।
- (v) गुआंगडांग सुंडेहुआनान सिर्विंग नीडल्स कं० लि०, चीन ।
- (vi) क्वीडांग सिर्विंग मशीन नीडल्स फैक्टरी, चीन ।
- (vii) हैमेन सिटी डांग चेंग नीडल्स फैक्टरी, चीन ।
- (viii) डोटेक नीडल्स कं० लि० ताइवान ।
- (ix) ट्रिम्फ नीडल कार्पोरेशन, चीनी ताइपेई ।

आयातक/प्रयोक्ता उद्योगः

- (i) ग्राज बेकर्ट एशिया प्रा० लि० चंडीगढ़ ।
- (ii) शेमेज इंडिया प्रा० लि०, मुम्बई ।
- (iii) मदुरा कोट्स लि०, बंगलौर ।
- (iv) आश्विनी इंटरकांटीनेन्टल, बंगलौर ।
- (v) एन. जुगराज एंड कं० चेन्नई *
- (vi) संजय ट्रेडिंग कंपनी, कलकत्ता ।
- (vii) कल्पना इंटरप्राइजेज, चेन्नई **
- (viii) सागर ओवरसीज, चेन्नई ।
- (ix) गोकुल दास इंडिया लि०, बंगलौर ।
- (x) ओरिएंट फैशन्स, नई दिल्ली ।
- (xi) दशमेश एम्ब्राइडरी, नई दिल्ली ।
- (xii) बाटा इंडिया लि०, पश्चिम बंगाल ।

* डाक प्राधिकारियों द्वारा वितरण किए बगैर वापस लौटाया ।

** उसी परिसर से प्रचालित मै० मनोज इंटरप्राइजेज द्वारा वापस लौटाया ।

एसोसिएशनः

इंडस्ट्रियल सिर्विंग मशीन डीलर्स एसोसिएशन, चेन्नई ।

2 आवेदन और प्रश्नावली के साथ जांच प्रारम्भ करने के नोटिस की एक प्रति निर्यातक देशों अर्थात् चीन जनवादी गणराज्य, जापान, जर्मनी, कोरिया जन गण, सिंगापुर और ताइवान की सरकारों को भी नई दिल्ली स्थित उनके उच्चायोगों/दूतावासों के जरिए भेजी गई थीं। जांच प्रारम्भ करने के नोटिस की प्रति भारत में यूरोपीय संघ, नई दिल्ली को भी भेजी गई थी।

3. दिनांक 13.08.2002 के नोटिस और प्रश्नावली के उत्तर निम्नलिखित पक्षकारों से प्राप्त हुए थे:-

घरेलू उत्पादक

- (i) आल्टेक लम्पर्टज नीडल्स लि०, तमिलनाडु।
- (ii) टी.वी.एस. सिर्विंग नीडल्स लि०, तमिलनाडु।
- (iii) शेमेज (आई) प्रा० लि०, मुम्बई।

निर्यातक

- (i) नानटोंग व्हाइट क्रेन नीडल्स कं० लि० और नानटोंग हुआटिंग नीडल्स मेकिंग कं० लि० चीन की ओर से और चीनी निर्यातकों की तथाकथित एक प्रतिनिधि एसोसिएशन चीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फार इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स (सीसीसीएमई) के अनुदेशानुसार काउंसल के जरिए उत्तर प्रस्तुत किए गए हैं।
- (ii) आर्गन नीडल कम्पनी लि०, जापान।
- (iii) के. ओ. नीडल्स कं० लि०, कोरिया गणराज्य।
- (iv) फर्ड शेमेज, जीएमबीएच, जर्मनी।

निम्नलिखित पक्षकार जो या तो प्रयोक्ता हैं अथवा आयातक द्वारा भी उत्तर प्रस्तुत किए गए हैं जिन्हें रिकार्ड में लिया गया है।

- (i) रोहन अपारेल्स प्रा० लि०, नई दिल्ली।
- (ii) शिवम् क्रिएशन, नई दिल्ली।
- (iii) साक्षी इंटरप्राइजिज, नोएडा, उ० प्र०।
- (iv) जे.बी. फैशन, नई दिल्ली।
- (v) जे.बी. इम्पेक्स प्रा० लि०, नई दिल्ली।
- (vi) दिलीप रेडीमेड्स, चेन्नई।

- (vii) विजय क्लाय कम्पनी, चेन्नई ।
- (viii) हनीफा लैदर मैनु. कं० चेन्नई ।
- (ix) राजेन्द्रा गार्मेन्ट्स, चेन्नई ।

4. जांच के लिए आवश्यक समझी गई सूचना का सत्यापन किया गया था और इस कार्य के लिए अधिकारियों के दल ने आवेदक घरेलू उत्पादक और मै० टी.वी.एस. सिविंग नीडल्स लि० मदुरै के परिसरों का दौरा किया । जांच के परिणाम से आवेदक, घरेलू उत्पादक को अवगत करा दिया गया था और सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में भी रखी गई थी ।

5. दिनांक 25 फरवरी, 2003 को सभी हितबद्ध पक्षकारों की सार्वजनिक सुनवाई की गई थी जिसकी सूचना दिनांक 28.01.2003 को भेजी गई थी । सार्वजनिक सुनवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों को उनके द्वारा दिए गए मौखिक तर्कों को दिनांक 6 मार्च, 2003 तक लिखित निवेदनों में प्रस्तुत करने और दूसरों द्वारा दिए गए उत्तरों की प्रतियां 7 मार्च, 2003 तक प्राप्त करने तथा खंडन यदि कोई हो तो 13 मार्च, 2003 तक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था । सार्वजनिक सुनवाई के दौरान महानिदेशक ने निर्यातकों और आयातकों के लिए इच्छा व्यक्त की कि पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए निर्यातों/आयातों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएं जिनके साथ संगत विवरण अर्थात् निर्यातक/आयातक का नाम, लदान बिलों की प्रतियां सहित निर्यात/आयात आई.एस.एम.एन की गुणवत्ता और मूल्य, माल सूची और प्रविष्टियों के बिल भी उनके अवलोकनार्थ साथ भेजे जाएं । आयातकों से उन कीमतों का अतिरिक्त ब्यौरा मांगा गया जिन पर माल का आयात किया जा रहा था और जिस कीमत पर वह अपने ग्राहकों को बिक्री कर रहे थे । इसके अतिरिक्त महानिदेशक ने चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स फार इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स (सीसीसीएमई) से भारत को उनके निर्यात के अधिप्रमाणित आंकड़ों के साथ-साथ सभी चीनी विनिर्माताओं के ब्यौरे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया ।

निम्नलिखित पक्षकारों ने सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया:-

- (i) आल्टेक लम्पर्टज नीडल्स लि०, तमिलनाडु ।
- (ii) शेमेज (i) प्रा० लि० मुम्बई (परामर्शदाता के जरिए) ।
- (iii) चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स फार इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स (सीसीसीएमई) ।
- (iv) विदेश व्यापार और आर्थिक सहयोग मंत्रालय (एमओएफटीईसी), चीन ।

- (v) चीन जनवादी गणराज्य का दूतावास, नई दिल्ली ।
- (vi) नानटोंग व्हाइट क्रैन नीडल्स कं० लि० चीन और नानटोंग हुआंटिंग नीडल्स मेकिंग कं० लि०, चीन (काउंसल के जरिए) ।
- (vii) दिलीप रेडीमेड्स, चेन्नई ।
- (viii) जे.जी. इम्पेक्स (प्रा.) लि०, नई दिल्ली ।
- (ix) प्लेजेंट ट्रेडिंग प्रा० लि०/इम्पेक्स सिंडिकेट, नई दिल्ली ।

ख. घरेलू उत्पादकों/घरेलू उद्योग के विचार

(i) टीवीएस सिविंग नीडल्स लिमिटेड, तमिलनाडु

वह सिलाई मशीन की सुईयों के मुख्य घरेलू उत्पादक हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 75 मिलियन सुईयां (घरेलू और औद्योगिक) हैं । उनकी आईएसएमएन बिक्रियां उनके उत्पादन से 1% कम हैं । उनकी बिक्री सकल बिक्री के % के रूप में इस प्रकार थी:-

विवरण	1999-00	2000-01	2001-02	मात्रा संख्या में
				2000-03 (अगस्त)
आईएसएमएन बिक्री	272100	248433	263350	24900
सकल बिक्री का %	0.46	0.52	0.62	0.22

(ii) शेमेज (आई) प्रा० लिमिटेड, मुम्बई

चीनी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग प्रति हजार नग 15 अमरीकी डालर है और उनकी क्षमता लगभग 500 मिलियन नग है । आल्टेक ने अधिक कीमत वाली सुईयों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध करते हुए पहले एक याचिका दायर की थी जिसे भारत सरकार द्वारा जांच के बाद खारिज कर दिया गया था । आल्टेक का दावा है कि वे आई एस एम एन का 95% घरेलू उत्पादन करते हैं जो भारतीय घरेलू खपत में बाजार का मात्र 2% हिस्सा है । सुई का वजन प्रति नग लगभग 2 ग्राम है कीमत सामान्यतः 1000 नग की एक इकाई के लिए उद्धृत की जाती है । आंकड़ों के रूप में मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ सुईयों जैसे उत्पादों के लिए वजन के आधार पर परिवर्तन करने पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि अलग-अलग प्रकार की

सुईयाँ, अलग-अलग उत्पादकों के लिए पैकिंग सामग्री में भी अन्तर होता है और इससे निष्कर्ष में अन्तर आ जाएगा ।

(iii) आल्टेक लम्मर्टज नीडल्स लि० (आल्टेक), चेन्नई ।

(क) ऐतिहासिक रूप से सुईयाँ अधिकांशतः जर्मनी, जापान और कोरिया में बनाई जाती थी । भारत ने सदैव इन देशों से सुइयों का आयात किया है । अमरीका और यूरोप में सिले हुए वस्त्र तैयार करना बहुत महंगा हो गया था और यह उद्योग एशियाई क्षेत्र में स्थानान्तरित हो गया । इसलिए सुइयों की मांग भी भारत जैसे एशियाई देशों को स्थानान्तरित हो गई । चीन ने संभावित बाजार के रूप में भारत पर ध्यान केन्द्रित किया और अपने उत्पाद की भारत में बाढ़ ला दी जिससे बाजार में पूरी तरह व्यवधान उत्पन्न होकर वह रास्ते से हट गया ।

(ख) उन्होंने जर्मन प्रौद्योगिकी से औद्योगिक सिलाई मशीन सुइयों का विनिर्माण करने के लिए संयंत्र स्थापित किया । कम्पनी ने वर्ष 1997 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया जिसकी स्थापित क्षमता 45 मिलियन सुईयाँ प्रति वर्ष थी । इस परियोजना का आई.सी.आई.सी.आई. द्वारा मूल्यांकन किया गया और 1200 लाख ₹ की कुल परियोजना लागत में 400 लाख ₹ की राशि का वित्तपोषण किया गया । शेष में से 48 लाख ₹ ई.सी.आई.पी. ऋण के रूप में शामिल किए गए और शेष धन राशि का वित्तपोषण इक्विटी के जरिए किया गया । आल्टेक ने प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक समावेश कर लिया और अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की औद्योगिक सिलाई मशीन सुइयों का उत्पादन शुरू कर दिया । परियोजना के मूल्यांकन के समय सुइयों का कुल मिलाकर जर्मनी, जापान और कोरिया से आयात किया जाता था । हालांकि चीन भी निर्यात कर रहा था लेकिन बाजार में इसका हिस्सा सिले हुए वस्त्र उद्योग के असंगठित भाग तक ही सीमित था । वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत के समय उनकी इकाई की क्षमता प्रतिवर्ष 25,714 कि.ग्राम अथवा 45 मिलियन सुईयाँ थी जो दो शिफ्टों के आधार पर बढ़कर प्रतिवर्ष 51,429 कि.ग्रा. अथवा 90 मिलियन हो गई थी । यह विस्तार मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से किया गया था ।

(i) चूंकि बुनियादी संरचना जैसे भूमि, बिजली पहले ही स्थापित थी इसलिए अतिरिक्त क्षमता स्थापित परिसम्पत्तियों में बहुत ही मामूली वृद्धि करके की जा सकती थी । भवन सहित विस्तार की लागत मात्र 452 लाख ₹ थी जबकि संयंत्र को स्थापित करने की प्रारम्भिक लागत 1585 लाख ₹ थी । इस प्रकार 100% से अधिक विस्तार इस अतिरिक्त पूंजीगत खर्च से किया जा सका ।

(ii) क्षमता में वृद्धि होने से प्रत्येक कि.ग्रा. उत्पादन के लिए नियत उपरि खर्च की लागत कम हो जाएगी।

(iii) अन्ततः आई.एस.एम.एन. के भारतीय बाजार की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इसकी मात्रा जो 1997-98 में 117,818 कि.ग्रा. थी, 2001-02 में बढ़कर 186,612 कि.ग्रा. हो गई।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन की घरेलू लागत इस प्रकार थी:-

वर्ष	लागत प्रति कि.ग्रा.
99-2000	6,296
2000-01	5,772
2001-02	3,991

(घ) चीन जनवादी गणराज्य ने भारत में अपने निर्यातों में निर्बाध रूप से नाटकीय ढंग से वृद्धि की जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है। निर्यात जो वर्ष 1997-98 में 53,545 कि.ग्रा. थे, बढ़कर वर्ष 98-99 में 85,818 कि.ग्रा. हो गए जिनमें 1998-99 की तुलना में 1999-2000 में मामूली गिरावट आई और चीन से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क, जिसे बाद में हटा लिया गया था, लगाए जाने के कारण पुनः गिरावट आकर 2000-01 में 29,270 कि.ग्रा. रह गए लेकिन 2001-02 में एकदम वृद्धि होकर 1,04,216 कि.ग्रा. हो गए। हालांकि अन्य देशों से आयात सामान्य रूप से 2000-01 में 67% से कम होकर 2001-02 में 42% रह गए थे परन्तु चीन से होने वाले निर्यातों में उसी अवधि के दौरान बाजार के हिस्से में 30% से 56% तक की अपूर्व वृद्धि हुई। पांच वर्ष की अवधि में वृद्धि की दर मिश्रित 15% से अधिक अथवा मात्रा के अनुसार लगभग दोगुनी है।

वर्ष	चीन		भारत		अन्य		जोड़
	मात्रा (कि.ग्रा.)	% हिस्सा	मात्रा (कि.ग्रा.)	% हिस्सा	मात्रा (कि.ग्रा.)	% हिस्सा	
1997-98	53,545	45%	1,348	1%	62,925	53%	117,818
1998-99	85,818	59%	1,621	1%	58,912	40%	146,351
99-2000	79,403	46%	3,549	2%	88,830	52%	171,782
2000-01	29,270	30%	2,836	3%	65,602	67%	97,708
2001-02	104,216	56%	4,631	2%	77,765	42%	186,612

(ड.) उनका हिस्सा चीन से निर्बाध आयातों द्वारा ही बाजार में व्यवधान होने के कारण प्रतिशत के अनुसार स्थिर हो गया है। सुनिश्चित तौर से भी उनकी बिक्री में घरेलू खपत में हुई अनुरूप वृद्धि नहीं हुई थी। उनका बाजार का हिस्सा जो 2000-01 में 3 प्रतिशत था 2001-02 में घटकर 2 प्रतिशत रह गया था जिसमें 33 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। उन्होंने अपनी क्षमता में 1997 में 25,714 कि.ग्रा. से वृद्धि करके वर्ष 2000 में दो सिफ्टों के आधार पर वृद्धि करके 51,429 कि.ग्रा. का उत्पादन किया ताकि बढ़ती हुई भारतीय मांग को पूरा किया जा सके और आयातों की तुलना में लागत में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए अर्धपरिष्कृत सुईयों का निर्यात किया जा सके। परन्तु पूरी समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारतीय बाजार के लिए उत्पादन चीन से अत्यधिक आयातों के कारण 4000-6000 कि.ग्रा. के बीच स्थिर रहा।

(च) अत्यधिक आयातों के कारण कम क्षमता के उपयोग की वजह से कंपनी प्रचालनों में दक्षता प्राप्त नहीं कर सकी, संयंत्र का इष्टतम प्रयोग नहीं कर सकी। अधिक मात्राओं के जरिए उत्पादन की लागत कम नहीं कर सकी जिसके परिणामस्वरूप उनके मुख्य प्रशिक्षित कार्मिक बेहतर अवसरों के लिए रोजगार छोड़कर चले गए।

(छ) उनका भारतीय बाजार के लिए क्षमता उपयोग 98-99 में 14 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2001-2002 के दौरान केवल 10 प्रतिशत रह गया था। कुल क्षमता उपयोग (निर्यातों सहित) 98-99 में 57 प्रतिशत से घटकर 2001-2002 में 45 प्रतिशत रह गया था।

(ज) उनको अत्यधिक वित्तीय घाटा हुआ और अब वे चीनी आयातों द्वारा बाजार में उत्पन्न किए गए व्यवधान के कारण बी आई एफ आर अधिनियम के अन्तर्गत एक संभावित रूग्ण कंपनी है। कम की गई कीमतों पर चीन से आयातों में हुई वृद्धि के अतिरिक्त चीन की निर्यातक ऋण सुविधाएं और पर्याप्त मात्रात्मक/नकद लाभांश भी दे रहे हैं जिनसे उन्हें अपनी कीमतों को कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है और उनकी वसूली प्रभावित हुई है। उदाहरण के लिए डी.बी. * 1 प्रणाली की कीमत सबसे अधिक बिकने वाली सुईयां-जनवरी 2002 में 2.95 ₹0 (कर सहित) प्रति सूई से कम होकर 2.50 ₹0 रह गई। इसके अतिरिक्त पूरे देश में 4-5% बिक्री कर में हुई वृद्धि को कम्पनी द्वारा समायोजित कर लिया गया है। आई.सी.आई.सी.आई जिन्होंने उनकी परियोजना का मूल्यांकन किया था और उन्हें ऋण दिया था, ने अनुमान लगाया है कि उस समय व्याप्त स्थिति के आधार पर भारतीय बाजार के लिए वसूली 7000 ₹0 प्रति कि.ग्रा. होगी। परन्तु मूल्य ह्रास और चीन से आयातों की मात्रा में वृद्धि होने के कारण

वसूली 2750 रु० प्रति कि.ग्रा से अधिक नहीं हुई है। यदि निवेदित रक्षोपाय शुल्क लगा दिया जाए तो वे चीनी सुईयों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी कीमतों में मामूली कमी कर सकेंगे जिसकी पूर्ति वे क्षमता उपयोग बढ़ाकर कर सकते हैं जो इस समय कम है। उनकी नकदी प्रवाह की स्थिति प्रभावित हुई जिससे भारी स्टॉक (10 से 12 महीने की बिक्री) हुआ, काफी देनदारी रही (5 से 7 महीने) जिसके फलस्वरूप अलाभकारी प्रचालन हुए और कम प्राप्ति हुई।

(झ) चीनी से सुईयों के आयात की लागत जो 1999-2000 में 671 रु० प्रति कि.ग्रा थी, कम होकर 2000-01 में 649 रु० रह गई और चीन को छोड़कर अन्य देशों की आयात कीमत (सी.आई.एफ) की तुलना में 2001-02 में मामूली बढ़कर 669 रु० हुई जो 1999-2000 में 1026 रु० से बढ़कर 2001-02 में 1732 रु० हो गई थी, जिससे चीन के निर्बाध आयातों द्वारा बाजार में उत्पन्न व्यवधान प्रतिबिंबित होता है। हालांकि चीन के साथ-साथ अन्य देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई परन्तु चीन की कीमत (सी.आई.एफ) में तदनुसूची वृद्धि नहीं हुई जो निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाएगी:-

प्रति कि.ग्रा.सीआईएफ कीमत रूप्यों में

वर्ष	चीन से आयात- मात्रा	चीनी से आयातों की लागत	अन्य देशों से आयात-मात्रा	आयातों की लागत-अन्य
1997-98	53,545	446	62,925	864
1998-99	85,818	508	58,912	1,267
1999-2000	79,403	671	88,830	1,026
2000-01	29,270	649	65,602	1,349
2001-02	104,216	669	77,765	1,732

(ट) यह स्पष्ट है कि बाजार में उत्पन्न व्यवधान का प्रत्यक्ष कारण चीन से सुईयों के आयातों में हुई वृद्धि है। क्षति सामान्य तौर से आयातों में हुई वृद्धि से हुई है परन्तु चीन से हुए आयातों से इसमें बहुत अधिक इजाफा हो गया था। चीन के निर्यातकों द्वारा लामांश और ऋणों में वृद्धि के कारण वे अधिक लामांश और कमीशन देने के लिए बाध्य हुए ताकि ग्राहक आधार बनाए रख सकें और अपने विनिर्माण प्रचालन जारी रख सकें जिसका उनकी वित्तीय स्थिति पर अपना प्रभाव था।

(ठ) उनके द्वारा किए गए आबद्ध निवेश के कारण वे यूनिट को न तो बंद कर सकें और न ही उत्पादन में कमी कर सकें तथा उन्हें अर्ध-परिष्कृत सुईयों का निर्यात करके अलाभकारी स्तरों पर यूनिट को चलाने के लिए बाध्य होना पड़ा ।

(ड) एक अन्तरिम रक्षोपाय शुल्क (अनन्तिम) के अतिरिक्त चार वर्ष के लिए चीन से आयातों पर आई.एस.एम.एन पर विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क लगाया जाए जो लोक हित में होगा और जिसके फलस्वरूप उनकी कम्पनी, जर्मनी, जापान आदि के मूल से गुणतायुक्त सुईयों के लिए घरेलू बाजार खुलेगा जिससे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त होगा ।

(ढ) आल्टेक ने अपनी कीमतों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक पुनर्संरचना योजना की परिकल्पना की । योजना के हिस्से के रूप में इसने कम लागत का ई.सी.बी. ऋण लिया और भारतीय वित्तीय संस्थान के साथ अपनी सभी आवधिक देयताएं समाप्त कर दी जिनकी लागत तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक थी । ई.सी.बी. ऋण का हिस्सा अप्रयुक्त रह गया जो अक्रियान्वित विस्तार कार्यक्रम के लिए है ।

(ण) इस समय वे सूई की तार जो मुख्य कच्ची सामग्री है, का जर्मनी से निर्यात कर रहे हैं । सूई की तार एक उच्च कार्बन स्टील की तार है जिसमें 1% कार्बन होती है । विश्व में केवल 4-5 विनिर्माता ही सूई की इस तार की समस्त सूई उद्योग को आपूर्ति करते हैं । विनिमय दर, सीमाशुल्क, भाड़ा, आयातों में पहुंच समय के कारण माल सूची के अधिक स्तर के कारण तार की लागत अधिक होती है । उन्होंने भारत में इस सूई की तार के स्रोत की संभावना का पहले ही अध्ययन कर लिया है । इस दिशा में उन्होंने सूई की तार के विनिर्माण के लिए मै0 गुजरात वायर इंडस्ट्रीज के साथ प्रबंध किया है । उनके दिशा-निर्देश और विशेषज्ञता से यह कम्पनी उत्तम गुणता की सूई की तार का उत्पादन करने में सफल रही है । निसंदेह उनका उत्पादन बहुत कम था । इसके अतिरिक्त सूई की प्रणाली और आकार के अनुसार विभिन्न मोटाई के तारों की आवश्यकता होती है । सूई के तार की मोटाई 1.63 मि.मी. से 2.02 मि.मी. तक होती है । यह कम्पनी केवल एक विशेष प्रणाली के लिए सूई की तार का उत्पादन करने में सफल रही है । तार की ड्राइंग जो सूई की तार के विनिर्माण में मूल प्रक्रिया है, एक अत्यधिक सूक्ष्म इंजीनियरी है क्योंकि गुणता की विनिर्दिष्टताएं अत्यन्त कठोर हैं । तार की गुणवत्ता अवश्य स्थिर होनी चाहिए विशेषतः जब मात्रा में वृद्धि हो जाए और वे विभिन्न व्यासों के तार का उत्पादन करने की स्थिति में हों । यूनिट को किसी न्यूनतम निकासी का आश्वासन भी दिया जाना चाहिए ताकि वे अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने संयंत्र में निवेश कर सकें । यह उम्मीद है कि लगभग तीन वर्ष में यह यूनिट

आल्टेक की लगभग 40% आवश्यकता की आपूर्ति करने की स्थिति में होगी । हालांकि इस यूनिट से आल्टेक की समस्त आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा सकती लेकिन इस 40% घरेलू स्रोत से उनकी कच्ची सामग्री की लागत काफी कम हो जाएगी ।

(त) डाइयां बहुत नाजुक होती हैं और आई एस एम एन के विनिर्माण के लिए आवश्यक औजार है । डाइयां पेटेंट की हुई प्रौद्योगिकी का हिस्सा होती हैं और उनको गुप्त रखने के लिए कड़ी सुरक्षा की जाती है । आल्टेक ने अपना औजार कक्ष स्थापित किया है तथा व्यापक अध्ययन किया है तथा डाइयां बनाने में परीक्षण किए हैं । कम्पनी के इंजीनियरों ने जर्मनी में व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं । इन सभी प्रयासों से वे डाइयों का पहला सैट बनाने में कामयाब रहे हैं । चूंकि सूईयों की प्रणालियों और आकार की व्यापक श्रृंखला है इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रणालियों/आकारों के संबंध में प्रयास किए हैं । बनाई जाने वाली डाइयों की व्यापक श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए उम्मीद है कि आल्टेक लगभग पांच वर्ष में स्वयं पूरी डाइयां बना लेगा ।

(थ) मिलिंग कटर एक अन्य नाजुक औजार है जिसका वे जर्मनी से आयात करते हैं। यद्यपि अन्तिम उत्पाद में मिलिंग कटर की लागत बहुत कम है परन्तु अधिक आयात लागत, भंडारण लागत से पर्याप्त वृद्धि हो जाती है । आल्टेक ने कटर बनाने की कला का व्यापक अध्ययन किया है जो सफल रहा है । आयातित मिलिंग कटर की लागत प्रति नग 300 रु० आती है जबकि एक घरेलू नग पर लगभग केवल 160 रु० की लागत आएगी ।

(द) स्टेबलाइजर एक रसायन है जो डेबेरिंग प्रचालन में प्रयुक्त होता है और सूई के तल को चिकना बनाता है और खुदरापन समाप्त करता है । एक जर्मनी कम्पनी के पास इस रसायन का मालिकाना हक है जो समस्त सूई उद्योग को आपूर्ति करती है । आल्टेक ने भारत सरकार के केन्द्रीय विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान से संपर्क किया और इस रसायन का घरेलू उत्पादन करने में उनकी मदद मांगी । आल्टेक ने इस एजेंसी के साथ एक करार किया है और परीक्षण किए जा रहे हैं । आल्टेक द्वारा प्रयुक्त इस रसायन की लागत घरेलू तौर पर उत्पादन करने पर पर्याप्त रूप से कम हो जाएगी ।

(ध) आल्टेक ने अपनी घरेलू बिक्रियां बढ़ाने के लिए बिक्री संवर्धन और विज्ञापनों पर बहुत धन राशि खर्च की है । इससे आल्टेक को घरेलू बाजार में एक विशेष छवि उत्पन्न करने में मदद मिली है । गुणता के अनुसार आल्टेक की सूईयों को जर्मनी, जापान और

कोरिया की सुईयों के बराबर समझा जाता है। इस प्रारम्भिक विशिष्ट छवि और घरेलू बिक्री में वृद्धि से आल्टेक के बिक्री खर्च काफी कम हो जाएंगे।

(न) वित्तीय पुनःसंरचना के भाग के रूप में आल्टेक ने वित्तीय संस्थानों की आवधिक देयताओं का पहले ही वापसी भुगतान कर दिया है जिनकी लागत 16% से 18% थी। इसका वापसी भुगतान आल्टेक द्वारा लिए गए ई.सी.बी. ऋण से किया गया है जिसकी लागत केवल 6.50% है। इस ऋण के वापसी भुगतान की सरल समय तालिका है जो 8 वर्ष की है। अन्य नियत उपरि खर्च जैसे कार्मिक लागतें, बिजली, उपभोग्य पदार्थ तथा अन्य उपरि खर्चों में उत्पादन में वृद्धि से बहुत ही कम बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है। अन्य शब्दों में सुईयों की लागत में नियत लागत घटक में पर्याप्त कमी होगी।

(प) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति बिक्रियां, नियत परिसम्पत्तियों पर नियोजित पूंजी और घाटे इस प्रकार थे:-

(Rs. Lakhs)

वर्ष	कर्म- चारियों की संख्या	नियोजित पूंजी		बिक्रियां		घाटे	
		राशि	प्रति कर्मचारी	राशि	प्रति कर्मचारी	राशि	प्रति कर्मचारी
1999- 2000	137	15,83.04	11.55	3,38.21	2.46	1,38.76	1.01
2000- 2001	161	19,65.51	14.34	6,32.11	4.61	2,22.78	1.62
2001- 2002	119	21,03.05	15.35	7,51.05	5.48	77.79	0.56

(फ) उन्होंने वर्ष 2000 में अपनी क्षमता 25,714 कि.ग्रा. से 51,428 कि.ग्रा. बढ़ाई और उनकी वर्तमान क्षमता दो शिफ्टों के आधार पर 51,428 कि.ग्रा. है। मौजूदा स्थापित मशीनों की क्षमता बढ़ाने में लगभग 15 लाख रु० का अतिरिक्त निवेश करके क्षमता बढ़कर 150 मिलियन अथवा 85,714 कि.ग्रा. हो जाएगी। आल्टेक ने अपने विस्तार कार्यक्रम के लिए पेटेंट शुदा मशीनों की आपूर्ति (जिनकी आपूर्ति केवल सहयोगियों द्वारा की जा सकती है) के लिए अपने सहयोगियों के साथ ठेके किए हैं जिनमें से केवल एक हिस्सा ही प्राप्त हुआ है और स्थापित किया गया है। शेष मशीनें बहुत कम अवधि में प्राप्त की जा सकती हैं। आल्टेक के संयंत्र की क्षमता लगभग 250 मिलियन या 1,42,857 कि.ग्रा. तक एक साथ बढ़ाई जा सकती है। विस्तार कार्यक्रम

के अन्तर्गत शेष मशीनों की लागत अनुमानतः लगभग 150 लाख रु० है । आल्टेक ने बहुत कम दर पर ई.सी.बी. ऋण लेकर अपनी आवधिक ऋण देयताओं की पुनःसंरचना की है जिसमें से भारतीय वित्तीय संस्थानों के अधिक लागत वाले आवधिक ऋण को समाप्त कर दिया गया है । अप्रयुक्त ई.सी.बी. ऋण शेष मशीनों की लागत पूरी करने के लिए पर्याप्त होगा ।

(ब) विनिर्मित सूईयों की सभी प्रणालियों और आकारों के उत्पादन की लागत लगभग एक समान है । विनिर्माण की प्रक्रिया भी सभी प्रणालियों के लिए समान ही है केवल उन कुछ प्रणालियों को छोड़कर जिनमें अतिरिक्त प्रचालनों की आवश्यकता होती है जैसे दोनों ओर खांचा बनाना, कुछ प्रणालियों के लिए प्रयुक्त मोटी तार के चलने में पतली तार वाली प्रणाली की अपेक्षा अधिक समय लगता है । तथापि, इन घटकों पर लागत में बहुत कम अन्तर है । मुख्य अन्तर बैच आकार के कारण होगा क्योंकि कुछ लागतें प्रत्येक बैच के लिए नियत होती है चाहे उनकी प्रणाली और आकार कुछ भी हो । तथापि, बिक्री कीमत प्रणाली के अनुसार अलग-अलग होती है । सूईयों की मूल किस्म अर्थात् डी.बी. * 1 और डी.पी. * 5 को 'रोटी और मक्खन' समझा जाता है जो विश्व में अधिकांश प्रतिस्पर्धी पक्षकारों द्वारा बनाई जाती है । तथापि, विशिष्ट प्रकार की सूईयां जिनकी मांग अधिक नहीं है, की आपूर्ति सामान्यतः विनिर्माताओं द्वारा की जाती है । ऐसी सूईयों की 100 से अधिक किस्में हैं और किसी भी कम्पनी के लिए सभी किस्म की सूईयां बनाना संभव नहीं है । पुनरपि यह मांग की कम मात्रा की वजह से प्रचालन कारणोंवश उचित है और इसका कारण यह नहीं है कि कम्पनियों के पास ऐसी सूईयां बनाने का ज्ञान अथवा सुविधा नहीं है ।

(म) आल्टेक ने औद्योगिक सिलाई मशीन की सूईयों का संयंत्र स्थापित करने वाली भारत में प्रथम यूनिट होने के कारण, अपने कर्मचारियों को भारत और जर्मनी में भी प्रशिक्षण देने के लिए बहुत खर्च किया । 25 कर्मचारियों तक को प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजा गया है और उनमें से कुछ को प्रौद्योगिकी ग्रहण करने तथा प्रशिक्षण के लिए एक से अधिक बार भेजा गया है ।

(म) आल्टेक जर्मनी में अपने सहयोगी से औद्योगिक सिलाई मशीन सूईयों की कुछ प्रणालियों का आयात करता है । प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं और अनुप्रयोगों के अनुसार औद्योगिक सिलाई मशीनों की सूईयों की प्रणालियों और आकारों की 1500 से अधिक किस्में हैं । घरेलू बाजार में कुछ किस्म की सूईयों की बहुत कम मांग है । कम मांग के कारण ऐसी प्रणालियों और आकारों का विनिर्माण करना कार्यक्षम नहीं होगा । ऐसी प्रणालियों का अधिकांशतः ग्राहक सेवा नीति के रूप में आल्टेक द्वारा निर्यात किया

जाता है। सूईयों की विभिन्न प्रणालियों के लिए विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को आर्डर देना सूईयों के किसी क्रेता के लिए कठिन होगा। अतः पूर्णतः एक ग्राहक सेवा के रूप में वे इन सूईयों का आयात करते हैं। आयातित सूईयों की बिक्रियां सामान्यतः इसके अपने घरेलू उत्पादन के साथ-साथ अपने वितरण और विपणन माध्यम के जरिए लगभग लागत दर लागत के आधार पर की जाती है। चूंकि आल्टेक के उत्पादन की तुलना में आयातित औद्योगिक सिलाई मशीन की सूईयां अलग प्रणालियों और आकारों की हैं इसलिए आयातित सूईयों और आल्टेक की सूईयों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है।

उपर्युक्त के अलावा उन्होंने निम्नलिखित विवरण भी दिया है:-

(क) दो निर्यातकों अर्थात् हुआटिंग और व्हाइट क्रेन के लिखित निवेदनों को इस आधार पर स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए कि उक्त दोनों निर्यातकों ने अपने प्रस्तुत उत्तर में अपनी सही पहचान नहीं बताई थी। निर्यातकों ने महानिदेशक को गुमराह करने के लिए अपनी वास्तविक पहचान को छुपाया है, निर्यातकों ने उनको भेजी गई प्रश्नावलियों के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए थे जिसके फलस्वरूप (आल्टेक) इन दोनों निर्यातकों के स्तर पर आशंका करने की स्थिति में नहीं थे जो चीन से भारत को आई.एस.एम.एन. के मुख्य निर्यातक बताए गए हैं। प्रश्नावली में अन्य बातों के साथ-साथ (i) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उनके द्वारा भारत में किए गए निर्यातों की मात्रा और मूल्य और (ii) भारत में उन डीलरों/एजेंटों के नाम और पते, जिनके माध्यम से उन्होंने निर्यात किया था, मांगे गए थे।

(ख) इस बात का सुझाव देने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य हैं कि हुआटिंग/व्हाइट क्रेन ने भारत को 1 अमरीकी डालर प्रति 1000 सूईयों पर आई.एस.एम.एन. की माल सूची भेजी। उनके द्वारा यथापरिकलित भाड़ा और पैकेजिंग की लागत प्रति सूई 5 पैसे है जिससे मालूम होगा कि चीनी निर्यातकों द्वारा आई.एस.एम.एन. की मुफ्त आपूर्ति की जा रही थी। विश्व में ऐसी कोई वाणिज्यिक सत्ता ऐसे कार्य नहीं करेगी। इसलिए एक ऐसा अपवित्र गठबंधन काम कर रहा है जो एक शैतानी योजना चला रहा है। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक के अलावा कुछ और है और मुक्त व्यापार के नाम पर भारतीय गणतंत्र की जड़ों पर प्रहार कर सकता है।

(ग) पिछले कुछ वर्ष पहले की गई पाटनरोधी जांच के दौरान विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने विस्तृत जांच के बाद 1.98 रू० प्रति सूई के पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी जो वर्तमान कीमत का 4000% परिकलित होती है। किसी भी पाटनरोधी जांच में विश्व के किसी भी भाग में इतने अधिक प्रतिशत की कोई जानकारी नहीं है। इस निर्णय को

चीनी सुई विनिर्माताओं द्वारा स्वीकार किया गया था। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इससे एक बहुत बड़े झूठ का खुलासा होता है कि चीनी उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी है। इसलिए ऐसी कीमत की पेशकश कर सकता है जो वास्तविक नहीं है। इससे साबित होता है कि चीनी कीमतों का न तो वास्तविकता से कोई संबंध है और न ही वे वाणिज्यिक स्वरूप की हैं। चीनी चैम्बर और चीन के विदेश व्यापार मंत्रालय ने इस मामले में असाधारण रूचि दिखाई है हालांकि आई.एस.एम.एन. भारत के साथ चीन के सकल व्यापार का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है।

(घ) दिनांक 25 फरवरी, 2003 को सार्वजनिक सुनवाई के दौरान महानिदेशक ने यह कहा कि 'ओरिएन्ट' ब्रांड नाम के आई.एस.एम.एन. का सीमाशुल्क के रिकार्ड के अनुसार आयात किया गया है और यह जानना चाहा कि निर्यातक का नाम क्या है। हुआटिंग/व्हाइटक्रैन के पास कोई उत्तर नहीं है परन्तु जांच करने के उपरान्त बताने का वायदा किया। इस बात का दावा करने वाले कुछ दस्तावेज कि आई.एस.एम.एन. के 'ओरिएन्ट' ब्रांड का विनिर्माण हुआटिंग द्वारा किया गया था, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे और उन्होंने इसका भारत में संजय ट्रेडिंग कं० कलकत्ता को निर्यात किया था। वे महसूस करते हैं कि प्रस्तुत की गई वाणिज्यिक माल सूची जाली दस्तावेज है क्योंकि इसमें परेषक/परेषिति का भी पता नहीं है।

(ङ) वे आई एस एम एन के एकमात्र उत्पादक हैं और घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं। शेमेज (इंडिया) बहुत ही सीमित किस्म की सुईयां बनाते हैं और शेमेज, जर्मनी के लिए एकमात्र विनिर्माता हैं तथा अपनी सभी सुईयों का थोक में तथा बिना पैक किए हुए निर्यात करते हैं जो बिक्री के लिए तैयार नहीं होती हैं। टी.वी.एस. नीडल्स ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि वे आई एस एम एन का कतई निर्माण नहीं करते हैं। इसलिए वे एकमात्र घरेलू विनिर्माता हैं।

(च) आवेदन में प्रस्तुत उनके आयात आंकड़े जो उन्होंने डीजीसीआईएंडएस कलकत्ता से प्राप्त किए थे, को चुनौती देते हुए चीनियों ने इस तथ्य के बावजूद सरकारी चीनी सरकार के अपने आंकड़ों को जान-बूझकर उद्धृत नहीं किया कि चीन चैम्बर और विदेश व्यापार मंत्रालय, चीन कार्यवाहियों में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। चीन प्रत्यक्षतः व्यापार आंकड़े रखता है और उन्होंने निर्यातकों को चयन करके उद्धृत किया है। परन्तु आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। इसकी तुलना में भारत, जर्मनी, जापान और कोरिया आदि इन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित करते हैं और ये वेबसाइट में उपलब्ध हैं।

(छ) निर्यातकों की ओर से यह कहा गया था कि भारत में सूई उद्योग को किसी परिणाम पर पहुंचने के लिए एक समग्र उद्योग समझा जाना चाहिए न कि आई एस एम एन को अलग। इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि भारत के सूई उद्योग में हाउसहोल्ड, आई एस एम एन, निटिंग मशीन, हैंड सिविंग मशीन नीडल्स और सर्जिकल सूईयां शामिल हैं। यह अवश्य माना जाना चाहिए कि घरेलू सिलाई मशीन की सूईयां और औद्योगिक सिलाई मशीन की सूईयां दो अलग-अलग उत्पाद हैं। किसी एक को दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए इन दोनों विभिन्न सूईयों को उसी प्रकार अलग समझा जाना चाहिए, अन्य सभी प्रकार की सूईयां (हाथ की सिलाई, बुनाई, शल्य चिकित्सा) को अलग-अलग उत्पाद समझा जाना चाहिए। राजस्व विभाग की कर अनुसंधान यूनिट (टी.आर.यू.) ने यह अनुदेश जारी किए हैं कि टैरिफ की सुमेलिकृत प्रणाली के स्थान पर आठ-अंकीय अन्तर्राष्ट्रीय कोड रखा जाना चाहिए। इस प्रथा का आयातकों द्वारा पहले ही अनुसरण किया जा रहा है।

(ज) हुआटिंग/व्हाइट क्रेन की ओर से यह दावा करना असंगत है कि टी.वी.एस का घरेलू सूईयों के लिए बहुत कम उत्पादन आधार है। टी.वी.एस. प्रतिवर्ष 50 मिलियन से अधिक सूईयों की बिक्री करता है और पिछले तीन दशकों से भारत की अधिकांश मांग को पूरा कर रहा है। अतः टी.वी.एस. पिछले तीन दशकों से अधिकांश घरेलू मांग पूरी करता है तथा चीनी आयात न्यूनतम हैं।

(झ) चीन चैम्बर को श्रेणी-वार और देश-वार आयातों और निर्यातों के संबंध में चीन सरकार के सरकारी आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए थे जिन्हें चीन निसन्देह किसी अन्य देश की तरह रखता है। चीन चैम्बर ने कहा है कि सूई एक "नगण्य वस्तु है" और भारत तथा चीन के बीच परस्पर व्यापार को इस तुच्छ वस्तु द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। वस्तुतः भारत सरकार को आई एस एम एन घरेलू विनिर्माता का मामला नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह एक "नगण्य वस्तु है", वे यह जानना चाहेंगे कि चीन चैम्बर और चीन सरकार इस मामले में इतनी अधिक रूचि क्यों ले रहे हैं। चीन चैम्बर का दावा है कि आई एस एम एन विनिर्माता चैम्बर के सदस्य हैं। परन्तु चीन चैम्बर को चीन में आई एस एम एन के विनिर्माताओं की संख्या भी मालूम नहीं है।

() सार्वजनिक सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक निवेदनों में कुछ आयातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों से यह मालूम होता है कि उन्होंने "आल्टेक" और चीनी निर्यातकों तथा चीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच हुए कुछ तथाकथित विचार-विमर्श सहित निर्यातकों और चीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रस्तुत निवेदनों को पुनः प्रस्तुत किया है। आयातकों ने अपने लिखित निवेदनों में वे बातें भी शामिल की हैं जो उन्होंने महानिदेशक के समक्ष

मौखिक रूप से प्रस्तुत नहीं की थी । उक्त आयातक जिन्हें अपने आयात ब्यौरों को विशेष रूप से प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, ने कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की ।

(ट) विशेष रक्षोपाय कानून के अधीन उनका मामला ऐसा अन्तिम मामला नहीं हो सकता । चीन चैम्बर द्वारा इस स्थिति को संभालने का सर्वाधिक कारगर तरीका संकीर्ण वाणिज्यिक विचार-धारा से ऊपर उठकर, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के बारे में चीन के विनिर्माताओं को शिक्षित करके उस देश के कानूनों का आदर और पालन करने की आवश्यकता है जिसके साथ वे व्यावसायिक संबंध स्थापित करते हैं । भारत और चीन के लोगों के बीच उत्तम व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध स्थापित करने के लिए यह सबसे प्रभावी रास्ता है ।

चीन के निर्यातकों के विचार

उन्होंने मुख्यतः निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं-

(क) वर्तमान जांच कठोर और विवेककारी है और गैर-कानूनी रूप से शुरू की गई मालूम होती है क्योंकि भारत और चीन की संबंधित सरकारों द्वारा कोई पूर्व परामर्श नहीं किए गए हैं जैसाकि उक्त प्रोटोकाल के अनुच्छेद 16 में परिकल्पित है । चीन द्वारा डब्ल्यू.टी.ओ. में शामिल होने के समय डब्ल्यू.टी.ओ. के सभी सदस्य देशों की ओर से एक विशिष्ट समझौता था कि वे केवल (असाधारण परिस्थितियों) में उक्त अनुच्छेद 16 को लागू करने तक सीमित रखेंगे । चीन के डब्ल्यू.टी.ओ. में शामिल होने के समय स्पष्ट रूप से यह समझा गया था कि "असाधारण परिस्थितियों" के अलावा कोई रक्षोपाय जांच उक्त अनुच्छेद 16 के प्रावधानों के अनुसरण में नहीं बल्कि रक्षोपाय करार के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

(ख) जांच गैर कानूनी ढंग से शुरू की गई है क्योंकि अपेक्षित संदर्भ वर्ष 2000-2001 है जिसके दौरान आवेदक ने यह बताया है कि भारत द्वारा आई एस एम एन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की थी जिसके फलस्वरूप जैसाकि आवेदन में स्वीकार किया गया है, 2000-2001 के आंकड़े एक संदर्भ वर्ष के रूप में प्रतिनिधि स्वरूप के अथवा उपयुक्त नहीं हैं । किसी विशिष्ट रक्षोपाय जांच में उचित प्रथा के विपरीत निवेदित रक्षोपाय शुल्क 1 अप्रैल, 2001 से 31 मार्च, 2002 तक की जांच अवधि के दौरान भारत द्वारा आयातित चीन के मूल के कथित आई एस एम एन के संबंधित औसत कीमतों और जांच अवधि के दौरान भारत द्वारा अन्य देशों से किए गए आई एस एम एन आयातों की कीमतों के बीच अन्तर से अधिक है ।

(ग) जैसाकि आरोप लगाया गया है, चीन मूल के आई एस एम एन आयातों द्वारा आयातों में अचानक कोई वृद्धि नहीं हुई है, बाजार में व्यवधान नहीं हुआ है अथवा कोई कारणात्मक संबंध नहीं है विशेषतः जबकि सभी हितबद्ध पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि वर्ष 2000-2001 एक उचित संदर्भ वर्ष नहीं है इसलिए महानिदेशक (विशिष्ट सुरक्षा) संदर्भ वर्ष के रूप में 2000-2001 के आधार पर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं।

(घ) आवेदक के जर्मन निर्यातकों के साथ संबंधों और इस तथ्य की दृष्टि से भी कि वह 'घरेलू उद्योग' के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करता कि चीन और भारत दोनों सूईयों को टैरिफ वर्गीकरण के अनुसार एक ही उद्योग मानते हैं और इस प्रकार, सूई उद्योग को 'घरेलू उद्योग' की स्थिति, 'आयातों में वृद्धि' और 'बाजार में व्यवधान' के प्रयोजनार्थ केवल आई.एस.एम.एन. के संबंध में नहीं बल्कि समग्र रूप से माना जाए। समग्र सूई उद्योग के संबंध में आंकड़े उपलब्ध न होने पर 'घरेलू उद्योग की स्थिति', 'आयातों में वृद्धि' और 'बाजार में व्यवधान' के मुद्दों के संबंध में कोई निष्कर्ष संभव नहीं है। यह मान लेने का भी कोई उचित आधार नहीं है कि चीन मूल की कथित रूप से 90% सूईयां आई.एस.एम.एन. है। आई एस.एम.एन. का उनके सकल सूई उत्पादन में 40% हिस्सा है।

(ङ) चीन मूल से आयातित आई.एस.एम.एन. में वृद्धि के आधार पर जांच शुरू करना चीन से हुए आयातों से अलग है और महानिदेशक के समक्ष इस बात को प्रदर्शित करने का पर्याप्त सबूत होना चाहिए कि तीसरे देशों के आयात वस्तुतः चीन मूल से होते हैं। हांगकांग और सिंगापुर से आई एस एम एन के निर्यात को चीन के आई एस एम एन के निर्यातों के साथ गलत ढंग से एकत्र किया गया है ताकि पर्याप्त साक्ष्य के बगैर आयातों में वृद्धि का आरोप लगाया जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने जांच अवधि के दौरान सिंगापुर अथवा हांगकांग को आई एस एम एन का कोई निर्यात नहीं किया।

(च) जैसाकि आरोप लगाया गया है, भारत में घरेलू उद्योग द्वारा बाजार में किसी व्यवधान का सामना नहीं किया गया। मामले की सच्चाई यह है कि भारत में आवेदक घरेलू उद्योग के पास आवेदन में दिए गए आंकड़ों के अनुसार इकानॉमी ऑफ स्केल, आधुनिक प्रक्रिया की कमी है और उन्होंने कभी अधिक क्षमता उपयोग नहीं किया है। यह स्पष्ट है कि आवेदक ने दक्षता और क्षमता उपयोग में सुधार करने की बजाय तुलनात्मक रूप से पूंजी की अधिक लागत पर 1 जनवरी, 2000 से अपनी क्षमता को दोगुना करके अपने व्यावसायिक निर्णयों में गलती की थी।

(छ) आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से मालूम होता है कि घरेलू बिक्रियों और क्षमता उपयोग में जांच अवधि के दौरान सुधार हुआ और उनकी निर्यात बिक्रियों और क्षमता उपयोग में गिरावट आई। घटिया निर्यात कार्य निष्पादन भारत में बाजार का व्यवधान नहीं है और न ही चीन को शामिल करते हुए विशिष्ट सुरक्षा जांच के लिए उचित कारण है। यह भी नोट किया जाए कि अन्य भारतीय विनिर्माताओं ने लाभ दर्शाया है जिनसे मालूम होता है कि भारत में बाजार में कोई व्यवधान नहीं हुआ है। किसी अकेले घरेलू उत्पादक द्वारा घटिया कार्य निष्पादन का तात्पर्य बाजार में व्यवधान उत्पन्न होना नहीं है।

(ज) निवेदित रक्षोपाय शुल्क आवेदक द्वारा अपनी विद्यमानता अथवा गैर क्षतिकारक कीमत के दावे के आधार पर है जो तथाकथित चीन मूल के अतिरिक्त आई एस एम एन के आयातों की औसत कीमत से भी बहुत अधिक है जो किसी विशिष्ट सुरक्षा जांच के विपरीत है जिसमें दावा किया गया अधिकतम रक्षोपाय शुल्क चीनी मूल के अतिरिक्त आई एस एम एन की औसत आयात कीमत पर आधारित हो सकता है। भारत के लिए सिले हुए वस्त्रों और चमड़े के उत्पाद महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अर्जक हैं। चीन से आई एस एम एन के आयातों से भारत के इन असाधारण निर्यातों से उद्योगों की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। इसके अतिरिक्त स्वयं आवेदक के अनुसार आई एस एम एन की सकल घरेलू खपत जांच अवधि के दौरान 186612 कि.ग्रा रही। आवेदक और अन्य घरेलू उत्पादक क्षमता का पूरा उपयोग करके भी वर्तमान मांग का एक हिस्सा भी पूरा करने के योग्य नहीं हैं। इसके अलावा वास्तविक प्रयोक्ता चीन से आई एस एम एन की गुणता की स्वीकार्यता और भारत के नाजुक निर्यात उद्योगों के लिए इसकी आवश्यकता का निर्णय करने के लिए सर्वोत्तम स्थिति में हैं। चीन से आई एस एम एन के आयातों पर विशिष्ट सुरक्षा शुल्क लगाना लोकहित में नहीं होगा क्योंकि आवेदक आई एस एम एन के घरेलू विनिर्माण द्वारा 90% घरेलू बिक्री करने का दावा करता है इसलिए कोई रक्षोपाय शुल्क लगाने से उसका एकाधिकार ही मजबूत होगा। महानिदेशक ऐसा कोई शुल्क लगाने से पहले समग्र लोक हित पर विचार कर सकते हैं। इस संबंध में कृपया यह भी ध्यान में रखा जाए कि भारत में आई एस एम एन पर सीमा शुल्क टैरिफ पहले ही बहुत अधिक है।

(झ) यह नोट किया जाए कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से उनके द्वारा अधिकतम 58% क्षमता उपयोग किया गया है और वर्ष 1997 और 2002 के बीच यह 51% से 58% के बीच रहा है। इसके अतिरिक्त क्षमता उपयोग में कमी होकर 45% होना स्वयं पर्याप्त नहीं है और पूर्णतः असंगत है, और जबकि क्षमता वर्ष 2000-2001 से दोगुनी हो गई थी और इसे ध्यान में रखते हुए जांच अवधि के दौरान किया गया उत्पादन आवेदक

की 2000 से पहले की क्षमता के 90% से अधिक था। आवेदक द्वारा अपनी दक्षता में सुधार किए बगैर इच्छानुसार क्षमता में वृद्धि करने का निर्णय करने के लिए स्पष्टीकरण देने और इसकी जांच करने की जरूरत है। आवेदक ऐतिहासिक रूप से कम क्षमता उपयोग का कारण स्पष्ट करे और तब भी क्षमता में वृद्धि करने के कारण बताए विशेषतः जब वह 2000 से पूर्व की अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता था जो आवेदक के कथनानुसार लगभग 25714 कि.ग्रा. थी। आवेदक को यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि क्या मशीनों के रख-रखाव की लम्बी समय तालिका है अथवा लम्बा टर्न अराउंड समय है अथवा आवेदक द्वारा विनिर्मित आई एस एम एन की अधिक अस्वीकृति दर है। आवेदक के लिए यह दर्शाना भी महत्वपूर्ण है कि श्रमिक अशांति अथवा अन्य समस्याओं अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों आदि के कारण कितने श्रम दिवसों का नुकसान हुआ। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और उन्हें समग्र रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि मशीनों की संस्थापना की प्रारम्भिक अवधि के दौरान शुरूआती समस्याएं हैं जिनके फलस्वरूप स्पष्टतौर पर क्षमता का कम उपयोग हुआ है।

() उनकी क्षमता बहुत अधिक है और उनका क्षमता उपयोग अपेक्षाकृत अधिक अर्थात् लगभग 96% है और अस्वीकृति दर बहुत ही कम और/अथवा न्यूनतम है। आवेदक द्वारा वर्णित प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है जिसमें अनेक चरण हैं जो 100 से अधिक हैं और स्पष्टतः बहुत अधिक अस्वीकृति दर होगी। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या चीन से आयातित आई एस एन एन के ग्रेड वही हैं जो जांच अवधि के दौरान आवेदक द्वारा बनाए गए आई एस एम एन के ग्रेड हैं।

(ट) डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार जांच अवधि के दौरान चीन से आई एसएमएन के आयातों की मात्रा लगभग 44516 कि.ग्रा. थी। तथापि, चीनी सीमाशुल्क प्राधिकरणों द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार जांच अवधि के दौरान आई एस एम एन और घरेलू सिलाई मशीन की सुईयों का कुल निर्यात 35538.4 कि.ग्रा. है। किसी भी स्थिति में डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदर्शित आंकड़े आवेदक द्वारा प्रस्तुत समेकित 1004216 से बहुत कम हैं।

(ठ) आवेदक का सही प्रयोजन वर्तमान जांच के बहाने अपने विदेशी सहयोगियों के लिए बाजार में लाभकारी अवसर प्राप्त करना है। आवेदक द्वारा निवेदित रक्षोपाय शुल्क लगाने से निर्यात आय, प्रयोक्ताओं के लिए अधिक लागतों, रोजगार और आर्थिक विकास के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा भारत में उक्त आवेदक का एकाधिकार स्थापित होगा अथवा एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा होगी और किसी भी प्रकार से इसे व्यापक लोकहित में नहीं समझा जा सकता।

(ड) घरेलू उत्पादन के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना का विश्लेषण किया गया है और उनके द्वारा यह टिप्पणी की गई है कि सकल उत्पादन में घरेलू तथा निर्यात दोनों उत्पादन शामिल हैं। सकल उत्पादन में घरेलू/निर्यात उत्पादन के योग के सामान्य विश्लेषण से मालूम होता है कि आवेदक ने सदैव निर्यात उत्पादन पर अधिक जोर दिया है।

(ढ) यह स्पष्ट नहीं है कि जांच अवधि के दौरान चीन से आयातित आई एस एम एन के ग्रेड वहीं हैं जो आवेदक द्वारा बनाए गए आई एस एम एन के ग्रेड हैं। चीनी ग्राहकों के पास सिलाई मशीनों की सूइयों का केवल एक ही वर्गीकरण है 8452.3000 जिसमें आईएसएमएन और घरेलू सिलाई मशीन सूईयां दोनों शामिल हैं।

(ण) चीन से निर्यात कीमतें चीन, हांगकांग और सिंगापुर से हुए आई एस एम एन के सकल निर्यातों पर आधारित मालूम होती है। जब तक सिंगापुर और हांगकांग के निर्यातकों को चीन मूल के निर्यातक नहीं दर्शाया जाता तब तक उनकी अलग से गणना करने की जरूरत है सूईयों के आयात की सीआईएफ लागत से वर्ष 1997-98 को आधार वर्ष मानने पर 21 प्रतिशत की वृद्धि मालूम होती है। निर्यात कीमत में अधिक वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि मुख्य घटकों अर्थात् स्टील की तार की कीमत वही रही है। नियमित लागत बचत उपायों को अपनाकर और उच्च प्रौद्योगिकी की मशीनों का प्रयोग करने में अस्वीकृति दें बहुत कम बनाए रखकर वे उत्पादन की लागत को अत्यधिक नियंत्रण में रख सके हैं। उनके द्वारा उत्पादित सूईयां मध्यम और कम ग्रेडों की हैं जिनकी मध्यम और कम गति है तथा विकासशील देशों को और उन क्षेत्रों को इनका निर्यात किया जाता है जिसका मुख्य कारण यह है कि निर्यात कीमत का निर्बाध रूप से क्यों बढ़ाया जाए।

(त) यह स्पष्ट नहीं है कि किस आधार पर आवेदक ने चीन से औद्योगिक सिलाई मशीन सूईयों के कुल आयात में घरेलू सूईयों का दस प्रतिशत हिस्सा होने का अनुमान लगाया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़े सही मालूम नहीं होते हैं और उन्हें अस्वीकार किया जाता है। चीनी सीमा शुल्क प्राधिकरणों के अनुसार जांच अवधि के दौरान आई एस एम एन और घरेलू सिलाई मशीन सूईयों दोनों का कुल निर्यात केवल 35538.4 कि.ग्रा. है न कि आवेदक द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए परिकल्पित किए गए अनुपात से अधिक बढ़ाए गए आंकड़े।

(थ) विशिष्ट सुरक्षा जांच की कार्यवाहियां कुछ कानूनी प्रावधानों द्वारा विनियमित होती हैं और यदि मूलभूत कानूनी हिस्से पूरे नहीं किए जाते हैं तो उक्त कार्यवाहियां समाप्त

कर देने की आवश्यकता होती है जैसाकि वर्तमान जांच के मामले में है। यह कहा गया है कि वर्तमान जांच भेद-भावपूर्ण है और उसको शुरू करने के लिए अनिवार्य उपेक्षाओं की उपस्थिति में दिमाग का प्रयोग किए बगैर इसे गैर कानूनी रूप से शुरू किया गया है और यह सीमा-शुल्क टैरिफ (संक्रमणकालीन उत्पाद विशिष्ट सुरक्षा शुल्क) नियमावली 2002 (क) उक्त अधिनियम की धारा 8 ग (1) के नियम 5 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 ग के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

(द) आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से चीन से भारत को औद्योगिक सिलाई मशीन सूईयों के आयात में कोई तीव्र वृद्धि नहीं हुई है ताकि यह आवेदक की वास्तविक क्षति का एक महत्वपूर्ण और/अथवा मुख्य कारण बन सके। इसके अतिरिक्त जब इसकी तुलना अनुचित अनुपयुक्त संदर्भ वर्ष 2000-2001 से की जाए जिसके दौरान भारत द्वारा आई एस एम एन के निर्यातों पर पाटनरोधी जांच की गई थी जिसके परिणामस्वरूप चीन से आई एस एम एन के निर्यातों पर अनन्तिम शुल्क लगाया गया था।

(ध) धारा 8 ग (7)(क) के अधीन यथा परिभाषित घरेलू उद्योग का अभिप्राय समान वस्तु अथवा भारत में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तु के समस्त उत्पाद को (आवेदक की तरह कोई अकेला उत्पाद नहीं) से है और इसे महानिदेशक द्वारा उसी तरह से समझे जाने की जरूरत है। देश में सूईयों के सभी विनिर्माताओं को घरेलू उद्योग के साथ में देखना होगा। तदनुसार, यह आवश्यक और अपेक्षित है कि आई एस एम एन के वांछित आयातों की शिकायत के किसी आवेदन को भारत के समस्त सूई उद्योग द्वारा दायर करना अनपेक्षित है न कि एक उत्पादक द्वारा जैसा कि वर्तमान मामले में है, और इस पर जब सूई उत्पादकों द्वारा समस्त घरेलू उद्योग के रूप में आयातों में तेजी से वृद्धि की शिकायत की जाए और उचित जांच पड़ताल के पश्चात इस पर केन्द्र सरकार द्वारा ही कार्यवाही की जा सकती है।

(न) भारत के उच्चतम न्यायालय ने बैरियम केमिकल्स लि० और एएनआर बी. कम्पनी लॉ बोर्ड एण्ड अदरस (ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 295) में अन्य बातों के साथ यह माना है कि केन्द्र सरकार का मत ईमानदार होना चाहिए और केन्द्र सरकार द्वारा अपना मत दिए जाने से पहले इसके पास कुछ निष्कर्षों का सुझाव देने वाली परिस्थितियाँ अवश्य होनी चाहिए। माननीय न्यायालय ने यह भी माना है कि निसंदेह मत व्यक्त करना सकारात्मक है परन्तु कार्यवाही के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में निष्कर्ष की संगत परिस्थितियों की मौजूदगी अवश्य दिखानी चाहिए। यदि कार्यवाही पर इस आधार पर आपत्ति की जाती है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8 (ग) के

अन्तर्गत पूर्वानुमानित किस्म के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो जब तक परिस्थितियों की मौजूदगी सिद्ध न की जाए तब तक कार्यवाही को रोका जा सकता है और चूंकि 'परिस्थितियों' की मौजूदगी कोई मत निर्धारित करने के लिए मौलिक शर्त है, इसलिए परिस्थितियों की मौजूदगी पर कोई आपत्ति की जाए तो इसे प्रथमदृष्ट्या साबित करना होगा और यह अनुमान लगाना पर्याप्त नहीं है कि परिस्थितियाँ मौजूद हैं। और इस बात का कोई संकेत न दिया जाए कि वे क्या हैं क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए जिनसे किसी निश्चितता का निष्कर्ष निकलता हो। उक्त परिस्थितियों की विद्यमानता के किसी मत से पहले अवश्य साबित करना चाहिए ताकि जांच प्रारम्भ करने का निर्णय लिया जा सके। यह सादर प्रस्तुत है कि कोई जांच शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार का अधिकार और शक्ति कुछ तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होती हैं तथा केवल संतुष्टि ही पर्याप्त नहीं है और यदि संगत मापदण्ड मौजूद नहीं है तो जांच शुरू नहीं की जानी चाहिए थी और इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

(प) आवेदक ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहकर सिंगापुर के आईएसएमएन के आयातकों को चीन मूल के आयातकों के साथ शामिल करने का स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है कि सिंगापुर में सूर्यो का विनिर्माण करने वाला कोई कारखाना नहीं है और जर्मनी, जापानी तथा कोरियाई विनिर्माताओं के भारत में वितरक और एजेंट हैं और इस प्रकार वे सिंगापुर के जरिए भारत को निर्यात नहीं करेंगे और यह भी कि जर्मनी से सिंगापुर के निर्यातक बहुत कम हैं और अन्ततः सिंगापुर से उत्पाद की कीमत जर्मनी से आयातित उत्पाद से कम है। यह जांच करने की जरूरत है कि सिंगापुर में कोई विनिर्माण आधार नहीं है। यह मानते हुए भी कि यह सही है यह निष्कर्ष निकालने का कोई औचित्य नहीं है कि जो कुछ सिंगापुर से आयात किया जा रहा है वह चीनी मूल का है। वितरक व्यवस्थाओं का होना अथवा न होना बिना किसी आगे विश्लेषण के कोई घटक नहीं बनाया जा सकता है और इसकी कोई संगतता नहीं होगी क्योंकि कोई आयातक जर्मनी, कोरिया और जापान से सिंगापुर में सूर्यो का आयात कर सकता है और उनका भारत में निर्यात कर सकता है। सिंगापुर से सूर्यो की कीमत कथित रूप से जर्मनी से कम बताई गई है। परन्तु उससे बिक्रियों में वृद्धि करने के लिए कीमत लाभांश आदि का आवेदक के अपने तर्क के अनुसरण में कोई बात सिद्ध नहीं होती और यही तर्क सिंगापुर से आयातित जर्मन, कोरियाई और जापानी मूल के उत्पादों के मामले में आसानी से लागू किया जा सकता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर इंपोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनी एण्ड इलेक्ट्रानिक्स प्रोडक्ट्स (सीसीसीएमई) ने कहा है कि उनके राष्ट्रीय व्यापी

गैर लाभकारी व्यवसायिक संगठन है और केवल इसी प्रकार के व्यवसायिक संगठन आयात और निर्यात के क्षेत्र में चीनी मशीन और इलैक्ट्रानिक उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं। आई एस एम एन एक ऐसा उत्पाद है जिसका सीसीसीएमई के सदस्य व्यापार करते हैं जब विश्व व्यापार संगठन करार जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 (ग) का आधार है, में चीन के शामिल होने के प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 16 पर वार्ताएं की गई थी तो डब्ल्यूटीओ के सदस्यों द्वारा एक समझौता प्रस्तुत किया गया था जिसमें भारत भी शामिल था कि इसे असाधारण परिस्थितियों में प्रतिबंध के साथ और अन्तिम उपाय के रूप में लागू किया जाएगा और अब अन्य सभी व्यापारिक उपाय समाप्त हो गए। यह कहा गया है कि वर्तमान जांच गैर कानूनी रूप से कठोर और भेद-भावपूर्ण है क्योंकि उक्त प्रोटोकॉल के उक्त अनुच्छेद 16 में यथा परिकलित भारत और चीन की संबंधित सरकारों के बीच कोई पूर्व विचार-विमर्श नहीं किया गया है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान जांच प्रथम विशिष्ट सुरक्षा जांच है जिसमें कथित रूप से चीनी मूल का सामान शामिल है।

(फ) सीसीसीएमई, चीनी निर्यातकों और चीनी सरकार ने इस तथ्य के बावजूद वर्तमान जांच में पूरा सहयोग दिया है कि उक्त जांच सीमा शुल्क टैरिफ (संक्रमणकालीन उत्पाद विशिष्ट सुरक्षा शुल्क) नियमावली 2002 के नियम 5 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8 (ग) के कानूनी प्रावधानों के विपरीत की गई।

(ब) आल्टेक के प्रबंध निदेशक ने दिसम्बर, 2002 में चेन्नई में क्रमशः व्हाइट क्रेन एंड हॉटिंग के महाप्रबंधकों के साथ बातचीत की थी और उनसे दो मिलियन अमेरिकी डालर का भुगतान करने के लिए उनके साथ सौदेबाजी करने का प्रयास किया था जो वर्तमान जांच को वापस लेने की कीमत थी यह निवेदन है कि उसने अपने गैर-कानूनी प्रयास करने के बाद व्हाइट क्रेन एंड हॉटिंग से अपने कारखाने में लगभग दो मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का अनुरोध किया था जिसको इंकार कर दिया गया था। उसने अपने गैर-कानूनी, अनीतिगत प्रयासों को आगे बढ़ाने में भारतीय आई एस एम एन बाजार पर एकाधिकार करने के लिए हॉटिंग और व्हाइट क्रेन से केवल आल्टेक को आईएसएमएन का निर्यात करने तथा आल्टेक के साथ हॉटिंग और व्हाइट क्रेन द्वारा एक आबंध एजेंसी करार पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध भी किया था। इसके अतिरिक्त उसने यह सुनिश्चित करने के लिए उसके साथ एक करार पर हस्ताक्षर करने के लिए सीसीसीएमई से भी अनुरोध किया था कि सभी सिलाई मशीन सूई निर्यातक और विनिर्माता (आईएसएमएन ही नहीं बल्कि घरेलू सिलाई मशीन सूईयों सहित) अगले पाँच वर्षों में (अर्थात् पूरे भारतीय बाजार में चीनी सिलाई मशीन सूईयों की आबद्ध एजेंसी) आल्टेक के जरिए भारतीय बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। आवेदक सद्भावना के साथ

प्राधिकारियों के साथ नहीं पहुंचे हैं और उन्होंने अनीतिगत रूप से विद्वेषपूर्वक और गुप्त उद्देश्य के साथ कार्यवाही की है। इस प्रकार के किसी भी प्रकार के रक्षाउपाय शुल्क के लिए पात्र नहीं हैं।

आयातकों और प्रयोक्ताओं के विचार -

उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ निम्न प्रकार कहा है:-

(i) दायर किया गया आवेदन भ्रान्ति उत्पन्न करने वाले तथ्यों और आंकड़ों से पूर्ण है जिन्हें आवेदक स्वयं यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाए, तो उचित साबित नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा निवेदित 3628 रु० प्रति कि.ग्रा. का असाधारण और अनुचित रक्षोपाय शुल्क निराधार है। चीन से आयातित सूईयां उत्तम गुणवत्ता और उचित मूल्य की रही हैं दूसरी ओर अन्य देशों की सूईयां कीमत में अधिक हैं तथा छोटे विनिर्माताओं के लिए लागत में बचतकारी नहीं हैं। आल्टेक की सूईयां भी अधिक कीमत का उत्पाद है और चूंकि उनकी गुणवत्ता न्यूनाधिक रूप से चीनी सूईयों के तुलनीय है, इसलिए छोटे प्रयोक्ताओं को अपनी लागतों को सीमित रखना पड़ता है तथा किसी लामांश के लिए चीनी सूईयों को वरीयता देनी पड़ती है। चीन से आयातित सूईयों का अनुप्रयोग आल्टेक द्वारा उत्पादित अथवा तीसरे देशों से आयातित सूईयों से अलग है।

(ii) आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि सूईयों के उत्पादन में लगभग सौ चरण हैं, तथापि विकसित उच्च गुणवत्ता वाली सूईयों को बनाने की आल्टेक की तरह नहीं बल्कि उनकी जानकारी के अनुसार केवल बत्तीस चरण शामिल हैं। आल्टेक ने वजन के आधार पर विभिन्न सांख्यिकीय आंकड़े दिए हैं परन्तु व्यापार में सूईयों का व्यवसाय कीमतों अथवा गणना के आधार पर किया जाता है। आल्टेक द्वारा प्राधिकारियों को भ्रान्ति में डालने के लिए वजन के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत किए मालूम होते हैं।

(iii) आवेदक ने केवल निहित स्वार्थों और अपने जर्मन सहायक, जर्मनी के लामर्टज की सहायता के लिए ही आवेदन दायर किया और कोई रक्षोपाय शुल्क लगाया जाए तो उससे आभासी रूप से भारत में हजारों आईएसएमएन प्रयोक्ता आवेदक की अधिक कीमत वाली घटिया सूईयाँ अथवा इससे संबंधित जर्मन निर्यातक की अधिक कीमत वाली सूईयाँ खरीदने के लिए बाध्य हो जाएंगे जो प्रयोक्ताओं पर अलामकारी वित्तीय बोझ के बराबर होगा और इससे विदेशी मुद्रा का अत्यधिक घाटा होगा क्योंकि

प्रयोक्ताओं को जर्मनी, जापान और कोरिया से अधिक लागत वाली सूईयां खरीदनी पड़ेगी ।

(iv) आवेदक को जो भी नुकसान हुए हैं उसकी अपनी अकुशलता के कारण हुए हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आवेदक ने अपनी प्रतिस्पर्धा में सुधार करने की बजाय जांच के लिए आवेदन करने का चयन किया है और इसके फलस्वरूप भारत में हजारों प्रयोक्ताओं के लिए संभावित वित्तीय खतरा उत्पन्न कर दिया है ।

जांच परिणाम

मैंने इस मामले के रिकार्डों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत निवेदनों की जांच की है । विभिन्न पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर आवश्यक सीमा तक निम्नलिखित निष्कर्षों में उचित स्थानों पर कार्यवाही की गई है । तथापि इस मामले के गुणावगुणों पर विचार-विमर्श करने से पहले एक प्रारम्भिक मुद्दे पर विचार-विमर्श करना आवश्यक समझा गया है जिसे सीमा शुल्क टैरिफ (संक्रमणकालीन विनिर्दिष्ट रक्षोपाय शुल्क नियमावली) (जिसे इसमें इसके बाद एसएसजीडी नियमावली कहा गया है) के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 (ग) के अधीन कार्यवाहियां करने और महानिदेशक (विनिर्दिष्ट सुरक्षा) के क्षेत्राधिकार के संबंध में कुछ पक्षकारों द्वारा जोरदार ढंग से उठाया गया है ।

निर्यातकों के विद्वान वरिष्ठ काउंसल ने प्रयोग किए गए विभिन्न शब्दों के अर्थ पर पर्याप्त तर्क किए और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 ग के अंतर्गत लगाई गई कुछ शर्तों के संबंध में तर्क देते हुए यह कहा कि जांच उक्त धारा 8 ग में निर्धारित सिद्धांतों के प्रतिकूल है । काउंसल ने मेरा ध्यान बेरियम केमिकल्स लि0 एंड एनआर बनाम कंपनी लॉ बोर्ड तथा अन्य (एआईआर 1967 एससी 295) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर भी आकर्षित किया । मैंने इस उद्धरण के साथ-साथ सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाहियों पर बहुत गंभीर रूप से विचार किया । मेरी यह राय है कि इस उद्धरण से कोई सहायता नहीं मिलती है क्योंकि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाहियाँ सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान कार्यवाहियों के समकक्ष नहीं हैं । जो कुछ महानिदेशक ने दिनांक 13 अगस्त, 2002 का नोटिस जारी करके करने का प्रस्ताव किया है वह किसी सुरक्षा उपाय को लागू करना अथवा बनाना नहीं है बल्कि ऐसी जांच-पड़ताल करने के लिए जांच की कार्यवाही शुरू करना है । महानिदेशक को सीमाशुल्क टैरिफ (संक्रमण कालीन उत्पाद सुरक्षा शुल्क) नियमावली 2002 के नियम 4 के अंतर्गत कोई अनंतिम अथवा अंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाने के बारे में सिफारिश करने

का कार्य सौंपा गया है। तथापि, रक्षोपाय शुल्क केवल केन्द्र सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि कोई राय कायम करने से पहले प्राधिकारी के समक्ष ऐसी परिस्थितियाँ होनी चाहिए जिनमें विशेष वृद्धियाँ होने का सुझाव दिया गया हो। इस मामले में महानिदेशक ने अवधारणा और निरर्थक अनुमानों पर मत कायम नहीं किया है परन्तु प्रथम दृष्ट्या मत कायम करने के लिए उसके पास परिस्थितियाँ और प्राधिकृत आंकड़े उपलब्ध थे जिनके आधार पर जांच प्रारंभ करने का नोटिस जारी किया गया था। कोई मत कायम करने के लिए अपेक्षित उक्त निर्णय के अनुसार मौलिक स्थितियाँ मौजूद होनी चाहिए, महानिदेशक के पास उपलब्ध थीं। अतः निर्णय निर्यातकों के लिए कोई लाभकारी नहीं है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर काउंसिल द्वारा गलती से विश्वास किया गया है और तथ्यों के आधार पर वर्तमान मामले में की जा रही कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। जांच आरंभ करने के लिए उदाहरणात्मक शर्तों की पूर्ति का दायित्व प्रथम दृष्ट्या पूरा हो गया था। जाँच आरंभ करने के नोटिस को निराधार कल्पनाओं और अनुमानों पर आधारित नहीं माना जा सकता।

एक अन्य संबंधित मुद्दा जिसे उठाया गया है और समान रूप से महत्वपूर्ण है, डब्ल्यू टी ओ में चीन जन. गण. के शामिल होने वाले प्रोटोकॉल (जिसे इसके बाद प्रोटोकॉल कहा गया है) के बारे में है। यह जोरदार तर्क दिया गया है कि वर्तमान कार्यवाहियाँ उक्त प्रोटोकॉल के उपबंधों का उल्लंघन करती हैं। यह तर्क दिया गया है कि प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 16, जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 ग का आधार है, पर जब वार्ताएं की गई थीं तो भारत समेत डब्ल्यू टी ओ के सदस्यों द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया था कि इसका प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में सीमित रूप से और अंतिम उपाय के लिए किया जाएगा जब सभी अन्य व्यापारिक उपाय समाप्त हो जाएं। यह कहा गया है कि वर्तमान जाँच गैर-कानूनी रूप से कठोर और भेदभावकारी है क्योंकि उक्त प्रोटोकॉल के उक्त अनुच्छेद 16 में यथा-परिकल्पित भारत और चीन की संबंधित सरकारों के बीच कोई पूर्व परामर्श नहीं किया गया है।

मैंने उक्त प्रोटोकॉल की सावधानी पूर्वक जांच की है और सामान्य पठन से यह मालूम हुआ है कि प्रोटोकॉल में किसी पूर्व परामर्श की परिकल्पना नहीं की गई है और इसमें केवल तभी परामर्श करने के लिए कहा गया है जब प्रभावित डब्ल्यू टी ओ सदस्य किसी प्राथमिक निर्धारण के अनुसंग में अनंतिम रक्षोपाय करता है कि आयातों से बाजार में व्यवधान उत्पन्न हो गया है अथवा उत्पन्न होने का खतरा है। इन उपायों को रक्षोपाय संबंधित नीति को अधिसूचित करने की जरूरत है और उसके तुरंत बाद द्विपक्षीय परामर्श किए जाने के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त,

भारतीय घरेलू कानून में ऐसा कुछ नहीं है जिससे डब्ल्यू टी ओ को शिकायत हो अथवा जिसमें कानूनी तौर पर ऐसे किसी पूर्व परामर्श का निर्धारण हो । तथापि, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि जब चीन द्वारा अनुरोध किया गया तो भारत ने तुरंत परामर्श के लिए सहमति व्यक्त की और 22 अक्टूबर, 2002 को जेनेवा में किए गए परामर्शों के लिए दिल्ली से एक अधिकारी को विशेष रूप से प्रतिनियुक्त किया गया था । अन्य बातों के साथ-साथ चीनी प्राधिकारियों को यह स्पष्ट किया गया था कि रक्षोपाय जांच एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है और इसे बीच में नहीं रोका जा सकता है और यदि कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने की सुविधा के लिए चीनी पक्ष द्वारा यदि निवेश उपलब्ध कराया जाता है तो यह बहुत लाभदायक होगा ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह देखा गया है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम और एसएसजीडी नियमावली के अधीन परिकल्पित सांविधिक प्रावधानों की आवश्यकता को पूरी तरह पूरा कर दिया गया है और जांच प्रारंभ करने का नोटिस सही तरीके से जारी किया गया है ।

जांचाधीन उत्पाद

जांचाधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के तत्कालीन शीर्ष 8452.30 और सुमेलीकृत वस्तुविवरण और कोडिंग प्रणाली के आधार पर भारतीय व्यापार वर्गीकरण (आईटीसी) के 84523000 के अंतर्गत वर्गीकृत आईएसएमएन है। 8 अंकीय सीमाशुल्क वर्गीकरण से संबंधित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश 2003 (2003 का 1) द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के संशोधन, जो 1 फरवरी, 2003 को लागू हुआ था, से अब आईएसएमएन 84523090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है । तथापि, वर्गीकरण सुविधा के प्रयोजनार्थ सूचित किया गया और जांचाधीन उत्पाद को शामिल करने के कार्यक्षेत्र को सीमित करने वाले के रूप में किसी भी प्रकार न समझा जाए ।

घरेलू उद्योग

आवेदन आईएसएमएन के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए आईएसएमएन के घरेलू उत्पादकों की ओर से ऑल्टेक द्वारा दायर किया गया है । हालांकि, तथाकथित रूप से तीन अन्य कंपनियाँ आईएसएमएन का उत्पादन कर रही हैं परन्तु ऑल्टेक आईएसएमएन का अधिकांश उत्पादन और बिक्री करता है । आई सी सी सी एम ई के अतिरिक्त निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि ऑल्टेक घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है । एक महत्वपूर्ण मुद्दा, जो सीमाशुल्क टैरिफ

अधिनियम के अधीन घरेलू उद्योग का गठन करने के बारे में है, उठाया गया है और इस पर काफी तर्क दिए गए हैं। यह कहा गया है कि आवेदक एक जर्मन निर्यातक के साथ इसके संबंधों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य की दृष्टि से भी घरेलू उद्योग के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं है कि चीन और भारत दोनों टैरिफ वर्गीकरण के अनुसार भी सूइयों को एक ही उद्योग मानते हैं और इस प्रकार इस प्रयोजन के लिए सूई उद्योग को अकेले आईएसएमएन के संबंध में बल्कि समग्र उद्योग के रूप में माना जाए। इसके अतिरिक्त यह दावा किया गया था कि समग्र सूई उद्योग के संबंध में आंकड़े न होने के कारण महानिदेशक द्वारा इस मुद्दे के संबंध में कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। यह तर्क उचित मालूम नहीं होता है क्योंकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 ग के अंतर्गत कार्यवाहियां टैरिफ पर केन्द्रित नहीं हैं बल्कि वस्तु/उत्पाद के संदर्भ में है। टैरिफ अनुसूची में प्रविष्टियों की व्याख्या करते समय उनका विधायिका द्वारा प्रयुक्त सामान्य शब्दावली और भाषा-शैली के रूप में अर्थ लगाया जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए और उनका लोकप्रिय अर्थ दिया जाना चाहिए जिससे उस विषय वस्तु को लोग भली-भांति परिचित हों जिसके संबंध में कानून द्वारा कार्यवाही की जा रही हो। भाषा की स्वतंत्र रूप से व्याख्या की जाए और इसे इसके व्याकरणिय अर्थ तक सीमित न रखा जाए। धारा 8 ग और एसएसजीडी नियमावली के प्रावधानों को इसकी समग्रता में पढ़ा जाए और समग्र रूप से अर्थ लगाया जाए ताकि यह सही अर्थ दे सके जिससे यह निष्प्रयोजन और नकारात्मक न बन सके। परन्तु, कोई संरचना, जिसका परिणाम असमान और असंगत हो, को दूर रखा जाए। ऐसी रचना जो दंडात्मक प्रावधान की तरह से न हो, की विभिन्न प्रकार से जांच करनी होती है। जहां तक जर्मन सहयोगी के साथ संबंध होने का प्रश्न है, मुझे घरेलू उद्योग की परिधि से आवेदक को अलग करने के लिए रक्षोपाय नियमावली के अंतर्गत कोई प्रतिबंध मालूम नहीं होता है जैसाकि पाटनरोधी जांच के मामले में होता है।

इसके अतिरिक्त आईएसएमएन के ज्ञात घरेलू उत्पादकों को प्रश्नावली भेजी गई थी। टी वी एस नीडल्स और शेमेज इंडिया से उत्तर प्राप्त हुआ था। यह देखा गया था कि टीवीएस नीडल्स लि० ने 1962 से घरेलू सूइयों का निर्माण किया है। कंपनी ने अपने उत्तर में यह सूचित किया था कि वे मुख्यतः घरेलू सूइयों (एचएचएन) का विनिर्माण कर रहे हैं और आईएसएमएन की केवल मामूली मात्रा है। यह देखा गया है कि कंपनी की 75 मिलियन सूइयों, जिनमें आईएसएमएन शामिल हैं, की स्थापित क्षमता है। वर्ष 2001-02 के दौरान कंपनी ने 42.73 मिलियन सूइयों का उत्पादन किया जिनमें से उन्होंने आईएसएमएन की बहुत थोड़ी सी मात्रा बनाई। कंपनी को पिछले तीन वर्ष के दौरान आईएसएमएन द्वारा निर्मित मात्राएँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। इसके ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यह पता लगाया था कि

कंपनी स्वयं आईएसएमएन का विपणन नहीं करती है और जितना भी उत्पादन किया जाता है, वह मै0 सिंगर इंडिया लि0 की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है जिन्हें आईएसएमएन की समस्त मात्रा हस्तांतरित कर दी जाती है। मै0 सिंगर इंडिया लि0 लगभग 2001 तक टीवीएस सीविंग नीडल्स लि0 में एक बड़ा इक्विटी धारक था और टीवीएस द्वारा विनिर्मित उत्पादों का बड़ा वितरक भी है। हालांकि शेमेज (आई) प्रा0 लि0, मुंबई ने एक घरेलू विनिर्माता के रूप में उत्तर नहीं दिया परन्तु सूइयों के आयातक के रूप में उत्तर दियारू ग्राज बेकर्ट एशिया लि0, चंडीगढ़ ने बिल्कुल उत्तर नहीं दिया और जांच में भाग नहीं लिया। इसलिए उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य की दृष्टि से कि उनका भारत में आईएसएमएन के निर्माण में अधिकांश हिस्सा है, ऑल्टेक के आवेदन को घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया हुआ समझा गया है।

वर्धित आयात

आईएसएमएन का भारत में मुख्यतः चीन जन.गण., जर्मनी, जापान, कोरिया (आरपी), सिंगापुर और ताइवान (चीनी ताइपेई) से आयात किया जाता है। आईएसएमएन का निर्यात सभी देशों से सामान्यतः कुल मिलाकर 1997-98 में 116470 कि.ग्रा. से बढ़कर 2001-02 में 174961 कि.ग्रा. हो गया था। आईएसएमएन के आयातों पर मूल सीमा शुल्क, जो 1998-99 में 40% था, को घटाकर 1999-00 में 35% कर दिया गया था और 2000-01 से इस पर 25% शुल्क लागू है।

आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए चीन से आयातित आयातों विशेषतः 2001-02 की अवधि के लिए आयातों के बारे में आयात आंकड़ों पर निर्यातकों और सीसीसीएमआई द्वारा संदेह व्यक्त किया गया है। यह कहा गया है कि आवेदक ने सिंगापुर और हांगकांग से आयातों को चीन मूल के आयातों में गलती से शामिल कर लिया है। सिंगापुर अथवा हांगकांग से केवल ऐसे आयात जो स्पष्ट रूप से चीन मूल के आयात साबित हो जाएं, को ही चीन के आईएसएमएन आयातों के साथ शामिल किया जाए। यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2001-02 के दौरान चीन से आईएसएमएन के आयातों की मात्रा 44516 कि.ग्रा. थी जो डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार है परन्तु चीनी सीमाशुल्क प्राधिकरणों द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार आईएसएमएन और घरेलू सहित सूइयों का उक्त अवधि के दौरान कुल निर्यात 35538.4 कि.ग्रा. था। डी जी सी आई एंड एस के आंकड़े भी आवेदक के 104216 कि.ग्रा. के कुल आंकड़ों से बहुत कम थे।

इस संबंध में आवेदक ने बताया है कि वर्ष 1997-98 से 2001-02 तक के आंकड़े डीजीसीआईएंडएस कलकत्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्तनवार आयात आंकड़ों से प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने बाजार के आसूचना स्रोतों के आधार पर घरेलू सूरियों के आयातों के आंकड़ों में उपयुक्त समायोजन किए हैं।

इस संबंध में 2001-02 की अवधि के दौरा आईएसएमएन के आयातों से संबंधित आवेदक द्वारा प्रस्तुत पत्तन-वार बयारों की सीमाशुल्क आयुक्त चेन्नई कार्यालय और आई.सी.डी. तुगलकाबाद से पुष्टि की गई थी। हालांकि आई.सी.डी. तुगलकाबाद से प्राप्त रिपोर्ट से मालूम हुआ कि 2001-02 के दौरान चीन अथवा सिंगापुर से आईएसएमएन का कोई आयात नहीं हुआ था जबकि चेन्नई सीमा शुल्क विभाग द्वारा यह पुष्टि की गई है कि आईएसएमएसन की 85355 कि.ग्र. मात्रा का चीन से भारत में आयात हुआ है और वर्ष 2001-02 में चेन्नई पत्तन पर सिंगापुर से कोई आयात नहीं हुआ है। यह देखा गया है कि चेन्नई में किए गए कुल आयात में से हुआटिंग ने 9737763 ₹/- मूल्य की 62940 कि.ग्र. मात्रा, व्हाइट क्रेन ने 1878124 ₹/- मूल्य की 20735 कि.ग्र. मात्रा और चाइना लाइट ने 667408 ₹/- के मूल्य की 1680 कि.ग्र. मात्रा का निर्यात किया था जो निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाएगा:-

नानटोंग हुआटिंग द्वारा निर्यात				
बी/ई	तारीख	आयातक	मूल्य(₹)	वजन (कि.ग्रा.)
331850	21 जून-01	कृष्णा रिबन्स, दिल्ली	548228	2990
335039	7 जुलाई-01	मैट्रो इम्पेक्स, दिल्ली	747658	4082
340257	30 जुलाई-01	कृष्णा रिबन्स, चेन्नई	10095576	5512
342921	9 अगस्त, 01	कृष्णा रिबल्स, दिल्ली	746047	4056
344774	21 अगस्त, 01	के के इम्पेक्स, दिल्ली	559535	3042
348542	5 सितम्बर, 01	के के इम्पेक्स, दिल्ली	726917	3952
355196	9.10.01	मद्रास इन्ट. इन्क. पोंडी	1862556	16900
358931	29 अक्टूबर-01	दिल्ली ट्रेडिंग हाउस, दिल्ली	867439	4646
367310	19 दिस. 01	मैट्रो इम्पेक्स, दिल्ली	965903	5148
381102	26-फरवरी-02	दिल्ली ट्रेडिंग, दिल्ली	1124069	7012
382606	7 मार्च-02	मैट्रो इम्पेक्स, दिल्ली	459835	5600
नानटोंग व्हाइट क्रेन द्वारा निर्यात				
380866	25.02.02	विजयलक्ष्मी इन्ट. दिल्ली	589032	6720
382596	07.3.02	दिल्ली ट्रेडिंग, दिल्ली	1289092	14015

चाइना लाइट द्वारा निर्यात

329660	11.6.01	जय इन्ट. चेन्नई	667408	1680
--------	---------	-----------------	--------	------

उपर्युक्त आंकड़े बिल प्रविष्टियों और मूल के देश के आधार पर संकलित किए गए हैं जैसाकि सीमाशुल्क रिकार्ड में उपलब्ध है। डीजीसीआईएंडएस ने स्पष्ट किया है कि उनके प्रकाशन में दर्शाए गए देशवार आयात कुल मिलाकर परेषण के देश भेजे गए देश को निर्दिष्ट करते हैं। यह देखा गया था कि दो चीनी निर्यातकों द्वारा अपने उत्तर में और सीसीसीएमई द्वारा घरेलू सूईयों सहित किए गए 35538.4 कि.ग्रा. निर्यात का दावा प्रथम दृष्टया गलत था और विश्वसनीय मालूम नहीं होता है। उन्होंने चीनी सीमाशुल्क विभाग द्वारा प्रमाणित कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था। सुनवाई के दौरान पूछे जाने के बावजूद उनके निर्यात के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हालांकि वे सभी जांच में सहयोग करने का दावा करते हैं। दो निर्यातकों द्वारा विशेष रूप से गोपनीय तरीके से प्रस्तुत सूचना भी बहुत बनावटी पाई गई थी और जानबूझ कर दबाई हुई मालूम होती थी जिसका कारण केवल वही जानते हैं।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत और इस महानिदेशालय द्वारा पुष्टिकृत आंकड़ों की तुलना में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दृढ़ता से विश्वास किए गए निर्यातों के ब्यौरे भी रिकार्ड में गलत पाए गए थे। किसी अन्य मामले का संदर्भ लिए बगैर चेन्नई पत्तन में बिल प्रविष्टि-वार, पक्षकार-वार हुए आईएसएमएन के आयातों के भारतीय सीमाशुल्क रिकार्ड के मात्र अवलोकन से यह मालूम हुआ कि चीनी निर्यातकों, आयातकों और सीसीसीएमई ने अपने निर्यातों/आयातों के तथ्यात्मक ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं जो किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए गहराई से जांच करने हेतु बहुत आवश्यक हैं। आयातकों की तथाकथित बिना साबित की हुई विरोधी बातें हैं और उन्होंने केवल निर्यातकों और सी सी सी एम ई द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को स्वीकार कर लिया। वस्तुतः मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने उस बात के भी लिखित निवेदन किए जो उन्होंने सुनवाई के दौरान नहीं कही थीं। आयातक इस तथ्य के बावजूद भी कि जो कार्य उन्हें विशेष रूप से करने के लिए कहा गया था, अपने आयातों से संबंधित प्रविष्टि बिल और माल सूचियों सहित उनका कोई संगत ब्यौरा प्रस्तुत नहीं कर सके। उन्होंने सदैव अपना पूरा सहयोग देने का दावा किया परन्तु कार्यस्थल पर उनके सहयोग में कोई वास्तविकता नहीं पाई गई।

सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध सूचना से मालूम होता है कि चीन जनवादी गणराज्य की सरकार ने 1 जुलाई, 1997 से हांगकांग पर राज्यक्षेत्रीय अधिकारों का दावा किया है और प्रभुसत्ता प्राप्त की है। चीन जनवादी गणराज्य की सरकार ने निर्णय भी लिया और हांगकांग को 'एक देश दो प्रणालियां' के सिद्धांत के अन्तर्गत अपने संविधान के

उपबंधों के अनुसार एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया। इसलिए मुझे हांगकांग से निर्यातों को चीन मूल के आयातों में शामिल करने में कुछ गलत मालूम नहीं होता। तथापि, की गई जांच को ध्यान में रखते हुए कि चेन्नई और तुगलकाबाद में सिंगापुर से कोई आयात ध्यान में नहीं आए हैं जिनमें पत्तनवार आंकड़ों के अनुसार 2001-02 के दौरान अधिकांश मात्रा का आयात हुआ था, वर्तमान कार्यवाहियों में सिंगापुर से हुए आयातों को गणना में शामिल नहीं किया गया है।

एक अन्य मुद्दा जिसे विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाया गया है, आवेदक द्वारा घरेलू सूईयों के आयात आंकड़ों में 10% समायोजन के बारे में है। विरोधी पक्षकारों ने दावा किया है कि चीन से हुए कुल 35538.4 कि.ग्रा. के आयात में लगभग 40% घरेलू सूईयां शामिल हैं। इस संबंध में तुलन-पत्रों से यह देखा गया है कि टी.वी.एस. सिर्विंग नीडल्स जो देश में एच.एच.एन का एकमात्र उत्पादक है, का बाजार का हिस्सा 1999-2000 में 59.53 मिलियन से घटकर 2000-01 में 47.50 मिलियन रह गया और 2001-02 में पुनः कम होकर 42.19 मिलियन हो गया जिससे बाजार के हिस्से में लगभग 10% के घाटे का संकेत मिलता है जो चीन द्वारा प्राप्त किया गया मालूम होता है। भारत में चीनी निर्यातक और आयातक जिन्हें अपने निर्यातों/आयातों के बारे में विशिष्ट ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, ने चुप रहने को वरीयता दी। मांगे गए ब्यौरों की अनुपस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना को स्वीकार न करना उचित न होगा।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह मालूम होता है कि डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त 1997-98 से 2000-01 तक अवधि के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़े प्रामाणिक हैं। तथापि, 2001-02 की अवधि के आयात जिन्हें वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया गया था, को अब पत्तनवार आंकड़ों के आधार पर और सीमाशुल्क से किए सत्यापन के आधार पर शुरू कर दिया गया है। मैं मानता हूँ कि निर्यातकों/आयातकों/सीसीसीएमई द्वारा प्रस्तुत कोई प्रतिकूल सूचना न होने से हांगकांग से हुए निर्यातों को चीन मूल के निर्यातों में शामिल किया गया है।

बाजार में व्यवधान का खतरा

निर्यातकों और सीसीसीएमई ने यह मुद्दा उठाया है कि जांच के प्रयोजनार्थ संदर्भ वर्ष को 2000-01 तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए परन्तु वर्तमान जांच के लिए अधिक लम्बी अवधि को शामिल किया जाना चाहिए। इस संबंध में यह अवलोकन किया गया है कि आयातों में वृद्धि पर उस अवधि के लिए विचार किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा जारी दिनांक 26 सितम्बर, 1997 के ट्रेड नोटिस सं०

एसजी/टीएन/1/97 के अधीन जांच शुरू करने से तुरंत पहले के हाल के 3 वर्ष (अथवा अधिक) की अवधि हो जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हों। इसलिए वर्तमान जांच में जांच की अवधि 1997-98 से 2001-02 तक ली गई है जिसके लिए आवेदक द्वारा आंकड़े उपलब्ध कराए गए थे। चाहे इनमें से किसी वर्ष में आयात हुए हों अथवा नहीं, विशेष रूप से असंगत हैं क्योंकि आयातों का मूल्यांकन समस्त अवधि के लिए तुलनात्मक आधार पर करना होता है। यदि किसी वर्ष में कोई आयात नहीं हुए अथवा बहुत कम मात्रा में आयात हुए तो उस वर्ष की इस आधार पर अनदेखी नहीं की जा सकती। समस्त अवधि में आयातों की समग्र वृद्धि पर इस निर्णय पर पहुंचने के लिए विचार किया जाना होता है कि क्या उस अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि हुई है। वर्ष 1997-98 से 2001-02 तक आईएसएमएन के आयात और घरेलू उत्पादन इस प्रकार रहे हैं-

(आंकड़े: मात्रा कि.ग्रा./मूल्य लाख ₹ में)

वर्ष	घरेलू उत्पादन	आयात						घरेलू उत्पाद के % के रूप में चीन से आयात
		चीन		अन्य		जोड़		
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
1997-98	1544	53545	238.64	62925	543.95	116470	782.59	3468%
1998-99	3683	85818	436.09	58912	746.65	144730	1182.74	2330%
1999-00	4755	79403	533.15	88830	911.38	168233	1444.53	1670%
2000-01	4353	29270	190.06	65602	884.95	94872	1075.01	672%
2001-02	5351	99609	219.60	75352	1377.22	174961	1596.82	1860%

भारत में आईएसएमएन का आयात कुछ समय से किया जा रहा था। तथापि, जांच अवधि के दौरान चीन मूल से हो रहे आयातों में 1997-98 में 53545 कि.ग्रा. से वृद्धि होकर 2001-02 में 99609 कि.ग्रा. हो गए। वर्ष 1997-98 से 2000-01 तक की अवधि के चार वर्ष में चीन मूल से आईएसएमएन के औसत आयातों में 62000 कि.ग्रा. की वृद्धि देखी गई जो 2001-02 में 99609 कि.ग्रा. हो गए जिसमें लगभग 60% की वृद्धि हुई। वर्ष 1997-98 से 2001-02 तक की अवधि के दौरान 3584 कि.ग्रा. के औसत घरेलू उत्पादन की प्रतिशत तुलना के रूप में आयात 1730% थे जो 2001-02 में बढ़कर 1860% हो गए। इस प्रकार आयातों में जांच अवधि के दौरान वास्तविक रूप से और घरेलू उत्पादन की तुलना में वृद्धि हुई है।

आईएसएमएन के वर्धित आयातों से आईएसएमएन के घरेलू उत्पादकों के लिए बाजार में व्यवधान उत्पन्न हुआ है/होने का खतरा उत्पन्न हुआ है जिसका संकेत निम्नलिखित कारकों द्वारा दिया गया है:-

(क) कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह बताया गया है कि 2001-02 के दौरान आईएसएमएन के लिए चीन की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग 15 अमरीकी डालर प्रति हजार नग थी । तथापि, इसके समर्थन में इस महानिदेशालय को कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । आईएसएमएन की सीआईएफ कीमत जो 1997-98 में 446 रू० प्रति कि.ग्रा. थी, 1999-2000 में बढ़कर 671 रू० प्रति कि.ग्रा. हो गई थी और 2001-01 में घटकर 649 रू० प्रति कि.ग्रा. रह गई थी तथा उसके बाद पुनः कम होकर 220 रू० प्रति कि.ग्रा. हो गई थी अर्थात् 66% तक कमी हुई जबकि अन्य देशों के मूल से आयातित आईएसएमएन में 97-98 में 1210 रू० प्रति कि.ग्रा. से बढ़ोत्तरी के रूख के कारण यह 2001-02 में 2425 रू० प्रति कि.ग्रा. हो गया । चीन के मूल से आयातित आईएसएमएन की कीमतों में कमी के साथ साम्यता बनाए रखने के लिए और बाजार में अपना हिस्सा कायम रखने हेतु घरेलू उत्पादक को क्रमिक रूप से आईएसएमएन की अपनी कीमतों में कमी करनी पड़ी, उनकी प्राप्ति में पर्याप्त कमी आई और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादक को घाटा हुआ । प्राप्ति जो 1998-99 में 7140 रू० प्रति कि.ग्रा. थी, घटकर 1999-2000 में 5096 रू० प्रति कि.ग्रा. रह गई और 2000-01 में मामूली सा सुधार होकर 5128 रू० प्रति कि.ग्रा. हुई, तत्पश्चात् 2001-02 में पर्याप्त मात्रा में घटकर 3817 रू० प्रति कि.ग्रा. रह गई ।

(ख) घरेलू उत्पादक का क्षमता उपयोग जो 1998-99 में 57% था, घटकर 1999-2000 में 51% रह गया, 2001-01 में बढ़कर 58% हुआ और 2001-02 में 13% की गिरावट आई जो 45% थी । उनके अन्तिम स्टॉक जो मार्च, 2000 की समाप्ति पर 4057 कि.ग्रा.था, मार्च, 2002 की समाप्ति पर बढ़कर 5552 कि.ग्रा. हो गया था ।

(ग) हालांकि आईएसएमएन के घरेलू उत्पादक के बाजार हिस्से सभी देशों से हुए आयातों को ध्यान में रखते हुए 1997-98 में 1.14% से वृद्धि होकर 2000-01 में आईएसएमएन के कुल घरेलू खपत में लगभग 3% हो गया, 2001-02 में घटकर 2.61% रह गयापरन्तु उक्त अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य से हो रहे आयातों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उत्पादक को लगभग 5% बाजार हिस्से का घाटा हुआ जिसे निम्न तालिका में दिखा जाएगा । घरेलू उत्पादक इस घटे हुए बाजार के हिस्से को अपनी बिक्री कीमतों को कम करके ही बनाए रख सके ।

(कि.ग्रा. में)

वर्ष	घरेलू बिक्रियां	सकल घरेलू खपत (चीन जनवादी गणराज्य से आयात और घरेलू बिक्रियां)	घरेलू खपत में घरेलू बिक्रियों का हिस्सा (2/3x 100%)	कुल घरेलू खपत (सभी देशों से आयात और घरेलू बिक्रियां)	घरेलू खपत में घरेलू बिक्रियों का हिस्सा (5/6 x 100%)
1	2	3	4	5	6
1997-98	1348	54893	2.45%	117818	1.14%
1998-99	1621	87439	1.85%	146351	1.11%
1999-00	3549	82952	4.28%	171782	2.07%
2000-01	2836	32106	8.83%	97708	2.90%
2001-02	4703	104312	4.50%	179664	2.61%

जैसाकि ऊपर देखा गया है घरेलू उद्योग को बाजार में व्यवधान/गंभीर क्षति हुई है। तथापि महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या उद्योग को यह घाटा बड़े हुए आयातों के कारण हुआ है अथवा जैसाकि कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा तर्क दिया गया है घरेलू उद्योग पर क्या यह एक सर्वेक्षिक क्षति है।

चीन के निर्यातकों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यदि वस्तुतः आवेदक द्वारा क्षमता को दुगुना करके क्षमता का सृजन किया गया है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि आयातों और क्षति/बाजार के व्यवधान के बीच कारणात्मक संबंध है। वर्तमान जांच में यह जांच की जा रही है कि क्या घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति/बाजार में व्यवधान के खतरे का सामना करना पड़ा है जो उनके 2001-02 के कार्य-निष्पादन के साथ पहले की अवधि के कार्य निष्पादन की तुलना से स्पष्ट है। घरेलू उत्पादकों का मामला यह है कि उन्होंने पहले के वर्षों की तुलना में 2001-02 की तुलना में कार्य निष्पादन में गंभीर रुकावट का सामना करना पड़ा है। चीनी निर्यातकों ने कहा है कि आल्टेक के अलावा आईएसएमएन के विनिर्माता लाभ अर्जित करते रहे हैं और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि महानिदेशक द्वारा इसकी जांच की जाए। टी.वी.एस. की स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया था। यह देखा गया था कि टी.वी.एस नीडल्स लाभ अर्जित कर रहा है परन्तु विनिर्माण कार्यों से इसकी आय घट रही है। प्रचालनों की आय जो 1999-

2000 में 41.81 लाख रु० थी, घटकर 23.12 लाख रु० रह गई थी जो 2001-02 में और घटकर 15.11 लाख रु० हो गई थी। टी.वी.एस नीडल्स की मुख्य आय दिनांक 31.03.02 की स्थिति के अनुसार 302 लाख रु० के उनके निवेश से 'अन्य आय' थी। उनकी 'अन्य आय' जो 1999-2000 में 24.04 लाख रु० थी 2000-01 में बढ़कर 26.81 लाख रु० हो गई थी जो 2001-02 में पुनः बढ़कर 29.75 लाख रु० हो गई थी जो मूल रूप से उनके लाभ का कारण है। अन्य उत्पादकों के संबंध में ऐसा विश्लेषण नहीं किया जा सका क्योंकि उन्होंने जांच प्रारम्भ करने के नोटिस और उन्हें भेजी गई प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया।

यह भी तर्क दिया गया है कि यदि उत्पादन और बिक्रियां स्थिर रहती अथवा बढ़ गई होती तो आयातों के साथ किसी कारणात्मक संबंध का दावा नहीं किया जा सकता है। यह कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं है जिसमें केवल उत्पादनों और बिक्रियों पर ही नहीं परन्तु विभिन्न घटकों के उद्देश्यपरक मूल्यांकन पर क्षति/बाजार में व्यवधान का निर्धारण करने की आवश्यकता होती है। वस्तुतः आयातों और क्षति/बाजार व्योयवधान के बीच कारणात्मक संबंध के विनिश्चय में सीमा शुल्क टैरिफ (संक्रमणकालीन उत्पाद विनिर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क) नियमावली, 2002 के अनुबंध में महानिदेशक के लिए यह अपेक्षा है कि वह किसी उद्देश्य के सभी संगत घटकों और उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव रखने वाले मात्रात्मक स्वरूप विशेषतः संबंधित वस्तु के वास्तविक और तुलनात्मक रूप से आयातों में वृद्धि की दर और मात्रा, बढ़े हुए आयातों द्वारा लिया गया घरेलू बाजार का हिस्सा, बिक्रियों, उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभ और घाटों आदि के स्तर में परिवर्तन का मूल्यांकन करें। इसलिए यदि बढ़े हुए आयात ऐसी स्थिति में आते हैं कि अधिक घरेलू उत्पादन और बिक्रियों के बावजूद आयात बाजार के अधिक हिस्से पर कब्जा करते हैं और घरेलू उद्योग को विस्थापित कर देते हैं तो इस प्रकार हुई क्षति निःसंदेह वर्धित आयातों के कारण मानी जाएगी।

इस मुद्दे का विश्लेषण इसके उचित परिप्रेक्ष्य में किया जाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्धारण के लिए अपरिहार्य है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति आयातों की वृद्धि के कारण अथवा अन्य कारकों के कारण हुई है। मुझे आशंका है कि यह तर्क पूर्णरूपेण भ्रामक है। प्रथमतः कानून में यह अपेक्षा नहीं है कि आयातों में वृद्धि अथवा गंभीर क्षति अथवा बाजार के व्यवधान के निर्धारण के लिए घरेलू उत्पादन में गिरावट अवश्य आनी चाहिए। आयातों में वृद्धि का निष्कर्ष आयातों पर वास्तविकता के साथ-साथ घरेलू उत्पादन की तुलना में विचार करने के बाद निकालना होता है। यदि घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई हो परन्तु यदि आयातों में और तेजी से वृद्धि हो रही हो वर्धित आयात का निष्कर्ष भली-भांति सिद्ध किया जा सकता है क्योंकि आयातों में वास्तविक रूप से और

घरेलू उत्पादन की तुलना में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग को ऐसी स्थिति में रक्षोपाय संरक्षण प्राप्त होगा यदि उससे यह मालूम हो सके कि घरेलू उद्योग को बढ़े हुए आयातों के कारण गंभीर क्षति/बाजार में व्यवधान हुआ है अथवा होने का खतरा है। अन्य शब्दों में गंभीर क्षति/बाजार के व्यवधान के निष्कर्ष के लिए अनिवार्यतः घरेलू उत्पादन में गिरावट आना जरूरी नहीं है।

घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति जो 1997-98 में होनी शुरू हुई थी, ने प्रमुख रूप से वर्ष 2001-02 में स्वयं स्पष्ट कर दिया था। इस अवधि में घरेलू उत्पादक की घरेलू बिक्रियों में मामूली वृद्धि हुई परन्तु वह कम की हुई कीमतों पर अलाभकारी बिक्री करने पर हुई। चूंकि घरेलू उत्पादकों का उत्पादन और बिक्री घटते रहे इसलिए इसका प्रभाव नियत लागत पर हुआ जिससे उत्पादन की लागत बढ़ती रही और लाभ घटते रहे। चीन से कम होती हुई कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रविष्ट हुए आयातों की वृद्धि से घरेलू उत्पादकों को बाजार में गंभीर व्यवधान का खतरा उत्पन्न हुआ क्योंकि उनके पास आईएसएमएन की भारतीय मांग को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं। आयात ऐसी स्थिति में प्रविष्ट हुए हैं कि घरेलू उत्पादन और बिक्री में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद आयातों ने बाजार के अधिक हिस्से पर आधिपत्य ग्रहण किया और घरेलू उत्पादन को विस्थापित कर दिया। निश्चित रूप से यह इस प्रकार पहुंचाई गई क्षति को निःसंदेह चीन मूल से हुए आयातों में वृद्धि के कारण कहा जा सकता है। तथापि, वर्तमान मामले में आल्टेक की बिक्रियों और उत्पादन में थोड़ी वृद्धि हुई परन्तु वह स्पष्ट घरेलू खपत में हुई वृद्धि से बहुत कम थी। उत्पादन और बिक्री में इस वृद्धि को आल्टेक द्वारा अपनी प्राप्तियों में कमी करके ही प्राप्त किया गया था। यह देखा गया है कि आल्टेक को अत्यधिक वित्तीय घाटा हुआ है और अब बी आई एफ आर अधिनियम के अधीन एक संभावित रूग्ण कम्पनी है। आल्टेक को 1999-2000 में 138.76 लाख ₹0 का घाटा हुआ जो 2000-01 में बढ़कर 222.78 लाख ₹0 हो गया था परन्तु 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार इसमें मुख्यतः ब्याज की कम दर वाले कम लागत के विदेशी वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) से घरेलू वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की उनकी पुनः संरचना के कारण कमी हुई।

गुणवत्ता

अल्टेक अंतर्राष्ट्रीय मानक एवं मानदण्ड का आई एस एम एन का विनिर्माण कर रहा है। उनके पास अपने उत्पादन कार्य क्षेत्र में एक अति ठोस गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली है। विनिर्मित आई एस एम एन के प्रत्येक धन का प्रचालन के प्रत्येक चरण में औचक आधार पर निरीक्षण किया जाता है और परिष्कृत उत्पाद का 100% वास्तविक निरीक्षण किया जाता है। उत्पादन की गिनती धानवार की जाती है और प्रत्येक धान के

उत्पादन/अस्वीकृति का ब्यौरा प्रत्येक चरण/प्रचालन में नीडल्स प्रोसेस कार्ड में दर्ज किया जाता है। अंतिम उत्पादन के आंकड़ों को माल सूची के अभिलेखों में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अल्टेक को अपने ठोस गुणवत्ता मानदण्डों के लिए आई एस ओ 9002 प्रमाणन की मान्यता दी गयी है। इसके अलावा, उन्हें गुणवत्ता मानदण्डों को पूरा करने के लिए यू.के. से एसएसटीआरए प्रमाणन से पुरस्कृत किया गया है। ऐसा समझा गया था कि अल्टेक विश्व में ऐसी मान्यता प्राप्त करने वाला सममात्र आईएसएमएन विनिर्माता है। सुईयों को ठोस गुणवत्ता मानदण्डों को पूरा करने के पश्चात् ही उपभोक्ताओं के पास भेजा जाता है।

कुछेक पक्षकारों ने यह दावा किया है कि चीन से आयातित सुईयां अल्टेक द्वारा विनिर्मित सुईयों की अपेक्षा गुणवत्ता में भिन्न हैं, यद्यपि एक हितबद्ध पक्षकार (प्रयोक्ता) ने यह कहा था कि यदि अल्टेक द्वारा विनिर्मित सुईयां कीमतों में प्रतिस्पर्धी हैं तो वह उनकी सुईयां पसंद करेगा। इस बारे में यह देखा गया कि चीन द्वारा उत्पादित एवं निर्यातित आई ए ए एम एन समेत आयातित आई एस एम एन और घरेलू आई एस एम एन दोनों की उसी बाजार में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा है और इनमें उपयोग की समान विशेषताएं हैं। मात्र गुणवत्ता की भिन्नता से कोई उत्पाद समान अथवा प्रत्यक्षरूप से प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादों के दायरे से अलग नहीं हो जाता है।

क्षमता वृद्धि

कुछेक पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा क्षमता में जो वृद्धि की गयी है वह समझदारी का निर्णय नहीं है और उन्हें जो क्षति हुई है वह स्वनिर्मित है। इस बारे में यह उल्लेख किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में अल्टेक ने अपनी क्षमता में वृद्धि की है, उसे देखने की जरूरत है। आवेदक ने कहा है कि वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत के समय उनके एकक की क्षमता 25,714 कि.ग्रा. अथवा 45 मिलियन सुईयां प्रति वर्ष की थी जो दो पाली आधार पर बढ़कर 51,429 कि.ग्रा. अथवा 90 मिलियन प्रति वर्ष की हो गयी थी। इस वृद्धि पर विचार निर्धारित परिसंम्पत्तियों में मामूली वृद्धि करके अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के पश्चात् किया गया था। भवन समेत क्षमता वृद्धि की लागत मात्र 452 लाख रुपए थी, यद्यपि संयंत्र स्थापना की आरंभिक लागत 1585 लाख रुपए की थी। इस प्रकार 100% से अधिक की क्षमता वृद्धि की उपलब्धि इस अतिरिक्त पूंजी व्यय से प्राप्त की जा सकी। क्षमता में जो वृद्धि हुई है उससे प्रत्येक किलोग्राम उत्पादन के लिए निर्धारित ऊपरी खर्चों की लागत में कमी आएगी और आई एस एम एन के विनिर्माता को अस्तित्व में बने रहने और भारतीय बाजार की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए बढ़ती हुई प्रणाली/आकारों की रेंज बनाए रखनी चाहिए। यह उल्लेख किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 1999 के

दौरान 331 आई एस एम एन प्रणालियों/आकारों की अपनी रेंज बढ़ाकर वर्ष 2000 में 357, 2001 में 450 और 2002 में 631 कर दी है। इन प्रगतियों को देखते हुए यह नहीं माना जा सकता है कि अल्टेक ने अपनी क्षमता बढ़ाने में समझदारी का निर्णय नहीं लिया अथवा उनको हुई क्षति स्वनिर्मित है।

कीमत निर्धारण

एक तर्क यह दिया गया है कि कीमत सुरक्षोपाय जांच में विचारार्थ एक संगत कारक नहीं है। इस बारे में यह उल्लेख किया जाता है कि पाटन-रोधी जांच के मामले जिसमें निर्यातक द्वारा अपनाए गए कीमत विभेदकारी तरीके पाटनरोधी कार्रवाई के लिए मूल कारण होते हैं, के विपरीत सुरक्षोपाय जांच के मामले में बढ़े हुए आयात सुरक्षोपाय कार्रवाई करने के लिए मूलभूत अपेक्षा हैं। किस कीमत पर आयात हो रहे हैं, वह संगत कारक नहीं हैं क्योंकि यह एक अनुचित प्रतिस्पर्धा नहीं है जो सुरक्षोपाय कार्रवाई का विषय है, किन्तु बढ़े हुए आयातों से घरेलू उत्पादकों को स्वतः प्रतिस्पर्धा मिली है यद्यपि यह उचित कीमतों पर है। इस संदर्भ में केवल आयात कीमतें संगत नहीं हैं। तथापि, जब बाजार विच्छिन्नता/गंभीर अति अथवा उसके खतरे के निर्धारण की बात आती है तो, कानूनी तौर पर घरेलू उत्पादकों की बिक्रियों, लाभप्रदता इत्यादि में परिवर्तन की जांच की जरूरत पड़ती है। निःसंदेह ये कारक प्रतिस्पर्धी उत्पादों की कीमतों पर निर्भर होते हैं और उस संदर्भ में आयात कीमतें संगत हो जाती हैं और विशेषकर घरेलू स्थिति पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करने की जरूरत पड़ती है।

चेन्नई सीमा शुल्क विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरों से यह देखा गया है कि वर्ष 2001-02 के दौरान 397 रूपए/कि.ग्रा. की दर पर चीन से आयातित मात्रा 1680 कि.ग्रा., लगभग 184 रूपए/कि.ग्रा. की दर पर 4044Q कि.ग्रा., 110 रूपए/कि.ग्रा. की दर पर 16900 कि.ग्रा., लगभग 88 रूपए/कि.ग्रा. की दर पर 26335 कि.ग्रा. थीं। स्वयं इससे कोई व्यक्ति यह अंदाजा लगा सकता है कि चीन से आई एस एम एन की (सीआईएफ) कीमतों में पर्याप्त ह्रास हुआ है, गिरावट 397 रूपए/कि.ग्रा. से 88 रूपए/कि.ग्रा. तक हुई है अर्थात् यह गिरावट वर्ष 2001-02 के दौरान लगभग 78% तक हुई है। इससे घरेलू उत्पादक द्वारा कीमतों में कमी करनी पड़ी। यह उल्लेख किया जाता है कि राष्ट्रीय कीमतों में जो गिरावट आई है वह बाजार विच्छिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और इसके फलस्वरूप घरेलू उत्पादक को क्षति हुई है। यद्यपि घरेलू उत्पादक के लिए क्षमता उत्पादन एवं उपयोग में बेहतर क्षमताएं प्राप्त करना संभव हो सकता है तथापि सर्वाधिक निर्णायक एवं महत्वपूर्ण पहले वह कीमत है जो वह अपने उत्पाद के लिए वसूल अथवा प्राप्त करने में सक्षम है। कीमतों में गिरावट

के फलस्वरूप निश्चित रूप से घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में घाटा हुआ है और उनकी लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ा है।

अंत में यह उल्लेख किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान आयातों में असाधारण वृद्धि हुई है। इन बड़े हुए आयातों से खपत में उत्तरोत्तर काफी वृद्धि हुई है जो वर्ष 1997-98 में 54893 से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 104312 हो गई थी। इन बड़े हुए आयातों के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है/बाजार विच्छिन्न हुआ है। जहां तक वर्तमान जांच का संबंध है, घरेलू उद्योग की स्थिति पर बड़े हुए आयातों से भिन्न किसी अन्य कारक का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव प्रतीत नहीं होता है।

घरेलू उत्पादकों की अक्षमता

एक मुद्दा यह उठाया गया है कि आई एस एम एन के घरेलू उत्पादक दक्षतापूर्वक प्रचालन नहीं कर रहे हैं और उत्पादन की उनकी प्रचालन की संख्या विदेशी विनिर्माताओं खासकर चीनी विनिर्माताओं की तुलना में काफी अधिक है। चीनी निर्यातकों ने अपने लिखित उत्तर में यह कहा है कि आल्टेक का यह दावा कि आई एस एम एन के विनिर्माण में लगभग 100 चरण हैं, के विपरीत उनके पास केवल 16 चरण हैं (यद्यपि उन्होंने यह उल्लेख किया था कि सुनवाई के दौरान 27 चरण थे)। इसकी जांच की गयी थी और यह समझा गया था कि आई एस एम एन जो एक सूक्ष्म इंजीनियरी का उत्पाद है, के विनिर्माण की उत्पादन कार्य प्रणाली में प्रसंस्करण के अगले चरण के लिए आई एस एम एन को तैयार करने के लिए मध्यवर्ती प्रचालनों जैसे विन्यास, सफाई, ग्रीस सहित, तेल रहित बनाने इत्यादि समेत लगभग 100 प्रचालन शामिल हैं, प्रणाली का अनुकरण विश्व के सभी विनिर्माता करते हैं। तथापि, यह सत्यापित किया गया था कि आल्टेक द्वारा आई एस एम एन का विनिर्माण करने के लिए 15 प्रमुख प्रचालनों का इस्तेमाल किया जा रहा था अर्थात् बण्डल बांधना काटना और गोल करना, दागना और सीधा करना, कैमिकल डेबरिंग और पालिश करना, चदर लगाना और सुईयों का वास्तविक निरीक्षण करना और उनकी अंतिम पैकिंग करना।

योजना की पुनर्संरचना

विरोधी पक्षकारों द्वारा यह कहा गया है कि आवेदक की समायोजन योजना पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उत्पादकों ने आई एस एम एन के विनिर्माण के लिए अपनी कच्ची सामग्रियों, विशेषकर स्टील की तार की खरीद प्रतिस्पर्धात्मक रूप से घरेलू स्रोतों से नहीं की है और आयातित इस्पात को अधिक पसंद किया है जो घरेलू इस्पात की अपेक्षा काफी महंगा है और इसीलिए यह उनको हुई क्षति का एक कारण है। यद्यपि नियमों में घरेलू उद्योग

द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली योजना की पुनर्संरचना किए जाने की कोई परिकल्पना नहीं की गयी है तथापि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी समायोजन योजना काल्पनिक अथवा शैक्षणिक नहीं है। अपनी उत्पादन लागत कम करने के एक प्रयास के रूप में प्रस्तुत उनकी पुनर्संरचना योजनाओं की जांच इस महानिदेशालय द्वारा की गई। वे प्रतिस्पर्धी बनने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास कर रहे हैं ताकि विशेष रूप से चीन से हुए आयातों से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा का सामना किया जा सके। यह समझा जाता है कि रक्षोपाय शुल्क लगाने से पुनर्संरचना करने और प्रतिस्पर्धी बनने में उन्हें मदद नहीं मिलेगी। यह भी उल्लेख किया जाता है कि घरेलू उत्पादकों द्वारा इस दिशा में पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और घरेलू उद्योग को अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए लगभग तीन वर्षों की एक अवधि की जरूरत पड़ेगी, यद्यपि उन्होंने चार वर्षों की एक अवधि का दावा किया है।

अत्यधिक आयातों के कारण क्षति

विभिन्न पक्षकारों द्वारा अनेक मुद्दे उठाए गए हैं जिनमें उन्होंने अत्यधिक आयातों को न्यायोचित बताया है अथवा यह प्रदर्शित किया है कि घरेलू उद्योग को जो क्षति हुई है वह अत्यधिक आयातों के कारण नहीं बल्कि अन्य कारकों से हुई है। इन मुद्दों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा आपूर्ति-मांग के बीच अंतर का है। कुछेक पक्षकारों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण अत्यधिक आयात नहीं था क्योंकि आयात करना घरेलू आपूर्ति एवं घरेलू मांग के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए आवश्यक था। इस पहलू की जांच की गयी है और यह उल्लेख किया गया है कि अल्टेक ने वर्ष 1997 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था और उसकी स्थापित क्षमता 45 मिलियन सुईयां प्रति वर्ष तथा संयंत्र और मशीनरी में कुल निवेश 1223.85 लाख रूपए का था। अल्टेक ने वर्ष 2000 में अपनी क्षमता 45 मिलियन से बढ़ाकर 90 मिलियन तक कर दी थी। इस वृद्धि की कुल लागत लगभग 325.26 रूपए थी जो संयंत्र और मशीनरी की मूल लागत का केवल 28% है, जबकि क्षमता 100% तक बढ़ गयी है। यह वृद्धि मुख्यतः एक निश्चित अवधि में आई एस एम एन की उत्पादन लागत कम करने के लिए की गयी थी। प्रबंधन से यह समझा गया था कि यह वृद्धि उनकी वित्तीय पुनर्संरचना योजना का एक हिस्सा था। कम्पनी ने भारतीय वित्तीय संस्थानों/बैंकों से मियादी ऋण और कार्यशील पूंजी उधार ली थी जिस पर ब्याज दर लगभग 18% थी जिसका प्रतिस्थापन निम्न लागत बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) द्वारा किया गया था जिस पर ब्याज की दर केवल 7.5% थी। यह सत्यापित किया गया था कि उनके पास पर्याप्त बुनियादी अवसंरचना सुविधा, स्थापित कतिपय संवेदनशील मशीनरी के अलावा पर्याप्त क्षमता रेटिंग वाली पेटेंट की गयी मशीनरी की आपूर्ति के लिए अपने सहयोगियों के साथ संविदाएं भी हैं और उनके पास विभिन्न विशिष्टताओं

एवं प्रणालियों के आई एस एम एन की लगभग 2,00,000 कि.ग्रा. प्रति वर्ष की मात्रा का विनिर्माण करने और इसे बढ़ाने की संभाव्यता है। इसके अलावा, आवेदक ने देश में आई एस एम एन के आयातों का विरोध नहीं किया है। उसने चीन मूल के आयातों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनने के लिए जो मांग की है वह केवल चार वर्ष के लिए एक समान अवसर वाला कार्य क्षेत्र है।

निर्यातों के घाटे के कारण क्षति

विरोधी पक्षकारों द्वारा यह भी दावा किया गया है कि घरेलू उत्पादक के दुःखों का कारण इसके निर्यात बाजार का घाटा है जो वर्ष 2001-02 में घटकर 17988 कि.ग्रा. हो गया है जब वर्ष 2000-01 में यह 25363 कि.ग्रा. था और न कि आई एस एम एन का आयात विशेषकर चीन मूल का आयात। इस बारे में यह बात दिमांग में रखनी महत्वपूर्ण है कि आई एस एम एन के उत्पादन के लिए उत्पादन प्रणाली घरेलू खपत और निर्यात बाजार दोनों के लिए एक समान है। एक घरेलू उद्योग जो घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सक्षम नहीं था, से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की आशा नहीं की जा सकती है, विशेषकर जब घरेलू उद्योग के लिए घरेलू आपूर्तिकर्ता मुख्य संभावित बाजार हों और निर्यात गौण बाजार हो। निर्यात के क्षेत्र में भी, आवेदक को भारत में आई एस एम एन के उन उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी जो ई ओ यू स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करते हुए अनन्य रूप से निर्यातों की पूर्ति कर रहे थे। आवेदक ने निर्यात बाजार में जोखिम लेने के कारण स्पष्ट करते हुए यह कहा है कि संयंत्र में किए आबद्ध निवेश के आलोक में और उत्पादन लागत में कमी करने के लिए अपनी क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया को जारी रखना था।

रिश्त के आरोप

यह उल्लेख किया गया है कि चीन वाणिज्य मण्डल ने चीन मूल के आई एस एम एन के आयातों के खिलाफ रक्षोपाय कार्रवाई के लिए अपने अनुरोध को वापस लेने पर विचार करने के लिए आवेदक के खिलाफ भारी रकम की मांग किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि उक्त आरोप न तो सुनवाई के दौरान और न ही अपने लिखित निवेदनों में लगाया गया है लेकिन प्रथम बार दायर किए गए खण्डनों में लगाया गया है जिसका उत्तर देने के लिए प्राधिकारी के पास कोई अवसर नहीं था। आवेदक के घर पर चीनी मण्डल के साथ जो बैठक हुई थी वह इस महानिदेशालय के अनुरोध पर नहीं की गयी थी और दो पक्षकारों के बीच हुई निजी वार्ता का वर्तमान कार्यवाही से कोई संगति नहीं है।

अनंतिम सुरक्षोपाय

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जांच पूरी करने के पश्चात् इस मामले में अंतिम जांच परिणाम जारी किए जा रहे हैं, अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाने के प्रयोजनार्थ कोई प्रारंभिक जांच परिणाम दर्ज करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है।

सार्वजनिक हित

यह तर्क दिया गया है कि आवेदक का बाजार हिस्सा भारत में आई एस एम एन के कुल खपत का केवल 2-3% है और चीन मूल के आई एस एम एन पर रक्षोपाय शुल्क लगाना जनहित में नहीं होगा। यह दावा इस आधार पर किया गया है कि रक्षोपाय शुल्क लगाने से आयातित आई एस एम एन आयातकों/प्रयोक्ताओं के हाथों में अधिक महंगा हो जाएगा जिसके फलस्वरूप परिणामी उत्पादों की लागत बढ़ जाएगी। यह दावा किया गया है कि आई एस एम एन पर रक्षोपाय शुल्क लगाने से यह अधिक महंगा हो जाएगा और यह उपभोक्ता के हितों के विरुद्ध होगा। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक ने अपने जर्मन सहयोगी को लाभ पहुंचाने के लिए रक्षोपाय शुल्क के संरक्षण की मांग की है। यह सत्यापित किया गया है आल्टेक के प्रबंधन पर अनन्य रूप से नियंत्रण भारतीय प्रवर्तकों का रहता है और आल्टेक में जर्मनी का कोई भी अधिकारी किसी कार्यकारी पद पर आसीन नहीं है। इसके अलावा, विरोधी पक्षकारों द्वारा मेरे समक्ष कोई मूल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और मैं किए गए दावे में कोई विशेषता नहीं देखता हूँ।

यह तर्क दिया गया है कि रक्षोपाय शुल्क लगाने की स्थिति में आवेदक लाभ की स्थिति में होगा और वह घरेलू बाजार का शोषण करेगा जिससे एकाधिकार की स्थिति पैदा हो सकती है। अनियंत्रित आयातों के आलोक में और इससे भी अधिक जब 1997-98 से 2001-02 की अवधि के दौरान चीन से हुए आयात घरेलू खपत के प्रमुख हिस्से के लिए परिकलित किए जाते हैं तो, यह पूर्वानुमान सही प्रतीत नहीं होते हैं। कानून में भी यह परिकल्पना नहीं की गयी है कि किसी एक उत्पादक के हित की रक्षा नहीं की जानी चाहिए भले ही वह रक्षा किए जाने का सही पात्र ही क्यों न हो। रक्षोपाय शुल्क लगाने का उद्देश्य एकाधिकार प्रथाओं को प्रोत्साहित करना नहीं है बल्कि यदि अत्यधिक आयातों से उनके लिए बाजार विच्छिन्नता होती है अथवा इसके होने का खतरा उत्पन्न होता है तो घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा करना है ताकि अत्यधिक आयातों से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए उन्हें समय दिया जा सके।

इस बारे में यह भी उल्लेख किया जाता है कि जन हित शब्द को केवल उपभोक्ता के हित को शामिल करने तक सीमित नहीं किया जाता है। यह एक अतिव्यापक शब्द है जिसके दायरे में विशाल समुदाय के हित को हिसाब में लेते हुए

सामान्य सामाजिक कल्याण शामिल हैं। यद्यपि रक्षोपाय शुल्क लगाने के फलस्वरूप क्रेताओं के हाथों में आयातित आई/एस एम एन की लागत में वृद्धि हो सकती है और इसलिए इससे विनिर्मित अंतिम उत्पादों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है तथापि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के उद्देश्य को ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। रक्षोपाय शुल्क लगाने का प्रयोजन घरेलू उद्योग को एक ऐसी समयावधि प्रदान करना है जिसके भीतर वह अत्यधिक आयातों से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा की नई स्थिति का सामना करने के लिए सकारात्मक समायोजन कर सके। रक्षोपाय शुल्क लगाने से क्रेताओं को अपनी अपेक्षाएं प्राप्त करने में न केवल व्यापक विकल्प बल्कि प्रतिस्पर्धी कीमत भी उपलब्ध होंगी। घरेलू उत्पादक असंख्य लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और अर्थव्यवस्था में बहुमूल्य योगदान देते हैं। इस प्रकार, रक्षोपाय शुल्क लगाने से वे ऐसे आयातों से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा की स्थिति में अपने अस्तित्व को बनाए रख सकेंगे जो आई एस एम एन के क्रेताओं और उससे विनिर्मित उत्पादों के उपभोक्ताओं के दीर्घकालिक हित में होने चाहिए। इस बारे में यह उल्लेख किया जाता है कि रक्षोपाय शुल्क लगाने से प्रयोक्ता उद्योग और खासकर इसके उपभोक्ताओं पर किसी महत्वपूर्ण प्रभाव के पड़ने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि रक्षोपाय शुल्क आई एस एम एन के घरेलू उत्पादकों की रक्षा करने के लिए केवल आवश्यक सीमा तक लगाए जाने का प्रस्ताव है। अतः यह समझा गया है कि चीन मूल के आई एस एम एन पर रक्षोपाय शुल्क लगाना सामान्य जनहित में होगा।

निष्कर्ष

उपयुक्त जांच परिणामों को देखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि भारत में चीन जनवादी गणराज्य मूल के आई एस एम एन के अत्यधिक आयातों से घरेलू उत्पादकों के लिए बाजार विच्छिन्न हुआ है जिससे उन्हें वास्तविक क्षति हुई है और तीन वर्षों की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाना जनहित में होगा।

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने भी यह आग्रह किया है आवेदक द्वारा रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की जो मांग की गई है वह अपने किए गए दावे की उत्तरजीविता अथवा नुकसानरहित कीमत जो कथित चीनी मूल से भिन्न आई एस एम एन की औसत कीमत से भी काफी अधिक है, पर आधारित है जो एक विशिष्ट रक्षोपाय जांच के विपरीत है। दावा किया गया अधिकतम रक्षोपाय शुल्क आई एस एम एन की न कि चीनी मूल की आई एस एम एन की औसत आयात कीमत पर आधारित उच्चतम हो सकता है। इस पर विचार किया गया है और रक्षोपाय शुल्क की केवल उस राशि, जिसे यदि लगाया गया तो, की सिफारिश की जा रही है जो बाजार विच्छिन्नता को रोकने अथवा उसका निराकरण करने के लिए पर्याप्त होगा।

रक्षोपाय शुल्क की उस मात्रा का निर्धारण करते समय स्वदेश में उत्पादित आई एस एम एन की उत्पादन लागत (गोपनीय) को उनके ईष्टतम क्षमता उपयोग और लागत कम करने के प्रयासों के आधार पर ली गयी है। यद्यपि आवेदक द्वारा उच्च लाभ मार्जिन का दावा किया गया था तथापि उचित लाभ मार्जिन की अनुमति दी गयी है। इसी प्रकार, चीन मूल के आई एस एम एन की सी आई एफ आयात कीमतें भी 1997-98 से 2001-02 की अवधि के दौरान अधिमानी औसत के आधार पर ली गयी हैं। स्वदेश में उत्पादित और आयातित दोनों आई एस एम एन के लिए यथा लागू शुल्कों, करों और प्रहस्तन प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं। तथापि, आयातों पर 4% विशेष अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने वाले प्रावधान को देखते हुए, स्वदेश में उत्पादित आई एस एम एन पर भुगतान किए गए बिक्री कर अथवा अन्य स्थानीय करों जिसमें बिक्री कर और अन्य स्थानीय कर इत्यादि जिन्हें आमतौर पर स्वदेश में उत्पादित माल पर लगाया जाता है, के लिए कोई समायोजन नहीं किया गया है। रक्षोपाय शुल्क का परिकलन इस महानिदेशालय और सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए कतिपय सत्यापनों के आधार पर प्रति सूई परिवर्तित और परिकलित मात्रा पर आई एस एम एन के प्रति कि.ग्रा. पर किया गया है।

सिफारिशें

यह सिफारिश की जाती है कि भारत में आई एस एम एन के उक्त आयातों द्वारा हुए बाजार में हुई विविधता के खतरे से घरेलू उद्योग की रक्षा करने के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए जो न्यूनतम आवश्यक है, भारत में चीन के मूल के आई एस एम एन के आयातों पर प्रति सूई 1.50 रूपए (एक रूपए पचास पैसे मात्र) की दर से एक विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क लगाया जाए।

[फा. सं. एस.एस.जी./आई एन वी/1/2002]
बी. के. मिश्रा, महानिदेशक

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL

(Specific Safeguards)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2003

Subject:—Safeguard Duty investigation against imports of Industrial Sewing Machine Needles (ISMN) into India under Rule 5 of the Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002 (hereinafter referred to as the SSGD Rules) read with Section 8C of the Customs Tariff Act, 1975—final findings.

G.S.R. 359(E).—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Transitional Product Specific safeguard Duty) Rules, 2002 thereof:

A. PROCEDURE

The Notice of initiation of specific safeguard duty investigation concerning imports of ISMN into India was issued on 13.08.2002 and was published in the Gazette of India, Extraordinary on 29.08.2002. A copy of the Notice alongwith copy of Application and a questionnaire was sent to all known interested parties to make their views known by 23rd September 2002 namely:-

Domestic Producers

- (i) Altek Lammertz Needles Limited, Tamil Nadu
- (ii) TVS Needles Limited, Tamil Nadu
- (iii) Schmetz (I) Pvt Limited, Mumbai
- (iv) Groz-Beckert Asia Limited, Chandigarh

Exporters

- (i) Gros Beckert AG, Germany
- (ii) Ferd. Schmetz gmbh, Germany.
- (iii) Organ Needle Co. Ltd, Japan.
- (iv) K.O. Needle Co. Ltd, Korea.
- (v) Guangdong Sundehuanan Sewing Needles co. Ltd. China
- (vi) Quidong Sewing Machine Needle Factory, China
- (vii) Haimen City Dong Cheng Needles Factory, China.
- (viii) Dotec Needles Co Ltd, Taiwan
- (ix) Triumph Needle Corporation, Chinese Taipei

Importers/ User Industry:

- (i) Groz-Beckert Asia Pvt Ltd, Chandigarh
- (ii) Schmetz India Pvt Ltd, Mumbai
- (iii) Madura Coats Ltd Bangalore
- (iv) Ashwini Intercontinental, Bangalore
- (v) N. Jugraj & Co. Chennai*
- (vi) Sanjay Trading Company, Calcutta
- (vii) Kalpana Enterprises, Chennai **
- (viii) Sagar Overseas, Chennai
- (ix) Gokuldas India Limited, Bangalore
- (x) Orient Fashions, New Delhi
- (xi) Dashmesh Embroidery, New Delhi
- (xii) Bata India Limited, West Bengal

* Returned undelivered by postal authorities

** Returned by one M/s Manoj Enterprises operating from the same premises

Association :

Industrial Sewing Machine Dealers' Association, Chennai

2. A copy of the notice of initiation alongwith the application and questionnaire was also sent to the governments of exporting countries through their High Commissions/Embassies in New Delhi namely Peoples' Republic of China, Japan, Germany. Korea RP, Singapore and Taiwan. A copy of the notice of initiation was also sent to the Delegation of European Union in India, New Delhi.

3. Replies to the Notice dated 13.08.2002 and to the questionnaire were received from the following parties:-

Domestic Producers

- (i) Altek Lammertz Needles Limited, Tamil Nadu
- (ii) TVS Sewing Needles Limited, Tamil Nadu
- (iii) Schmetz (I) Pvt Limited, Mumbai

Exporters

- (i) Replies have been filed through Counsel under instructions of China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronics Products(CCCME) reportedly a representative Association of Chinese Exporters & on behalf of Nantong White Crane Needles Co Ltd and Nantong Huating Needles Making Co. Ltd ,China.
- (ii) Organ Needle Co. Ltd, Japan
- (iii) K.O.Needles Co. Ltd., Republic of Korea
- (iv) Ferd. Schmetz GMBH, Germany

Replies have also been filed by the following interested parties who are either users or importers which were taken on record.

- (i) Rohan Apparels Pvt. Ltd, New Delhi
- (ii) Shivam Creation, New Delhi
- (iii) Sakshi Enterprises , Noida, U.P.
- (iv) J.B. Fashion, New Delhi
- (v) J.G. Impex Private Limited, New Delhi
- (vi) Dilip Readymades, Chennai
- (vii) Vijay Cloth Company, Chennai
- (viii) Haneefa Leather Mfg.Co., Chennai
- (ix) Rajendra Garments, Chennai

4. Verification of the information considered necessary for the investigation was done and to this end a team of officers visited the premises of the applicant domestic producer and M/s. TVS Sewing Needles Ltd., Madurai. The outcome of the investigations was conveyed to the applicant domestic producer and a copy of the verification report was also placed in Public File.

5. A Public Hearing was given to all interested parties on 25th February, 2003, notice for which was sent on 28.01.2003. During the Public Hearing the interested parties were requested to file their written submission of oral arguments made by them by 6th March 2003, collect replies filed by others on 7th March, 2003 and to file rebuttals , if any, by 13th March, 2003. During the Public Hearing the Director General desired the Exporters and Importers to furnish details of exports/imports effected by them during the last three years along with relevant details namely name of the exporter/ importer, quantity and value of ISMN exported/ imported along with copies of Shipping Bills, Invoices and Bill of Entries for his perusal. The importers were also asked in addition details of prices at which the goods were being imported and at what prices they were selling in turn to their customers. Further the Director General requested the China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronics Products(CCCME) to furnish details of all Chinese manufacturers of ISMN along with authenticated figures of their exports to India.

The following parties attended the Public Hearing:

- (i) Altek Lammertz Needles Limited,Tamil Nadu
- (ii) Schmetz (I) Pvt Limited, Mumbai (through consultant)
- (iii) China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronics Products(CCCME)

- (iv) Ministry of Foreign Trade & Economic Co-operation (MOFTEC), China
- (v) Embassy of Peoples' Republic of China, New Delhi
- (vi) Nantong White Crane Needles Co Ltd China and Nantong Huating Needles Making Co. Ltd, China. (through Counsel)
- (vii) Dillip Readymades, Chennai
- (viii) J.G. Impex (P) Ltd., New Delhi
- (ix) Pleasant Trading Pvt. Ltd/ Impex Syndicate, New Delhi

B. Views of domestic producers/Domestic Industry

(I) TVS Sewing Needles Limited, Tamil Nadu

They are a major producer of domestic sewing machine needles with a production capacity of 75 Million needles (domestic & industrial). Their ISMN sales is less than 1% of their production. Their sales as a % of total sales was as under:

Details	Quantity in numbers			
	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03 Aug)
ISMN sales	272100	248433	263350	24900
% of total sales	0.46	0.52	0.62	0.22

(II) Schmetz (I) Pvt Limited, Mumbai

The Chinese international market price is about US \$15 per thousand pieces and their potential is about 500 million pieces. Altek earlier filed a petition seeking imposition of anti-dumping duty on higher priced needles which on investigation was rejected by the government of India. Altek claims that they produce 95% of domestic production of ISMN which translates to only 2% market share in Indian domestic consumption. The weight of the needle is about 2 grammes per piece and the price is normally quoted on a unit of 1000 pcs. Converting to weight basis for products like needles for the purpose of statistical evaluation cannot be relied upon as the packing materials vary from needle to needle, producer to producer and will skew the conclusion.

(iii) Altek Lammertz Needles Ltd.(Altek), Chennai

(a) Historically, Needles were manufactured mostly in Germany, Japan and Korea. India always imported the needles from these countries. Garment making in US and Europe became too expensive and the industry shifted to Asian region. Therefore, demand for needles shifted to Asian countries like India. China concentrated on India as a potential market and resorted to flooding India with their product which has completely disrupted the market throwing it out of gear.

(b) They set up a plant to manufacture Industrial Sewing Machine Needles with German technology. The company commenced commercial production in the year 1997 with an installed capacity of 45 million needles per annum. The project was

appraised and funded by ICICI to the extent of Rs 400 lakhs out of the total project cost of Rs 1200 lakhs. Out of the balance a sum of Rs 48 lakhs came in as ECIP loan and the balance was funded by way of equity. Altek successfully absorbed the technology and started producing Industrial Sewing Machine Needles of International quality. At the time of project appraisal the needles were by and large imported from Germany, Japan and Korea. Even though China was also exporting, its share in market was restricted to the unorganized segment of garment industry. The Capacity of their unit at the time of commencement of commercial production was 25,714 kgs or 45 million needles per annum which was increased to 51,429 kgs or 90 million per annum on two shift basis. The expansion was made mainly for the following reasons:

(i) As the infrastructure such as land, power was already established, the additional capacity could be created with a very nominal addition to the fixed assets. The cost of expansion including building was only Rs. 452 lakhs while the initial cost of setting up the plant was Rs 1585 lakhs. Thus expansion of more than 100% could be achieved with this additional capital expenditure.

(ii) The increase in the capacity would bring down the cost of fixed overheads for every kg of production.

(iii) Finally to cater to the growing Indian market for ISMN which increased from 117,818 kgs in 1997-98, to 186,612 kgs in 2001-02.

(c) The domestic cost of production during the last three years was as under.

Year	Cost per kg
99-2000	6,296
2000-01	5,772
2001-02	3,991

(d) The Peoples' Republic of China increased its exports to India dramatically in absolute terms as would be evident from the following table. The exports which was 53,545 kgs in the year 1997-98 increased to 85,818 kgs in 98-99, declining marginally in 1999-2000 vis-à-vis 1998-99 and declining further in 2000-01 to 29,270 kgs, mainly due to imposition of Anti Dumping duties on imports from China which was subsequently withdrawn, shot upto 1,04,216 kgs in 2001-02. While the imports in general from other countries declined from 67% in 2000-01 to 42% in 2001-02 imports emanating from China registered a phenomenal increase from 30% to 56% of the market share during the same period. The rate of increase during the five year period is more than 15% compounded or nearly twice in quantitative terms.

Year	China		India		Others		Total
	Qty (kgs)	% share	Qty (kgs)	% share	Qty (kgs)	% share	
1997-98	53,545	45%	1,348	1%	62,925	53%	117,818
1998-99	85,818	59%	1,621	1%	58,912	40%	146,351
99-2000	79,403	46%	3,549	2%	88,830	52%	171,782
2000-01	29,270	30%	2,836	3%	65,602	67%	97,708
2001-02	104,216	56%	4,631	2%	77,785	42%	186,612

(e) Their share has stagnated in percentage terms due to market disruption caused exclusively by the unabated imports from China. In absolute terms also their sale did not increase corresponding to the increase in the domestic consumption. Their market share which was 3% in 2000-01 reduced to 2% in 2001-02, registering a 33% decline. They increased their capacity from 25,714 Kgs in 1997 to 51,429 kgs on 2-shift basis in the year 2000 to cater to the increasing Indian demand and to export semi-finished needles to stay competitive by bringing down cost vis-à-vis imports. But, production for Indian market stagnated during the entire period under review in the range of 4,000 - 6,000 kgs due to flood of imports from China.

(f) Due to low capacity utilisation caused by large imports, the company was not able to achieve efficiency in operations, optimise plant utilisation, reduce cost of production through higher volumes which resulted in number of their key trained personnel leaving for better pastures.

(g) Their capacity utilisation for Indian market declined from 14% in 98-99 to just 10% during the year 2001-2002. The total capacity utilisation (including for exports) has also declined from 57% in 98-99 to 45% in 2001-2002.

(h) They suffered huge financial loss and they are now a potentially sick company under the BIFR Act due to market disruption caused by Chinese imports. Besides surge in imports from China at depressed prices, the exporters from China are also extending credit facilities and enormous quantitative/cash discounts which has forced them to reduce their prices affecting the realisation. For example, the price of DB*1 system- the largest selling needle - has been reduced from Rs 2.95 (inclusive of taxes) to Rs 2.50 per needle in January 2002. Additionally, increases in Sales Tax ranging from 4-5% all over the country has been absorbed by the company. ICICI, who had appraised their project and granted term loans, has estimated that the realisation for the Indian market will be Rs 7,000 per kg on the basis of situation that existed at that time. But, due to price depression and surge in quantity of imports from China, realisation has not exceeded even Rs 2,750 per kg. If the safeguard duty sought for is imposed, they will be able to marginally reduce their prices to stay competitive with the Chinese needles, which they will be able to make up through increased capacity utilisation, which at present is very low.

(i) Their liquidity position suffered causing huge stocks (10 to 12 months sales), large debtors (5 to 7 months) leading to uneconomic operations and lower realisations.

(j) The cost of imports of needles from China which was Rs 671/- per kg in 1999-2000 declined to Rs 649 in 2000-01 and gained marginally to Rs 669 in 2001-02 as compared to the import prices (c.i.f.) of countries other than China which increased from Rs.1,026 in 1999-2000 to Rs 1,732 in 2001-02 which reflects market disruption caused by unabated imports from China. Though the quantity of imports increased from China as well as other countries, the price (c.i.f.) from China did not increase correspondingly as would be evident from the following table.

Year	Imports from China - qty	CIF Price per kg in Rs.		
		Cost of imports From China	Imports from Others -qty	Cost of imports - Others
1997-98	53,545	446	62,925	864
1998-99	85,818	508	58,912	1,267
1999-2000	79,403	671	88,830	1,026
2000-01	29,270	649	65,602	1,349
2001-02	104,216	669	77,765	1,732

(k) It would be evident that the market disruption is directly attributable to surge in imports of needles from China. The injury has been caused by increased imports in general but got aggravated by increased imports from China. Increased discounts and credit terms by exporters from China compelled them to resort to offering higher discounts and commissions, to retain the customer base and to continue their manufacturing operations which had its own impact on their liquidity position.

(l) The dedicated investment made by them prevented them from either closing down the unit or curtailing the production and they were forced to run the unit at uneconomical levels by exporting semi-finished needles.

(m) Specific safeguard duty on ISMN be imposed on imports from China for a period of four years, besides an interim safeguard duty (provisional) which will be in Public Interest and will result in the domestic market opening for quality needles originating from their company and from Germany, Japan etc. which will give better value for the domestic consumers.

(n) Altek to make its needle prices more competitive envisaged a restructuring plan. As part of the plan it raised low cost ECB loan and closed all its term liabilities with Indian Financial Institution cost of which was comparatively very high. Part of the ECB loan remains unutilized which is meant for the unexecuted expansion programme.

(o) At present they are importing needle wire, which is the main raw material from Germany. Needle wire is a high carbon steel wire with 1% carbon content. There are only 4 or 5 manufacturers in the world who supply this needle wire to the entire needle industry. Due to exchange rate, customs duty, freight, high inventory level due to lead time in imports, the cost of wire is high. They have already studied the potential of sourcing this needle wire in India. In this direction they have made an arrangement with M/s Gujarat Wire Industries for manufacturing needle wire. With their guidance and expertise, this company has been successful in producing needle wire of good quality. Of course their output was very low. Further needle wire of different thickness are required depending upon the system and size of the needle. The needle wire thickness varies between 1.63 mm to 2.02 mm. This company has been successful in producing needle wire for a particular system alone. Wire drawing, which is the basic process in manufacturing needle wire is a high precision engineering as the quality specifications are very stringent. The quality of the wire must stabilize particularly when the volume increases and they must be in a position to produce wire of different dia. The unit must also be assured of certain minimum off take to enable them to invest in their plant to increase their production. It is expected that in about three years, this unit will be in position to supply about 40% of Altek's requirements. Even though the entire requirements of Altek cannot be sourced from this unit, this 40% indigenous source will reduce their raw material cost considerably.

(p) Dies are very critical and essential tools for manufacturing of ISMN. Dies form part of the patented technology and is a closely guarded secret. Altek has set up its own tool room and has done extensive study and trials in making dies. The company's engineers have undergone extensive training in Germany. With all these efforts, they have been successful in making the first set of dies. As there are a wide range of systems and sizes of needles, attempts are being made by them on different systems/sizes. Considering the wide range of dies to be made, it is expected that Altek will make the entire dies in-house in about five years.

(q) Milling cutter is another critical tool, which is being imported by them from Germany. Even though the cost of the milling cutter in the end product is very low, high import cost, cost of inventory contributes considerably. Altek has made extensive study on the art of making cutters, which has been quite successful. The imported milling cutter costs Rs 300 per piece, whereas the indigenous one would cost about Rs 160 only.

(r) Stabiliser is a chemical used in deburring operation, which makes the needle surface smooth and free of burrs. A German company holds the proprietary for this chemical, who supply to the entire needle industry. Altek approached the Central Institute of Scientific and Industrial Research, Govt. of India, seeking their assistance in producing this chemical indigenously. Altek has entered into an agreement with this agency and the trials are under way. The cost of this chemical consumed by Altek would come down considerably if sourced indigenously.

(s) Altek has spent huge amounts on sales promotion and advertisements to increase its domestic sales. This has helped Altek in creating a brand image in the

domestic market. In terms of quality Altek's needles are considered on par with those of Germany, Japan and Korea. With this initial brand image and increased domestic sales, Altek's selling expenses would come down reasonably.

(t) As part of financial restructuring, Altek has already repaid its term liabilities with Financial Institutions, which was costing as high as 16% to 18%. This has been repaid out of the ECB loan raised by Altek, which costs only 6.50%. This loan has a soft repayment schedule spread over 8 years. The other fixed overheads such as personnel costs, power, consumables and other overheads are expected to increase very marginally with increase in the production. In other words the fixed cost element in the cost of needles will decrease considerably.

(u) The per capita sales, capital employed on fixed assets and losses during the last three years was as under:

Year	No of employees	(Rs Lakhs)					
		Capital employed ---		Sales		Losses	
		Amount	Per employee	Amount	Per employee	amount	Per employee
1999-2000	137	15,83.04	11.55	3,38.21	2.46	1,38.76	1.01
2000-2001	161	19,65.51	14.34	6,32.11	4.61	2,22.78	1.62
2001-2002	119	21,03.05	15.35	7,51.05	5.48	77.79	0.56

(v) They expanded their capacity from 25,714 kgs to 51,428 kgs in the year 2000 and their present capacity of 51,428 kgs is based on two shifts. With an additional investment of about Rs 15 lakhs in enhancing the capacity of the existing machinery installed, the capacity will increase to 150 million or 85,714 kgs. Altek contracted with its collaborators for supply of patented machineries, (which can be supplied only by the collaborator), for its expansion programme, out of which only a part has been received and installed. The balance machineries can be received within a very short period. The capacity of Altek's plant together can be enhanced to around 250 million or 1,42,857 kgs per annum. The cost of the balance machineries under the expansion programme is estimated around Rs 150 lakhs. Altek has restructured its term loan liabilities by raising a ECB loan at a very low rate of interest, out of which the high cost 'term loan' of Indian financial institutions have been closed. The unutilised ECB loan will be sufficient to meet this balance machinery cost.

(w) Their cost of production of all the systems and sizes of needles manufactured is almost the same. The process of manufacture is almost same for all the systems, excepting that certain systems require additional operations such as double side grooving, the running of thick wire used for certain systems takes longer time than the one using thinner wire. However the cost variation is very marginal on these factors. The main difference will be due to batch size as certain costs are standard for each batch, irrespective of the system and size. The selling price however varies depending upon the system. The basic variety of needles, namely DB*1 and DP*5, considered as 'bread and butter', are manufactured by most of the players in the world. However the speciality needles, for which demand is not as big, are generally supplemented by the manufacturers. There are more than 100 varieties of such needles and it may not be possible for any company to manufacture the entire range. Again this is purely because of operational reasons owing to small quantity of demand and not because the companies do not have the facility or know-how to make such needles.

(x) Altek being the first unit in India to set up Industrial Sewing Machine Needles plant spent a lot on training its staff in India and also at Germany. As many as 25 staff have been sent to Germany for training and some of them have even been sent more than once for technology absorption and training.

(y) Altek imports certain systems of Industrial Sewing Machine Needles from its collaborator in Germany. There are more than 1500 varieties of systems and sizes of Industrial Sewing Machine Needles, depending upon the users' application and requirements. The demand for certain types of needles are very low in the domestic market. It may not be viable to manufacture such systems and sizes because of very low demand. Such systems are imported by Altek more as a customer service policy. It would be difficult for any buyer of needles to place orders on different suppliers for different systems of needles. Hence purely as a customer service, they import these needles. The sales of imported needles are normally made on almost cost to cost basis through its own distribution and marketing channel along with its domestic production. Since the imported Industrial Sewing Machine Needles are of different systems and sizes as compared to Altek's production, there is no competition between the imported needles and Altek's needles.

In addition to the above they have also stated the following:

a) The written submissions of the two exporters namely, Huating and White Crane should not be admitted on the grounds that the said two exporters had not disclosed their correct identity in their response filed by them; the exporters have concealed their real identity to mislead the DG; the exporters did not submit the answers to the questionnaires sent to them resulting they (Altek) were not in a position to comprehend the status of these two exporters who have been reported to be the major exporters of ISMN from China to India. The questionnaire, inter alia, sought specific details of (i) Volume and value of exports to India made by them during the last three financial years and (ii) names and addresses of dealers/agents in India through whom exports were made by them.

b) There are documentary evidences suggesting that Huating/White Crane invoice ISMN to India at US \$ 1 (cif) per 1000 needles. The cost of freight and packing itself is, as calculated by them is 5 paise per needle, which would suggest that the ISMN was being supplied free by the Chinese exporters. No commercial entity in the world will indulge in such practices. Therefore, there is an unholy alliance at work which is working to a diabolical plan. The objective is something other than mere commercial and can strike at the very root of Indian democracy in the name of free trade.

(c) During the anti-dumping investigations carried out a few years back, the Designated Authority recommended, after detailed investigations, anti-dumping duty of Rs 1.98 per needle which works out to 4000% at today's price. Such a high percentage is unknown in any anti-dumping investigation in any part of the world. This judgement was accepted by the Chinese needle manufacturers. More importantly, it exposes the great lie that the Chinese industry is more competitive and, therefore, able to offer prices which are not realistic. This proves that neither Chinese prices have any relationship to reality nor are they commercial in nature. The China Chamber and the Ministry of Foreign Trade, China, have shown an unusual amount of interest in this case even though ISMN forms an insignificant portion of China's total trade with India.

- (d) During the Public Hearing on 25th February 2003, the Director General pointed out that ISMN bearing the brand name "Orient" has been imported according to Indian Customs record and desired to know the name of exporter. Huating/White Crane had no answer but promised to check and revert. Some document claiming that the said 'Orient' brand of ISMN was manufactured by Huating was furnished by them and that they exported it to India to one Sanjay Trading Co. Calcutta. They feel that the commercial invoice furnished is a fake document since it does not contain even the consignor's/consignee's address.
- (e) They are the exclusive producers of ISMN and represent the domestic industry. Schmetz (India) manufactures an extremely limited range of needles and is simply a contract manufacturer for Schmetz, Germany, and exports all their needles in bulk and in unpacked condition, which is not ready for sale. TVS Needles themselves have admitted that they do not manufacture ISMN at all. Therefore, they are the only domestic manufacturer.
- (f) While challenging their import data furnished in the application which they had sourced to DGCIS Calcutta, the Chinese have studiously avoided quoting their official Chinese Government's own figures in spite of the fact that China Chamber and Ministry of Foreign Trade, China, are active participants in the proceedings. China apparently maintains trade data and the exporters have quoted selectively from them. But, the data itself is not available in public domain. By contrast India, Germany, Japan, Korea etc., publish them in book form and are available in the web site.
- (g) It was stated on behalf of the exporters that the Needle industry in India should be treated as whole for the purpose of arriving at any conclusion and not segregate ISMN. In this regard it is mentioned that the Needle industry in India consists of Household, ISMN, Knitting Machine, Hand Sewing Machine Needles and Surgical needles. It must be understood Household Sewing Machine Needles and Industrial Sewing Machine Needles are two different products. One cannot be used as a substitute for the other. Therefore, these two different needles must be treated differently in the same way all other types of needles (Hand sewing, Knitting, surgical) are treated as separate products. India follows the eight digit code for classifying needles followed internationally. The Tax Research Unit (TRU) of the Department of Revenue has issued Instructions that the harmonized system of tariff must be replaced by eight-digit international code. This practice is already being followed by importers.
- (h) It is absurd on the part of Huating/White Crane to claim that TVS has very low production base for Household needles. TVS sells more than 50 Million needles per annum and has been meeting most of India's requirement for last three decades. Therefore, TVS meets most of the demand for Household needles for three decades and Chinese imports are minimal.
- (i) The China Chamber should have produced the official statistics of the Government of China on imports and exports, classification-wise and country-wise, which China doubtless maintains like any other country. China Chamber mentions that needle is a "trivial commodity" and mutual trade between India and China should not be adversely influenced by this trivial commodity. If in fact, Government of India should not take up the case of a ISMN domestic manufacturer because it is a "trivial commodity", they would like to know as to why China Chamber and the Government of China are taking such huge interest in this case. China Chamber claims that the ISMN manufacturers are members of the Chamber. But, the China Chamber is not even aware of the number of manufacturers of ISMN in China.

(j) The responses filed by some of the importers of their oral submissions made during the public hearing reveals that they have reproduced submissions made by the exporters and the China Chamber of Commerce including certain alleged discussions which took place between Altek and the Chinese exporters and China Chamber of Commerce. The importers have also included in their written submissions which they had not orally submitted before the Director General. The said importers who were specifically asked to furnish details of their imports have not submitted any information.

(k) Their case under the Special Safeguards law may not be the last such case. The most effective way to handle this situation by China Chamber is by rising above narrow commercial considerations, educating the manufacturer's in China about international law, need to respect and observe laws of the country with whom business relationship is established. This is the most effective route to establish good personal and business relationship between the people of India and people of China.

Views of Exporters from China

The following main points have been made by them:

(a) The present investigation is both harsh and discriminatory and has been unlawfully initiated since, there have been no prior consultations between the respective Governments of India and China as envisaged in Article 16 of the said Protocol. At the time of the accession by China to the WTO there was a specific understanding on the part of all the member countries of WTO that they would exercise restraint in invoking the said Article 16 only in 'extra ordinary circumstances'. The clear understanding at the time of China's accession to WTO was that any safeguards investigation other than in 'extra ordinary circumstances' would take place in accordance with the provisions of the Agreement on Safeguards and not pursuant to the provisions of the said Article 16.

(b) The investigation is unlawfully initiated, since the required reference year is 2000-2001, during which year the Applicant has stated that there was an anti-dumping investigation on imports of ISMN by India as a result of which, as admitted in the Application the data for 2000-2001 is not representative or suitable as a reference year. Contrary to the appropriate practice in a Specific Safeguards investigation, the Safeguard duty sought is higher than the difference between the respective average prices of ISMN allegedly of Chinese origin imported by India during the Period of Investigation (POI) from 1st April 2001 to 31st March 2002 and the ISMN imports by India during the POI from other countries.

(c) There is no 'sudden surge' in imports, market disruption or causal link, as alleged, by imports of ISMN of Chinese origin particularly when all the interested parties agree that 2000-2001 is not an appropriate reference year. It was not open to the Director General (Specific Safeguards) to proceed on the basis of 2000-2001 as a reference year.

(d) The Applicant does not qualify as 'domestic industry' in view of its relationship with a German exporter and further in view of the fact that both China and India treat needles as a single industry even in terms of tariff classification and thus the needle industry may be considered as a whole and not in respect of ISMN alone for the purposes of 'domestic industry standing', 'increase in imports' and 'market disruption'.

In the absence of data on the needles industry as a whole no finding is possible on the issues of 'domestic industry standing', 'increase in imports' and 'market disruption'. There is also no reasonable basis to assume that 90% of all needles allegedly of Chinese origin are ISMN. ISMN accounts for 40% of their total needles production.

(e) Initiating an investigation on the basis of an increase in imports of ISMN originating from China is distinct from imports from China and there must be substantial evidence before the Director General to show that imports from third countries actually originate from China. The imports of ISMN from Hong Kong and Singapore have been wrongly aggregated with the imports of ISMN from China to allege an increase in imports without sufficient evidence. Further there was no export of ISMN by them to Singapore or Hong Kong during the period of investigation.

(f) There is no market disruption suffered by the domestic industry in India, as alleged. The fact of the matter is that the applicant domestic industry in India lacks economies of scale and modern process and has never enjoyed high capacity utilization as per the data furnished in the application. It is apparent that the Applicant made errors in terms of its business decisions by doubling its capacity with effect from 1st January 2000 at a relatively high cost of capital instead of improving efficiency and capacity utilization.

(g) The data furnished by the applicant shows that the domestic sales and capacity utilisation improved during the period of investigation and it was the export sales and capacity utilisation thereof that declined. Poor export performance is not market disruption in India and is not a proper cause for a specific safeguards investigation involving China. It may also be noted that other Indian manufacturers have shown profits, thus showing that there has not been any market disruption in India. Poor performance by individual domestic producers also does not amount to market disruption.

(h) The safeguard duty sought is based on Applicant's claimed survival or non-injurious price that is much higher even than the average price of imports of ISMN other than of alleged Chinese origin which is contrary to a specific safeguards investigation in which the maximum safeguard duty claimed can utmost be based on the average import price of ISMN not of Chinese origin. Exports of garments and leather products are important foreign exchange earners for India. Imports of ISMN from China enhance the competitiveness of these extra ordinary export industries of India. Further, according to the Applicant itself the total domestic consumption is about 186612 kgs of ISMN during the period of investigation. The Applicant and the other domestic producers are not even capable of meeting a fraction of the present demand even with full capacity utilization. Further, the actual users are in the best position to judge the acceptability of the quality of the ISMN from China and requirement of the same to the crucial export industries of India. Public Interest would lie in not imposing a Specific Safeguards Duty on imports of ISMN from China since the Applicant claims to account for 90% of domestic sales by domestic manufacturers of ISMN, any safeguard duty imposed would only strengthen its monopoly. Director General may consider the overall public interest before imposing any such duty. In this regard it may also be kept in mind that the customs tariff in India on ISMN is already very high.

(i) It may be noted that from the data furnished by the Applicant the highest capacity utilization ever achieved by them is 58% and is in the range from 51% to 58% between 1997 and 2002. Further, the decrease in capacity utilization to 45% is not in itself substantial and is completely irrelevant, more so when the capacity was doubled

from the year 2000 - 2001 and considering the same, the production achieved in the POI represents over 90% of the pre 2000 capacity of the Applicant. The decision by the Applicant to arbitrarily increase capacity without improving its efficiency needs to be explained and investigated. The Applicant may explain the reasons for historically low capacity utilization and the reasons to nonetheless increase capacity especially when it was unable to utilize its pre- 2000 capacity which was about 25,714 kgs as stated by the Applicant. The Applicant needs to explain whether the machinery have long maintenance schedules and long turn around time or is there a high rejection rate of the ISMN manufactured by the Applicant. It is also important for the Applicant to show the number of man-days lost due to labour unrest or other problems or force majeure situations etc. It is clear from the data furnished by the Applicant and reading the same as a whole, that during the initial period of machinery installation there are start up problems which has obviously led to low capacity utilization.

(j) Their capacity is much higher and their capacity utilization is higher at about 96% and the rejection rate is extremely low and/or minimal. The process described by the applicant is highly complex with a number of steps which goes more than 100 and obviously there would be very high rejection rate. It is not clear if the grades of ISMN imported from China are the same as the grades of ISMN made by the applicant during the period of investigation.

(k) The imports of ISMN from China during the period of investigation amounted to about 44,516 kgs. as per the DGCIS statistics. However, according to the data maintained by the Chinese Custom Authorities, the total export of all ISMN and household sewing machine needles is 35538.4 kgs during the POI. In any event the figure shown by DGCIS is also much lower than one projected by the Applicant aggregating to 104216.

(l) The true purpose of the applicant is to achieve market profiteering opportunities for its foreign collaborators through the guise of the present Investigation. Imposition of safeguards duty sought by the Applicant could only adversely impact on the Indian economy in terms of export earnings, higher costs for users, jobs and economic growth and establish the monopoly or monopolistic competition of the said Applicant in India and cannot be deemed to be in the wider Public Interest in any manner whatsoever.

(m) The information provided by the Applicant in respect of domestic production has been analysed and it was observed by them that the total production covers both, domestic as well as for exports. A simple analysis of composition of domestic/export production in total production reveals that the Applicant has always stressed more on export production.

(n) It is not clear if the grades of ISMN imported from China are the same as the grades of ISMN made by the Applicant during the POI. Chinese customs have only a single classification of sewing machine needles being 8452.3000 including both ISMN and household sewing needles.

(o) The export prices from China appear to be based on the aggregation of the imports of ISMN from China, Hong Kong and Singapore. Unless the exports from Singapore and Hong Kong are shown to be of Chinese origin the same need to be separately calculated. The CIF cost of imports of needles shows an increase of 21% by taking year 1997-98 as base. The export price has not increased much because the price of major components i.e. steel wire has remained the same. By adopting

regular cost saving measures and by keeping the rejection rates quite low by using hi-tech machines they have been able to keep cost of production under close check. The needles produced by them is of middle and low grades with middle and low speed, and is exported to developing countries and regions which is one of the main reasons why the export price have increased moderately.

(p) It is not clear on what basis the Applicant has arrived at the estimate of the share of household needles as 10% in the total import of industrial sewing needles from China. The figures furnished by the Applicant do not appear to be accurate and are denied. According to the Chinese Custom Authorities, the total exports of both the ISMN and household sewing machine needles during the POI is only 35538.4 kgs. and not the out of proportion bloated figure made out by the Applicant to suit its purpose.

(q) Specific safeguard investigation proceedings are governed by certain legal provisions and if the fundamental legal ingredients are not satisfied, the said proceedings would require to be terminated, as is the case in the present investigation. It is stated that the present investigation is discriminatory and has been unlawfully initiated without application of mind, in the absence of essential requirements for initiation, and is beyond the scope of Section 8C of the Customs Tariff Act, 1975 read with Rule 5 of the Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002 (a) Section 8C (1) of the said Act

(r) From the data provided by the applicant, there is no rapid increase of imports of Industrial Sewing Machine Needles from China to India so as to be a significant and/or principal cause of material injury to the Applicant more so when it is compared to improper, unsuitable Reference Year being 2000-2001 during which year there was anti dumping investigation on imports of ISMN by India and as a result thereof provisional duty on imports of ISMN from China was imposed.

(s) The "domestic industry" as defined under Section 8C(7)(a) means the producers (and not a single producer like the Applicant) as a whole of a like article or directly competitive article in India and needs to be understood in that sense by the Director General. All the needle manufacturers in the country have to be viewed as constituting the domestic industry. Accordingly it is necessary and required that any application complaining the increased imports of ISMN is required to be filed by the Needle Industry of India as whole and not one producer, as in the present case, and it could only be entertained by the Central Government when the domestic industry as a whole comprising of producers of needles complain about the increased rapid imports and that too after proper verification.

(t) The Supreme Court of India in **Barium Chemicals Ltd. & Anr v. Company Law Board & Ors (AIR 1967 SC 295)** has, inter alia, held that the opinion of the Central Government should be honest and before the Central Government forms its opinion, it must have before it circumstances suggesting certain inferences. The Hon'ble Court has also held that no doubt the formation of opinion is subjective but the existence of circumstances relevant to the inference as the sine qua non for action must be demonstrable. If the action is questioned on the ground that no circumstances leading to an inference of the kind contemplated under Section 8C of the Customs Tariff Act exists, the action might be exposed to interference unless the existence of the circumstances is made out and since the existence of "circumstances" is a condition fundamental to the making of an opinion, the existence of the circumstances, if questioned, has to be proved at least prima facie and that it is

not sufficient to assert that the circumstances exist and give no clue to what they are because the circumstances must be such as to lead to conclusion of certain definiteness. The existence of above circumstances must be proved before any opinion as to initiation of investigation can be arrived at. It is respectfully submitted that the right and power of the Central Government to initiate an investigation has to depend upon the existence of certain facts and circumstances and the satisfaction cannot be absolute and if the relevant parameters are not present, the investigation ought not to have been initiated and deserves to be terminated.

(u) The Applicant has attempted to explain the aggregation of imports of ISMN from Singapore to be of Chinese origin, by stating inter alia, that, Singapore has no factory manufacturing needles and that the German, Japanese and Korean manufacturers have distributor and agent in India and thus they would not export to India through Singapore and further that the exports from Germany to Singapore are very low and lastly that the price of the product from Singapore is lower than the product imported from Germany. It needs to be verified that Singapore does not have a manufacturing base. Even assuming that the same is correct, there is no justification to jump at the conclusion that what is being imported from Singapore is of Chinese origin. The presence or absence of distributor arrangements cannot be made a factor without further analysis and the same would have no relevance as any importer could import needles from Germany, Korea and Japan to Singapore and export the same to India. The price of needles from Singapore is alleged to be lower from Germany. But the same does not prove anything following the Applicant's own logic of price discounts etc., to boost sales and the same reasoning could easily be applied here in case of German, Korean and Japanese origin products imported from Singapore.

In addition to the above the **China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronics Products(CCCME)** have stated that they are a nationwide, non-profit business organization and the only kind of such business organization representing Chinese machinery and electronic Industries in the import and export field. ISMN is one of the products that members of CCCME deal with. When Article 16 of the Protocol of China's Accession into WTO Agreement, which is the basis of Section 8C of the Customs Tariff Act, 1975 was negotiated there was an understanding expressed by WTO members, including India, that it would be exercised with 'restraint' and as 'a last resort' in 'extraordinary circumstances' and when all other trade measures are exhausted. It is stated that the present investigation is unduly harsh and discriminatory since there have been no prior consultations between the respective Governments of India and China as envisaged in the said Article 16 of the said Protocol. This is particularly significant since the present investigation is the first Specific Safeguard investigation involving goods allegedly of Chinese origin.

The CCCME, Chinese exporters and the Chinese Government have all fully co-operated with the present investigation despite the fact that the initiation of the said investigation has been contrary to legal provisions of Section 8C of the said Act read with Rule 5 of the Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002 .

The Managing Director of Altek had talks with the General Managers of White Crane and Huating respectively in Chennai in December 2002 and tried to negotiate with them to pay him 2 million USD, being the price to withdraw the present safeguards investigation. It is submitted that after failing in his illegal endeavours, he requested White Crane and Huating to invest about 2 million USD in his factory which

was refused. In furtherance of his illegal, unethical efforts to monopolise the Indian ISMN market he also requested Huating and White Crane to export ISMN only to Altek and that Huating and White Crane sign an exclusive agency agreements with Altek. In addition, he also requested CCCME to sign an agreement with him to ensure that all Chinese sewing machine needle exporters and manufacturers (including not only ISMN but also household sewing machine needles) could only enter Indian market through Altek at least in the next 5 years (i.e. exclusive agency of Chinese sewing machine needles in whole Indian market). The Applicant has not approached the authorities with clean hands and has acted unethically, with malafides and with ulterior motives, thus not eligible for any safeguard duty whatsoever.

Views of importers and Users

They have, inter alia, stated the following

- (i) The application filed is full of misleading facts and figures which the applicant themselves cannot justify if called to do so. Further the inordinate and unreasonable Safeguard Duty of Rs.3628 Per Kg. sought by the applicant is without any basis. The needles from China have been of good quality and reasonably priced. On the other hand the needles from other countries are higher in price and not cost effective for small manufacturers. Altek needles are also a higher priced product and since their quality is more or less comparable to those of Chinese needles small users have to restrict their costs and show any margin of profits prefer Chinese needles. The specification of the needles imported from China are different from the needles produced by Altek or imported from third Countries.
- (ii) It has been stated by the applicant that there are 100 steps in the needle production, however even in making of advanced high quality needles, unlike those of Altek, to their knowledge only 32 steps are involved. Altek has given various statistical figures based on weight, but the trade deals with the needles on the basis of pieces or counts. Altek appears to have presented data based on weight to mislead the authorities.
- (iii) The applicant has filed the application solely for vested interest and for helping their German collaborator, Lamertz of Germany and any safeguard duty if imposed will virtually compel thousands of users of ISMN in India to purchase the Applicant's higher cost sub-standard needles or relatively higher priced needles of its connected German exporter which will amount to non remunerative financial burden on the users and huge loss of foreign exchange as users will have to purchase high cost needles from Germany, Japan and Korea.
- (iv) Whatever losses the applicant has suffered are due to its own inefficiency and it is unfortunate that instead of improving its competitiveness, the applicant has chosen to apply for the investigation and as a result has posed possible financial jeopardy for thousands of users in India.

Findings

I have gone through the case records and the submissions made by the interested parties. The issues raised by various parties are dealt with at appropriate places in the findings below to the extent necessary. However, before proceeding to discuss the merits of the case it is considered necessary to discuss a **preliminary issue** most vociferously contended by some of the parties concerning the

maintainability of the proceedings under Section 8C of the Customs Tariff Act, 1975 read with the Customs Tariff (Transitional Specific Safeguard Duty Rules) (hereinafter referred to as SSGD Rules) and the jurisdiction of the Director General (Specific Safeguards).

The Learned Senior Counsel for the exporters argued at length on the meaning of various expressions used and certain conditionalities imposed under Section 8C of the Customs Tariff Act, 1975 and contended that the investigation is contrary to the principles laid down in the said Section 8C. The Counsel also invited my attention to the Hon'ble Supreme Court decision in the case of **Barium Chemicals Ltd. & Anr Vs. Company Law Board & Ors (AIR 1967 SC 295)**. I have given a very serious consideration to this citation vis-a-vis the proceedings initiated under the Customs Tariff Act 1975. I am of the opinion that the citation is of little help since the proceedings under the Companies Act are not *pari materia* to the present proceedings under the Customs Tariff Act. What the Director General has proposed to do by issuing the Notice dated 13th August 2002 is to start the process of investigation for conducting such enquiries and not to 'apply or extend' a safeguard measure. The DG, under Rule 4 of the Customs Tariff (Transitional Product Safeguard Duty) Rules, 2002 is entrusted with making recommendation regarding imposition of a provisional or final safeguard duty. The safeguard duty, however, may be applied only by the Central Government. The Supreme Court in its verdict has held that before forming an opinion the Authority should have before it circumstances suggesting certain inferences. In the given case the Director General did not form an opinion on presumption and vague inferences but circumstances and authoritative data were available to him to form his opinion, *prima facie*, on the basis of which the notice of initiation was issued. The fundamental conditions that must exist as per the said judgement required to form an opinion was available with the Director General and hence the judgement is of no avail to the exporters. The Counsel's reliance on the Supreme Court judgement is misconceived and is not applicable to the proceeding in the instant case on facts. The onus of fulfillment of conditions precedent for initiation *prima facie* was found satisfied. The notice of initiation cannot be held to be based on surmises and conjectures.

Another related issue which has been raised and is equally important is with regard to the Protocol on the accession of the People's Republic of China to WTO (hereafter referred to as Protocol). It has been strongly contended that the present proceedings are violative of the provisions of the said Protocol. It has been argued that when Article 16 of the Protocol, which is the basis of Section 8C of the Customs Tariff Act, 1975, was negotiated there was an understanding expressed by WTO members, including India, that it would be exercised with 'restraint' and as 'a last resort' in 'extraordinary circumstances' and when all other trade measures are exhausted. It has been stated that the present investigation is unduly harsh and discriminatory since there have been no prior consultations between the respective Governments of India and China as envisaged in the said Article 16 of the said Protocol.

I have carefully gone through the said Protocol and it is observed on a plain reading that the Protocol does not envisage any prior consultations and speaks of offering consultations only when the affected WTO Member takes a provisional safeguard measure pursuant to a preliminary determination that imports have caused or threatened to cause market disruption. The measure needs to be notified to the Committee on safeguards and a request for bilateral consultations shall be effected (emphasised) immediately thereafter. Moreover there is nothing in

the Indian domestic legislation, which are WTO compliant, statutorily prescribing any such prior consultations. However, it has been informed by the Ministry of Commerce, Government of India that when requested by China, India readily agreed for consultations and an officer was specially deputed from Delhi for the consultations held in Geneva on 22nd October 2002. It was clarified to the Chinese authorities, inter alia, that the safeguard investigation is a quasi judicial process and cannot be stalled midway and that it would be very useful if inputs were provided by the Chinese side to facilitate completion of the legal process.

In view of the above, it is observed that the requirements of the statutory provisions envisaged under the Customs Tariff Act and the SSGD Rules have been fully met and the notice of Initiation has been correctly issued.

Product under Investigation

The product under investigation is ISMN classified under the erstwhile sub-heading 8452.30 of the First Schedule to the Customs Tariff Act 1975 and under 84523000 of the Indian Trade Classification (ITC) based on the Harmonised Commodity Description and Coding system. With the amendment of the First Schedule to the Customs Tariff Act 1975 by the Customs Tariff (Amendment) Ordinance, 2003 (1 of 2003) relating to eight digit Customs classification, which came into effect from 1st February 2003, ISMN is now classifiable under 84523090. However, the classification is indicated for the purpose of convenience and in no way be construed as restricting the scope of coverage of the product under investigation.

Domestic Industry

The application has been filed by Altek on behalf of the domestic producers of ISMN for imposition of safeguard duty on imports of ISMN. Though there are three other companies reportedly producing ISMN, Altek accounts for the major production and sale of ISMN. It has been contended by the exporters, importers and users besides the CCCME that Altek does not represent the domestic industry. An important issue regarding what constitutes the domestic industry under the Customs Tariff Act has been raised and argued at length. It has been stated that the Applicant does not qualify as 'domestic industry' in view of its relationship with a German exporter and further in view of the fact that both China and India treat needles as a single industry even in terms of tariff classification and thus the needle industry may be considered as a whole and not in respect of ISMN alone for the purpose. Further it was claimed that in the absence of data on the needle industry as a whole no finding is possible by the Director General on this issue. This contention appears to be not correct as under Section 8 C of the Customs Tariff Act 1975 the proceedings are with reference to the article/ product and not tariff centric. While interpreting the entries in the tariff Schedule, they must be construed and understood as in common parlance and words used by the legislature must be given their popular sense of which the people conversant with the subject matter with which the statute was dealing would attribute it. Liberal interpretation is to be imparted to the language and not confined to its grammatical meaning. The provisions of Section 8 C and the SSGD rules made thereunder has to be read in its entirety and construed as a whole to give true import and meaning not to make it purposeless and nugatory. But a construction which results in inequitable result and incongruous is to be avoided. The construction unlike a penal provision has to be tested on a different touchstone. As regards the relationship with the German collaborator; I see no restriction under the safeguard

rules, unlike in the case of anti-dumping investigation, to exclude the applicant from the ambit of domestic industry.

Further questionnaire were sent to known domestic producers of ISMN. Response was received from TVS Needles and Schmetz India. It was observed that TVS Needles Ltd. has been manufacturing domestic needles since 1962. The company in its reply had informed that they are manufacturing primarily household needles (HHN) and only a very insignificant quantity of ISMN. It has been observed the company has an installed capacity of 75 million needles including ISMN. During the year 2001-02 they produced a quantity of 42.73 million needles out of which they manufactured only a very insignificant quantity of ISMN. The company was requested to furnish quantities manufactured of ISMN during the last three years. The details have not been made available. It was gathered that the company on its own does not market ISMN and whatever is produced is based on the requirements of M/s. Singer India Ltd. to whom the entire quantity of ISMN is transferred. M/s. Singer India Ltd. was one of the major equity holders in TVS Sewing Needles Ltd till about 2001 and continues to be the major distributor of the products manufactured by TVS. While Schmetz (I) Pvt Limited, Mumbai did not respond as a domestic manufacturer but as an importer of needles; Groz-Beckert Asia Limited, Chandigarh did not respond at all and did not participate in the investigation. Therefore, the application by Atek in the light of what has been stated above and in view of the fact they account for the major proportion of ISMN manufactured in India, is considered to have been made on behalf of domestic industry.

Increased Imports

ISMN is imported into India mainly from the Peoples Republic of China, Germany, Japan, Korea (RP), Singapore and Taiwan (Chinese Taipei). The imports of ISMN in general from all countries put together increased from 116470 kgs. in 1997-98 to 174961 kgs in 2001-02. The Basic Customs Duty on imports of ISMN which was 40% in 1998-99 was brought down to 35% in 1999-2000 and since 2000-01 attracts a duty of 25% which is in force.

Doubts have been expressed by exporters and CCCME about the authenticity of import data in respect of ISMN from China provided by the applicants, particularly in respect of imports for the period 2001-02. It has been stated that the Applicant wrongly aggregated imports from Singapore & Hongkong to be originating from China. Only such imports of ISMN from Singapore or Hong Kong that are clearly proven to be of Chinese origin, may be aggregated with the imports of ISMN from China. It has also been averred that while the imports of ISMN from China during the 2001-02 amounted to about 44,516 kgs. as per the DGCIS statistics but as per the data maintained by the Chinese Custom Authorities the total export of needles including ISMN and household was 35538.4 kgs during the said period. Even the DGCIS figure was also much lower than one projected by the Applicant aggregating to 104216 Kgs.

The Applicant in this regard has stated that the data for the years 1997-98 to 2001-02 has been furnished by them from port wise import data made available by the DGCIS, Calcutta. Suitable adjustments in the figures for imports of Household needles, have been made by them based on market intelligence sources.

In this connection, the Port-wise details furnished by the applicant relating to imports of ISMN during the period 2001-02 was got verified through Commissionerate

of Customs, Chennai and ICD Tughlakabad. While report received from ICD Tughlakabad revealed that there were no imports of ISMN either from China or from Singapore during 2001-02, it has been verified and reported by the Chennai Customs that a quantity of 85355 Kgs of ISMN has been imported into India from China and there has been no imports from Singapore during the year 2001-02 at Chennai Port. It has been observed that Huating accounted for a quantity of 62940 Kgs valued at Rs.9737763/-; White Crane accounted for a quantity of 20735 Kgs. valued at Rs. 1878124/- and China Light accounted for a quantity of 1680 Kgs valued at Rs.667408/- of the total imports made at Chennai, as would be evident from the table below:

Exports by Nantong Huating				
B/E	Date	Importer	Value(Rs) c.i.f.	Weight (Kgs)
331850	21-Jun-01	Krishna Ribbons, Delhi	548228	2990
335039	7-Jul-01	Metro Impex, Delhi	747658	4082
340257	30-Jul-01	Krishna Ribbons, Chennai	1009576	5512
342921	9th Aug 01	Krishna Ribbons, Delhi	746047	4056
344774	21-Aug-01	K K Impex, Delhi	559535	3042
348542	5th Sep 01	K K Impex, Delhi	726917	3952
355196	9.10.01	Madras Int. Inc. Pondy	1862556	16900
358931	29-Oct-01	Delhi Trading House, Delhi	867439	4646
367310	19-Dec-01	Metro Impex, Delhi	965903	5148
381102	26-Feb-02	Delhi Trading, Delhi	1124069	7012
382606	7-Mar-02	Metro Impex, Delhi	459835	5600
Exports by Nantong White Crane				
380866	25.02.02	Vijayalakshmi Ent.Delhi	589032	6720
382596	07.3.02	Delhi Trading, Delhi	1289092	14015
Exports by China Light				
329660	11.6.01	Jai Ent. Chennai	667408	1680

The above data has been compiled based on Bills of Entries and the country of Origin as available in the Customs record. The DGCIS have clarified that country wise imports reflected in their publication, by and large, denotes imports credited to the country of Consignment. It was observed that the details of exports claimed by the two Chinese exporters in their response and CCCME of 35538.4 Kgs including Household needles was prima facie wrong and appears to be not credible. They did not file any documentary evidence certified by the Chinese Customs. In spite of being asked during the hearing, details of their export were not furnished though they all claim to have co-operated with the investigations. The information furnished by the two exporters in particular, in a confidential manner, was also found very sketchy and appears to be deliberately suppressed for reasons only known to them.

The details of exports which have been strongly relied upon by the opposing interested parties as against what has been furnished by the applicants and duly verified by this Directorate General was found to be an error on face of the record. A mere perusal of the Indian Customs record of ISMN imports, made at Chennai Port Bill of Entry-wise, party wise without reference to any other matter revealed that the Chinese exporters, importers and the CCCME have not furnished the factual details of their exports/imports which are very material for an in depth examination for arriving at a decision. The importers have alleged contradictory things without substantiating and

merely adopted the replies filed by the exporters and CCCME. In fact, I observe that they had made written submissions of even what they had not stated during the hearing. The importers failed to furnish any of the relevant details of their imports including details of Bill of Entry & invoices relating thereto, despite the fact they were specifically asked to do so. They were always claiming to have extended their fullest cooperation but on the ground their cooperation have been found to be without substance.

Information available in public domain reveals that the Government of Peoples Republic of China has claimed territorial rights and resumed sovereignty over Hongkong since 1st July 1997. The Government of PR China also decided and established Hongkong as a **special administrative region** in accordance with provisions of its Constitution under the principle of "one Country, two systems". Therefore, I do not see anything wrong adding the imports from Hongkong to be the imports originating from China. However, keeping in view the verifications carried out that no imports from Singapore have been noticed at Chennai and Tughlakabad which as per port wise data accounted for a major quantity during 2001-02, the imports from Singapore has not been taken into account in the present proceedings.

Another point which has been raised by the opposing interested parties is with regard to adjustment in the import figures for Household needles by the applicant to the extent of 10%. The opposing parties have claimed that the total exports from China of 35538.4 Kgs is inclusive of about 40% Household needles. In this connection it has been observed from the balance sheets that TVS Sewing Needles the sole producer of HHN in the country have lost their market from 59.53 Millions in 1999-2000 to 47.50 Millions in 2000-01 and further to 42.19 Millions in 2001-02 indicating a loss of market share of about 10% which appears to have been gained by the Chinese. The Chinese exporters and importers in India who were asked to furnish specific details with regard their exports/imports have preferred to keep silent. In the absence of the details sought it would not be fair not to admit what has been furnished by the Applicant.

In view of the above, it is observed that the data provided by the Applicant for the period from 1997-98 to 2000-01 sourced to DGCIS is authentic. However, the imports for the period 2001-02 which was furnished on annualised basis has now been corrected on the basis of port wise data and on the basis of verification carried out from Customs. I hold in the absence of anything contra furnished by the exporters/importers/CCCME, the imports from Hongkong has been included to be of Chinese origin. As regards the imports from Singapore the entire quantity has been excluded to be originating from China in the present investigation. The import of ISMN originating from China during the year 2001-02 as 99609 Kgs valued at Rs.21960090/- is hereby confirmed on verification.

Threat of Market disruption

The exporters and CCCME have raised a point that the reference year for the purpose of investigation should not be restricted to 2000-01 but should cover a longer period for the purpose of present investigation. In this regard it is observed that the increase in imports is to be considered over a period which under the Trade Notice No. SG/TN/1/97 dated 26th September, 1997 issued by the Director General has been specified to be a period of the most recent 3 years (or longer) immediately preceding the commencement of investigation for which data is available. In the current investigation, therefore, the period of investigation has been taken as 1997-98 to 2001-02 for which data was made available by the applicants. Whether or not there were imports in any of these years is irrelevant specially as the evaluation of imports is to be done on a comparative basis for the entire period. If there were no imports or

only a small quantum of imports in a year, that year cannot be ignored only on that ground. The increase in imports for the entire period in totality has to be considered for arriving at a decision whether imports have increased during the period.

The imports and domestic production of ISMN during 1997-98 to 2001-02 have been as under:

(Figures : Qty. in Kgs./Value in Rs. lakhs)

Year	Domestic Production	Imports						Imports from China as % of Domestic Production
		China		Others		Total		
		Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value	
1997-98	1544	53545	238.64	62925	543.95	116470	782.59	3468%
1998-99	3683	85818	436.09	58912	746.65	144730	1182.74	2330%
1999-00	4755	79403	533.15	88830	911.38	168233	1444.53	1670%
2000-01	4353	29270	190.06	65602	884.95	94872	1075.01	672%
2001-02	5351	99609	219.60	75352	1377.22	174961	1596.82	1860%

ISMN was being imported into India for quite sometime. However, during the period under investigation the imports originating from China have increased from 53545 Kgs in 1997-98 to 99609 Kgs in 2001-02. The average imports of ISMN originating from China during the four year period 1997-98 to 2000-01 was observed to be 62,000 Kgs which increased to 99609 Kgs. in 2001-02 registering an increase by about 60%. The imports as a percentage compared to the average domestic production of 3584 Kgs. during the period 1997-98 to 2001-02 which stood at 1730% increased to 1860% in 2001-02. The imports, thus, have increased both in absolute terms as well as compared to domestic production during the period under investigation.

The increased imports of ISMN have caused /threatened to cause market disruption to the domestic producers of ISMN as indicated by the following factors:

(a) It has been stated by certain interested parties that the Chinese international market price for ISMN during 2001-02 was about US \$15 per thousand pieces; however, no evidence has been furnished to this Directorate General to corroborate the same. The CIF price of ISMN which was Rs.446/- per kg. in 1997-98 increased to Rs.671/- per kg. in 1999-2000 and declined to Rs.649/- per kg. in 2000-01 and thereafter further declined to Rs.220/- per kg i.e. drop by 66%, whereas the prices of ISMN originating from other countries have shown an upward trend from Rs. 1,210 per kg in 97-98 to Rs 2,425 per kg in 2001-02. To keep up with the decline in prices of ISMN originating from China and to retain their market share, the domestic producer had to reduce their prices of ISMN, as a sequel, their realisation has declined considerably and resulted in loss to the domestic producer. The realisation which was Rs.7140/- per kg. in the 1998-99 declined to Rs.5096/- per kg. in 1999-2000 and improved marginally to Rs.5128/- per kg. in 2000-01, thereafter, fell appreciably to Rs.3817/- per kg in 2001-02.

(b) The capacity utilisation of domestic producer which was 57% in 1998-99 declined to 51% in 1999-2000, increased to 58% in 2000-01 and registered a decline of 13% in 2001-02 which is at 45%. Their closing stocks which was 4057 Kgs at the end of March 2000 increased to 5552 Kgs. at the end of March 2002.

(c) While the market share of domestic producer of ISMN, considering the imports emanating from all countries, improved from 1.14% in 1997-98 to about 3% in 2000-01 in the total domestic consumption of ISMN, fell marginally to 2.61 % in 2001-02, but the injury suffered by the domestic producer by way of loss of market share was around 5% considering the imports emanating from the Peoples' Republic of China during the said period as would be indicated in the table below. The domestic producers have been able to retain even this reduced market share only at the cost of reduction of their sales price.

(In Kgs.)

Year	Domestic sales	Total Domestic consumption (imports from the Peoples Republic of China and domestic sales)	Share of domestic Sales to domestic consumption (2/3x100%)	Total Domestic consumption (imports from all countries and domestic sales)	Share of domestic Sales to domestic consumption (5/6x100%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1997-98	1348	54893	2.45%	117818	1.14%
1998-99	1621	87439	1.85%	146351	1.11%
1999-00	3549	82952	4.28%	171782	2.07%
2000-01	2836	32106	8.83%	97708	2.90%
2001-02	4703	104312	4.50%	179664	2.61%

The domestic industry has suffered market disruption/serious injury as observed above. However, the crucial question is whether this sufferance of the domestic industry is on account of increased imports or is it a self inflicted injury on the domestic industry as argued by some interested parties.

It has been argued by the exporters from China that if there has been a capacity creation, in fact, doubling the capacity by the applicant, then it cannot be said that there is causal link between imports and injury/market disruption. In the present investigation it is being examined whether the domestic producers have faced a threat of serious injury/market disruption as evident on comparison of their performance in 2001-02 with that of earlier period. The case of the domestic producers is that they have faced a severe set-back in performance in 2001-02 as compared to earlier years. The Chinese exporters have stated that manufacturers of ISMN other than Altek has been making profits and they desired that this may be examined by the Director General. An attempt was made to analyse the position of TVS. It was observed that TVS Needles has been making profits but its income from manufacturing operations has been decreasing. The income from operations which was Rs.41.81 lakhs in 1999-2000 declined to Rs.23.12 lakhs, further declining to Rs 15.11 lakhs in 2001-02. The major income for TVS Needles is from 'other income' out of their investments of Rs.302 lakhs as on 31.03.02. Their 'other income', which was 24.04 lakhs in 1999-2000, increased to Rs.26.81 lakhs in 2000-01, which further increased to Rs.29.75 lakhs in 2001-02 which basically accounts for their profits. A similar analysis could not be carried out in respect of other producers since they did not respond to the notice of initiation and the questionnaire sent to them.

It has also been argued that if the production and sales have either remained constant or gone up, no causal link can be claimed with imports. This is not in accordance with the provisions of the law which requires determination of injury/market disruption to be made on an objective evaluation of various factors and not just upon production and sales. In fact, in determination of causal link between imports and injury/market disruption, the Annex to the Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules 2002 requires the Director General to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of that article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, capacity utilization, profit & losses etc. If, therefore, the increased imports enter in such condition that despite higher domestic production and sales, the imports occupy a higher market share and displace the domestic production, the injury so caused is undoubtedly attributable to increased imports.

It is important to analyse this issue in its right perspective as it lies in the heart of the determination whether the injury caused to domestic industry is on account of increased imports or on account of other factors. I am afraid this argument is totally fallacious. Firstly, the law does not require that for a determination of increased imports or serious injury or market disruption the domestic production must fall. A finding of increased imports is to be arrived at after considering the imports in absolute terms as well as compared to the domestic production. In case the domestic production was increasing but if the imports were increasing still faster, a finding of increased imports can well be made as the imports increased both absolutely as well as compared to domestic production. Safeguard protection will be available to the domestic industry in such a situation if it could be demonstrated that the domestic industry suffered serious injury/market disruption or a threat thereof caused by the increased imports. In other words, a finding of serious injury/market disruption does not necessarily require domestic production to fall.

The serious injury to the domestic industry which started taking place in 1997-98 manifested itself more prominently in the year 2001-02. In this period the domestic sales of the domestic producer did register a marginal increase but only at the cost of unprofitable sale at reduced prices. As the domestic producers kept on losing production and sale it had its impact on fixed cost, thereby increasing the cost of production and reducing the profits. The increase in imports which have been entering the Indian markets at declining prices from China have threatened the domestic producers of serious market disruption specially as they have adequate capacity to cater to Indian demand of ISMN substantially. The imports have entered in such condition that despite a marginal higher domestic production and sale, the imports occupied a higher market share and have displaced the domestic production, obviously the injury so caused is undoubtedly attributed to the increased imports originating from China. In the present case, however, Altek did achieve a small growth in sales and production but far below the growth of apparent domestic consumption. Even this increased production and sales was achieved by Altek at the cost of reduction in their realisations. It has been observed that Altek suffered huge financial loss and is now a potential sick company under the BIFR Act. Altek suffered a loss of Rs138.76 Lakhs during 1999-2000 which increased to Rs222.78 Lakhs in 2000-01 but registered a decline to Rs77.79 Lakhs as on 31st March 2002 primarily due to their restructuring of borrowings from domestic financial institutions with low cost External Commercial Borrowing (ECB) attracting a lower rate of interest..

Quality

Altek is manufacturing ISMN of international standards and parameters. They have a very rigid quality control system built in its production line. Each and every batch of ISMN manufactured is inspected on a random basis at every stage of operation and the finished product is visually inspected 100%. The production is accounted batch wise and every batch carries its production/rejection details which is recorded at every stage/operation in Needles Process Card. The final production data is transferred to inventory records. Altek with its strict quality parameters has been accredited with ISO 9002 certification besides they have been awarded with SATRA certification from UK for meeting quality parameters. It was gathered that Altek is the only ISMN manufacturer to get this accreditation in the world. The needles are despatched to the customers only after strict quality standards are met.

Some of the interested parties have claimed that the needles imported from China are different in quality vis-à-vis the one manufactured by Altek although one of the interested parties (user) had stated that if needles manufactured by Altek were competitively priced they would prefer their needles. In this regard, it is observed that both the imported ISMN, including that produced and exported by China and the domestic ISMN compete with each other in the same market and have the same usage characteristics. A mere difference in quality does not ipso-facto take away a product out of the scope of 'like or directly competitive products'.

Expansion of Capacity

It has been argued by some parties that expansion of capacity by the applicant was not a wise decision and that the injury to them is self-inflicted. In this regard, it is observed that the circumstances under which Altek expanded their capacity needs to be seen. The Applicant has stated that Capacity of their unit at the time of commencement of commercial production was 25,714 kgs or 45 million needles per annum which was increased to 51,429 kgs or 90 million per annum on two shift basis. The expansion was considered since the additional capacity could be created with a very nominal addition to the fixed assets. The cost of expansion including building was only Rs. 452 lakhs while the initial cost of setting up the plant was Rs 1585 lakhs. Thus expansion of more than 100% could be achieved with this additional capital expenditure. The increase in the capacity would bring down the cost of fixed overheads for every kg of production and an ISMN manufacturer must keep an increasing range of system/sizes to survive and to cater to the growing Indian market. It was observed that domestic industry has increased its range of ISMN systems/sizes from 331 during the year 1999 to 357 in 2000; 450 in 2001 and 631 in 2002. In view of these developments, it can not be held that Altek did not take a wise decision in expanding their capacity or that the injury to them is self-inflicted.

Pricing

An argument has been raised that price is not a relevant factor for consideration in the Safeguard investigation. In this regard it is observed that unlike in the case of anti-dumping investigation where the price discriminatory practices adopted by the exporters is the root cause for an anti-dumping action, in the case of Safeguard investigation increased imports is the fundamental requirement for maintaining a safeguard action. At what prices the imports are entering is not the relevant factor because it is not the unfair competition which is the subject matter of

safeguard action but it is the competition per se offered by the increased imports to the domestic producers, even if it is at fair prices. Only in this context the import prices are not relevant. However, when it comes to determination of market disruption/serious injury or threat thereof, the law requires an examination of change in level of sales, profitability etc. of the domestic producers. These factors undoubtedly depend upon the prices of competing products and in that context import prices do become relevant and require an examination, specially to assess their effect on the domestic situation.

It has been observed from the details made available by Chennai Customs that during 2001-02, a quantity of 1680 Kgs was imported from China at the rate of Rs.397/Kg; a quantity of 40440 at the rate of around Rs.184/Kg; a quantity of 16900 Kgs at the rate of Rs.110/Kg and a quantity of 26335 Kgs at the rate of around Rs.88/Kg. This in itself will lead one to observe that there has been a substantial depression in prices (cif) of imports of ISMN from China, the decline being from Rs.397/Kg to Rs.88/Kg that is a decline by about 78% during the year 2001-02. This led to reduction in prices by the domestic producer. It may be mentioned that depression in national prices is an important indicator of the market disruption and as a sequel thereof the injury suffered by the domestic producer. While it may be possible for the domestic producer to achieve better efficiencies in production and utilization of capacity, the most crucial and important aspect is the price which they are able to realise or fetch for their product. Invariably, the depressed prices results in loss of market share for the domestic producers and affect their profitability.

In conclusion, it is observed that the imports have grown phenomenally during the period under investigation. These increased imports have progressively taken a significant share in the apparent consumption which increased from 54893 in 1997-98 to 104312 in 2001-02. The serious injury /market disruption to the domestic industry is a consequence of these increased imports. Factors other than increased imports do not appear to have any significant effect on the state of the industry in so far as the present investigation is concerned.

Inefficiency of domestic producers

An issue has been raised that the domestic producers of ISMN are not operating efficiently and that their number of operations for production is much higher as compared to overseas manufacturers and in particular the Chinese manufacturers. The Chinese exporters have stated in their written response that as against the claim of Altek that there are about 100 steps in manufacturing ISMN they have only 16 stages(though they mentioned that there were 27 stages during the hearing). This, was verified and it was gathered that the production plan in manufacture of ISMN which is a product of precision engineering involves as many as 100 operations including intermediate operations like arranging, cleaning, degreasing, de-oiling etc. to make the ISMN ready for the next stage of processing which practice is followed by all manufacturers internationally. However, it was verified that there are only 15 major operations that was being carried out for manufacture of ISMN by Altek namely swaging, cutting & rounding, branding & straightening, die pressing, milling, fin grinding, pointing & egalising, heat treatment, chemical deburing & polishing, plating, visual inspection and final packing of needles.

Re-structuring Plan

It has been stated by the opposing parties that the adjustment plan of the applicant cannot be relied upon. It has been argued by them that the domestic producers have not procured their raw materials particularly the steel wire for manufacture of ISMN competitively from indigenous sources and have preferred imported steel wire which was far more expensive vis-à-vis the indigenous one and is therefore one of the causes of injury to them. Though the rules do not envisage any re-structuring plan to be submitted by the domestic industry, the adjustment plan submitted by the applicant is not hypothetical or academic. Their restructuring plans furnished in an attempt to reduce their cost of production was examined in detail by this Directorate General. They are making sincere efforts to become competitive so as to face competition offered by the imports from China in particular. It is considered that imposition of Safeguard duty would help them in re-structuring and to become competitive. It is also observed that the domestic producers have already taken steps in this direction and the domestic industry would need a period of about three years, although they have claimed a period of four years to substantially complete their plans.

Injury due to increased imports

A number of issues have been raised by various parties justifying the increased imports or to show that the injury caused to the domestic industry was not on account of increased imports but on account of other factors. The most important amongst these issues is the supply-demand gap. Some of the parties have claimed that the cause of injury to the domestic industry was not increased imports as the imports were necessitated to meet the gap between domestic supply and domestic demand. This aspect has been examined and it has been observed that Altek went into commercial production in the year 1997 with an installed capacity of 45 million needles per annum at a total investment in the plant & machinery of Rs.1223.85 lakhs. Altek expanded their capacity from 45 millions to 90 million in the year 2000. The total cost of the expansion was around Rs.352.26 which is only 28% of the original cost plant and machinery, whereas the capacity has been increased by 100%. The expansion was undertaken primarily to reduce the cost of production of ISMN over a period of years. It was gathered from the management that the expansion was part of their financial restructuring plan. The company had borrowed term liabilities and working capital from Indian financial Institutions/Banks on which the interest rate was as high as 18% which was substituted with low cost External Commercial Borrowing (ECB) attracting interest rate of only 7.5%. It was verified that they have sufficient infrastructure, installed certain critical machineries besides have also contracted with their collaborators for supply of patented machineries with adequate capacity ratings and they have the potential to enhance and manufacture a quantity of approximately 2,00,000 Kgs per annum of ISMN of various specifications and systems. Moreover, the Applicant has not opposed the imports of ISMN into the country. What he has sought is only a level playing field for a period of four years to become competitive vis-à-vis imports originating from China.

Injury due to loss of Exports

It has also been claimed by the opposing parties that the reason for the woes of the domestic producer is loss of its export market that has declined to 17988 Kgs in 2001-02 as compared to 25363 Kgs in 2000-01 and not the imports of ISMN particularly originating from China. In this regard it is important to keep in mind that the production line for production of ISMN is common both for the domestic consumption and for the export market. A domestic industry that was not able to compete in the

domestic market could hardly have been expected to compete in the international market, specially when the domestic supplies were the major potential market for the domestic industry and export was a secondary market. Even on the export front the Applicant had to compete with other ISMN producers in India who were exclusively catering to exports enjoying the various incentives under the EOU Scheme. The Applicant has explained the reasons for venturing into the export market and has stated that it was to keep the production process going in the light of dedicated investments made in the plant and to improve their capacity utilisation to bring down the cost of production.

Allegations of Bribe

It has been observed that the China Chamber of Commerce have come up with serious allegations against the applicant for alleged demands of heavy sums in consideration for withdrawal of their request for safeguard action against the imports of ISMN originating from China. It would be pertinent to mention that the said allegations were neither raised during the hearing nor in their written submissions but in the rebuttals filed for the first time to which the applicant had no chance to respond. The meeting with the Chinese Chamber at the Applicant's place was not at the instance of this Directorate General and private negotiations between the two parties has no relevance to the present proceedings.

Provisional Safeguard Duty

In view of the fact that after completing the investigation final findings are being issued in this case, it is not considered necessary to record any preliminary finding for the purposes of imposition of provisional safeguard duty.

Public Interest

It has been argued that the applicant has only a market share of 2-3% of the total consumption of the ISMN in India and imposition of safeguard duty on ISMN originating from China would not be in public interest. This claim has been made on the basis that imposition of safeguard duty would make the imported ISMN costlier in the hands of importers/users which may result in the increased cost of resultant products. It has been claimed that imposition of Safeguard duty on ISMN would make it costlier and this would be against consumer interest. It has been argued that the applicant has sought safeguard duty protection to benefit their German collaborator. It has been verified that the management of Altek is exclusively controlled by Indian promoters and none from Germany hold any executive position in Altek. Besides, there is no substantive evidence placed before me by the opposing parties and I see no merits in the contention raised.

It has been argued that the Applicant would profiteer and exploit the domestic market in the event of imposition of safeguard duty leading to a monopolistic situation. In the light of unrestricted imports and more so when imports from China accounted for a major share of the apparent domestic consumption during the period 1997-98 to 2001-02 this presumption appears to be not correct. The law also does not envisage that interest of a single producer should not be protected even if it rightly deserves to be protected. Imposition of safeguard duty is not aimed at encouraging monopolistic practices but at protecting the interests of domestic producers, if increased imports cause or threaten to cause market disruption to them so as to allow them time to meet the competition offered by the increased imports.

In this regard it is also observed that the scope of the term Public Interest is not to be restricted to cover consumer interest alone. It is a much wider term which covers in its ambit the general social welfare taking into account the larger community interest. While the imposition of safeguard duty may result in increased cost of imported ISMN in the hands of buyers and therefore, it may also effect the end products manufactured therefrom, it is important to keep in mind the objective of imposition of safeguard duty. The purpose of imposition is to provide time to the domestic industry within which it may make positive adjustments to meet with the new situation of competition offered by the increased imports. The imposition of safeguard duty would not only allow a wider choice to the buyers to source their requirements, but also at competitive price. The domestic producers provide employment to a large number of people and make valuable contribution to the economy. Safeguard duty would thus enable them to survive in the face of competition offered by the imports which should also be in the long term interest of the buyers of ISMN as well as of the consumers of products manufactured therefrom. In this regard, it is observed that the imposition of safeguard duty is not likely to have any significant effect on the user industry and the consumers thereof especially as the safeguard duty is proposed to be imposed only to the extent necessary to protect the domestic producers of ISMN. It is, therefore, considered that imposition of Safeguard Duty on ISMN originating from China would be in general public interest.

Conclusion

In view of the findings above, it is concluded that the increased imports of ISMN originating from PR China into India have caused market disruption to the domestic producers causing material injury to them and imposition of Safeguard duty for a period of **three years** will be in the Public interest.

The opposing interested parties have also averred that the safeguard duty sought by the Applicant is based on its claimed survival or non-injurious price that is much higher even than the average price of imports of ISMN other than of alleged Chinese origin which is contrary to a specific safeguards investigation. The maximum safeguard duty claimed can utmost be based on the average import price of ISMN not of Chinese origin. This has been considered and only that amount of safeguard duty which, if levied, would be adequate to prevent or remedy market disruption is being recommended.

While arriving at the quantum of safeguard duty which will be adequate to protect domestic industry, the cost of production (**confidential**) of ISMN produced domestically has been taken on the basis of their optimum capacity utilisation and cost reduction efforts. Although a higher profit margin of profit had been claimed by the applicant a reasonable margin has been allowed. Similarly, the CIF import prices of ISMN originating from China have also been taken on weighted average basis during the period 1997-98 to 2001-02. Adjustments have been made for duties, taxes and handling charges as applicable both for domestically produced and for the imported ISMN. No adjustment has, however, been made for the sales tax or other local taxes

paid on the domestically produced ISMN in view of provision of levying 4% Special Additional Duty on imports which takes into account sales tax and other local taxes etc. generally levied on domestically produced goods. The safeguard duty has been worked out per kg of ISMN converted and quantified per needle on the basis of certain verifications carried out by the officers of this Directorate General and from Customs.

Recommendations

It is recommended that a specific safeguard duty @ Rs1.50P(Rupee one and paise fifty only) per needle be imposed on Imports of ISMN originating from China into India for a period of 3 years being the minimum necessary for the protection of the domestic industry from the threat of market disruption caused by the said Imports of ISMN into India.

[F. No. SSG/INV/1/2002]

B. K. MISHRA, Director General